{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
शनिवार 23 मई 2026
ज्येष्ठ शुक्ल 06 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 238
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

संसेक्स - 75,415.35
निफ्टी - 23,719.30
सोना - 1,59,490
चांदी - 2,85,000
डॉलर - 95.59

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कर रही है पेट्रोल-डीजल सस्ता करने की तैयारी

पेट्रोल-डीजल पर वेट घटाएंगे राज्य

तेलंगाना में सबसे ज्यादा लगता है टैक्स, 10 तक एक्साइज ड्यूटी घटा चुका केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पेट्रोल-डीजल सस्ता करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (वेट) कम करने की अपील कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा शासित 22 राज्यों में वैट में कटौती की पूरी संभावना है। डीजल की कीमतों को नियंत्रित करना प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर परिवहन, खेती और उद्योग जगत पर पड़ता है।

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही हैं। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड करीब 1.9 प्रतिशत बढ़कर 104.52 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। हालांकि, इसके बाद पेट्रोल-डीजल की कीमत में 3.90 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।

डीजल पर फोकस, क्योंकि इसका सीधा असर महंगाई पर

अधिकारियों के मुताबिक, भाजपा शासित राज्य सबसे पहले डीजल पर टैक्स कम करने पर विचार कर सकते हैं। भारत में हर साल करीब 9.47 करोड़ टन डीजल की खपत होती है, जो किसी भी अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से कहीं ज्यादा है। पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादातर निजी वाहनों के लिए होता है, लेकिन डीजल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, खेती और इंडस्ट्री में होता है। अगर डीजल सस्ता होता है तो माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे रोजमर्रा की चीजों के दाम गिरेंगे। अप्रैल में थोक महंगाई दर 42 महीने के उच्च स्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

सचिवों के समूह ने की ईरान युद्ध के असर पर चर्चा

ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर पडने वाले असर को लेकर हाल ही में सचिवों के एक अधिकार प्राप्त ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा की गई कि महंगे कच्चे तेल के बोझ को कम करने के लिए वैट में कटौती जरूरी है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 प्रति लीटर घटाकर शून्य कर दी थी, जबकि पेट्रोल पर 3 की कटौती की गई थी। अब केंद्र चाहता है कि राज्य भी अपनी ओर से टैक्स कम करें।

क्रीमी लेयर और आरक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

माता-पिता आईएएस हैं तो आरक्षण क्यों?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता शशांक रतनू ने कहा कि लोगों को उनकी सैलरी की वजह से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक दर्जे के आधार पर बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप-ए कर्मचारियों को बाहर किया गया है और ग्रुप-बी कर्मचारियों को भी बाहर किया जाता है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। ऐसे में अगर अगली पीढ़ी भी आरक्षण मांगती रहेगी तो समाज कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि छात्रों के माता-पिता अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर भी आरक्षण चाहते हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें अब आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए।

संतुलन बनाए रखना जरूरी

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस मुद्दे में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अपनी जगह है, लेकिन जब माता-पिता आरक्षण का लाभ लेकर एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं और दोनों आईएएस अधिकारी या सरकारी सेवा में अच्छी स्थिति में हैं, तो सामाजिक गतिशीलता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर रखने के आदेशों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

खास खबर

नासिक में भीषण गर्मी, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी बंद

नासिक। महाराष्ट्र के नासिक स्थित एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में डीजल संकट और भीषण गर्मी के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। ट्रकों को पर्याप्त डीजल नहीं मिलने से प्याज की ढुलाई प्रभावित हुई, जिसके चलते मंडी में नीलामी प्रक्रिया रोकनी पड़ी। 43 डिग्री तापमान के बीच गोदामों में रखा प्याज तेजी से खराब हो रहा है। व्यापारियों और किसानों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है। मंडी में रोजाना हजारों क्विंटल प्याज की आवक होती है, लेकिन सप्लाई चेन टूटने से व्यापार प्रभावित हुआ है। किसानों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने और परिवहन व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

निजी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस लागू नहीं

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) की गाइडलाइंस सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होंगी। मंत्रालय के अनुसार, यह छूट उन निजी स्कूलों को दी गई है जो शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 2(एन)(4) के तहत आते हैं और जिन्हें सरकार या स्थानीय निकाय से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न वर्गों की चिंताओं और सुझावों के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। फैसले के बाद निजी स्कूलों को प्रशासनिक मामलों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सीबीएसई की नई पॉलिसी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल बोर्ड

ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की नई पॉलिसी को चुनौती वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इस पॉलिसी के तहत नौवीं क्लास के स्टूडेंट्स को तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य किया गया है। यह याचिका स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने मिलकर दायर की है। सीनियर वकील ने सीजेआई की बेंच के सामने याचिका लगाते हुए कहा कि अचानक, नौवीं क्लास के लिए नीति लागू कर दी गई है। यह मौजूदा व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। इससे अफरा-तफरी मच जाएगी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी।

प्रेगाबालिन दवा शेड्यूल एच1 में शामिल, नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेगाबालिन दवा कोशेड्यूल एच1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी। यह फैसला कुछ राज्यों से मिली उन रिपोर्टों को देखते हुए लिया गया, जिनमें प्रेगाबालिन के गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग की बात सामने आई थी। नियमों का उल्लंघन करने और उनका पालन नहीं करने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के मुताबिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि यह दवा पुराने दर्द, न्यूरोपैथी, फाइब्रोमायल्जिया और कुछ विशेष न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के इलाज के लिए दी जाती है, लेकिन कथित तौर पर इसके नींद लाने वाले, उत्साह पैदा करने वाले और मानसिक प्रभावों के कारण इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों, जिनमें निर्माता, वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और फार्मासिस्ट शामिल हैं, को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। देश के कुछ हिस्सों से अवैध रूप से जमा की गई और बिना अनुमति के बेची जा रही प्रेगाबालिन की हाल में बरामदगी की खबरें भी सामने आई हैं। गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी में प्रकाशित इस अधिसूचना के बाद प्रेगाबालिन अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के तहत मौजूदा शेड्यूल एच के बजाय ज्यादा सख्त शेड्यूल एच1 प्रावधानों के तहत विनियमित की जाएगी।

संशोधित वर्गीकरण के मुताबिक प्रेगाबालिन केवल किसी पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर द्वारा जारी वैध पर्चे के आधार पर ही बेची जा सकेगी। साथ ही खुदरा विक्रेताओं को पर्चों और बिक्री का विवरण दर्ज करने के लिए अलग रजिस्टर रखना होगा और निर्माताओं को उत्पाद की पैकेजिंग पर निर्धारित शेड्यूल एच1 ड्रग वार्निंग लेबल प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पूरी आपूर्ति शृंखला में जवाबदेही को मजबूत करना, बिना अनुमति के पहुंच को रोकना, पर्चों की निगरानी को बेहतर बनाना, अवैध तस्करी पर रोक लगाना और दवाओं के गलत इस्तेमाल व दुरुपयोग से जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।

पीएम मोदी ने मंत्रियों से पूछा 2 साल में क्या किया?

बगलें झांकने वालों को दी सख्त हिदायत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पांच देशों के दौरे से लौटते ही शासन व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एनडीए-3 सरकार के दो साल पूरे होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक बेहद अहम और लंबी बैठक हुई। करीब चार घंटे चली इस बैठक में सीधे तौर पर विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

इस उच्च स्तरीय बैठक में कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने मंत्रालयों के प्रदर्शन पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रालयों की रैंकिंग तय करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रमुख पैमानों को आधार बनाया गया—पहला, सरकारी फाइलों का निस्तारण कितनी तेजी से हो रहा है और दूसरा, आम जनता की शिकायतों (पब्लिक ग्रीवांस) को सुलझाने में मंत्रालय का रवैया कितना सक्रिय है।

इन्हीं मानकों के आधार पर सबसे बेहतर काम करने वाले टॉप-5 और सबसे सुस्त प्रदर्शन करने वाले बॉटम-5 मंत्रालयों की एक स्पष्ट सूची बैठक में सामने रखी गई। हालांकि, खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों के नामों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन निचले पायदान पर रहने वाले मंत्रालयों को प्रधानमंत्री ने अपने कामकाज के तरीके में तुरंत सुधार लाने की सख्त हिदायत दी है। पीएम ने दो टूक कहा कि फैसले तेजी से लिए जाने चाहिए, उत्पादकता बढ़ाई जानी चाहिए और लालफीताशाही को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। इस समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की अटकलें जोरों पर हैं। आगामी 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों का परफॉरमेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, उन्हें हटाया जा सकता है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि अच्छा काम करने वाले चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बैठक में कृषि, श्रम, सड़क परिवहन और ऊर्जा सहित कई प्रमुख मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग पर फोकस करते हुए मंत्रियों और शीर्ष नौकरशाहों से कहा कि हर सुधार का अंतिम लक्ष्य आम नागरिक के जीवन को आसान बनाना होना चाहिए।

सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली अगले साल भी जारी रहने की संभावना

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अगले वर्ष भी अपनी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) नामक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को जारी रखेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस साल शुरू हुई प्रणाली, उत्तर पुस्तिकाओं की भौतिक जांच के बजाय डिजिटल रूप से स्कैन की गई प्रतियों का मूल्यांकन कंप्यूटर स्क्रीन पर करती है। बोर्ड मौजूदा साल के कार्यान्वयन और प्राप्त प्रतिक्रियाओं की गहन समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लेगा। मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों ने डिजिटल प्रणाली का बचाव कर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया के कुल पैमाने की तुलना में ऑनलाइन उठाए गए मुद्दों की संख्या सीमित थी।

यह टिप्पणियां छात्रों की बढ़ती असंतुष्टि के बीच आई हैं, जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में धुंधले या अपठनीय पृष्ठों, बिना जांचे उत्तरों, और अंकों में विसंगतियों की शिकायत की है। इसके अतिरिक्त, छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर तकनीकी खराबी की शिकायत की। हालांकि, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने डिजिटल प्रणाली का बचाव कर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया के कुल पैमाने की तुलना में ऑनलाइन उठाए गए मुद्दों की संख्या सीमित थी। एक अधिकारी ने बताया कि करीब 98 लाख स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में से, केवल 13,000 मामलों में ही स्कैनिंग संबंधी समस्याएं मिली, जिनकी मैन्युअल जांच की गई।

ईडी के 20 साल में मात्र 1 फीसदी केस में सजा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और उसकी सफलता दर को लेकर सामने आए आंकड़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 20 वर्षों में ईडी द्वारा दर्ज हजारों मामलों में से केवल 1 फीसदी मामलों में ही अंतिम सजा हो सकी है। आंकड़ों के अनुसार 20 साल में केवल 60 मामलों की सुनवाई पूरी हुई, जबकि दोषसिद्धि दर 93 फीसदी बताई जा रही है।

ईडी ने इस दौरान बड़ी मात्रा में संपत्तियां कुर्क कीं, लेकिन इनमें से करीब 72 फीसदी संपत्ति बाद में लौटानी पड़ी। इससे जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2014 तक मामलों की संख्या सीमित थी, लेकिन 2019 के बाद केस दर्ज करने और मामलों को बंद करने की रफ्तार तेजी से बढ़ी। आंकड़ों में यह भी सामने आया कि गिरफ्तारी और कुर्की की कार्रवाई में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन उसके अनुपात में सजा के मामले बेहद कम रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया और पर्याप्त साक्ष्यों की कमी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। वहीं विपक्ष लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है, जबकि सरकार इसे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई बता रही है।

थिरुवनचूर राधाकृष्णन चुने गए केरल विधानसभा के स्पीकर

राधाकृष्णन को 101 वोट, मोइदीन को 35 और गोपकुमार को 3 वोट मिले

तिरुवनंतपुरम। सात बार के कांग्रेस विधायक थिरुवनचूर राधाकृष्णन को शुक्रवार को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह चुनाव एक ऐतिहासिक त्रिकोणीय मुकाबले के बाद हुआ, जिसने राज्य में नए राजनीतिक समीकरणों को उजागर किया। केरल विधानसभा के स्पीकर पद के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों राजनीतिक गठबंधनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। सत्तारूढ़ यूडीएफ ने अनुभवी विधायक थिरुवनचूर राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया जबकि वाम मोर्चे ने पूर्व मंत्री एसी मोइदीन को मैदान में उतारा और एनडीए ने अपने तीन सदस्यीय दल के सदस्य

बीबी गोपकुमार को प्रत्याशी बनाया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर जी सुधाकरण ने रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाई और मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कुल 139 विधायकों ने मतदान किया। परिणाम घोषित करते हुए उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन को 101 वोट मिले, मोइदीन को 35 और गोपकुमार को 3 वोट मिले। घोषणा के बाद सदन में जोरदार मेज-थपथाई गई और दलों के सदस्य उन्हें बधाई देने आगे आए। एक प्रतीकात्मक और संसदीय परंपरा को दर्शाने वाले दृश्य में सीएमए वीडी सतीशन और विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने संयुक्त रूप से नए स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया।

सीएम सतीशन ने उन्हें विनम्र और परिपक्व व्यवहार वाला आदर्श नेता बताते हुए कहा कि वे पहले छात्र आंदोलन के दिनों में भी उनके लिए नारे लगाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि राधाकृष्णन ने करीब 17 विभाग संभाले हैं और अपने क्षेत्र के विकास पर लगातार ध्यान दिया है। विजयन ने भी उनके लंबे संसदीय और सार्वजनिक जीवन के अनुभव की तारीफ की और विश्वास जताया कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाएंगे।

बता दें समझौता-आधारित राजनीति के लिए जाने जाने वाले राधाकृष्णन कोट्टयम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 1987 में पहली चुनावी हारने के बाद 1991 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे पूर्व सीएम ओमान चांडी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं और अब केरल की राजनीति में एक अहम संवैधानिक पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं।

10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 18 जून को

भावना सिंघल

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख का एलान कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्यसभा की सभी 24 सीटों के लिए 18 जून 2026 को वोटिंग कराई जाएगी। इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी।

इसी के साथ चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात-मध्यप्रदेश समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव 18 जून 2026 को कराया जाएगा। इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती भी होगी।

चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यसभा के जिन 24 सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई 2026 में समाप्त हो रहा है। उन सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून रखी गई है।

आयोग के मुताबिक, मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. इसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी. पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 जून 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

इन चुनावों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सीटें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात से चार सीटें खाली हो रही हैं, साथ ही कर्नाटक से भी चार राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का नाम भी शामिल है। राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी और रवनीत सिंह की सीटें भी खाली हो रही हैं।

चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। किसी अन्य पेन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। साथ ही चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि मतदान निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा कराया जा सके।

राजनीतिक तौर पर इन चुनावों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा में संख्या बल कई बड़े विधेयकों और राजनीतिक रणनीतियों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आने वाले दिनों में विभिन्न दल उम्मीदवारों के चयन और समर्थन जुटाने की कोशिश तेज कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है।

किस राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव?

आंध्र प्रदेश- 4
गुजरात- 4
कर्नाटक- 4
मध्य प्रदेश- 3
राजस्थान- 3
झारखंड- 2
मणिपुर- 1
मेघालय- 1
अरुणाचल प्रदेश = 1
मिजोरम =1

एनसीईआरटी पुस्तक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदला रुख

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़ी कथित आपत्तिजनक सामग्री के मामले में अपने 11 मार्च के आदेश में संशोधन किया है। अदालत ने अब केंद्र, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे इस मुद्दे पर बिना किसी पूर्व टिप्पणी से प्रभावित हुए स्वयं निर्णय लें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने उस हिस्से को भी वापस ले लिया, जिसमें तीन शिक्षाविदों (मिचेल डेनिनो, सुपर्णा द्विवेदी और आलोक कुमार प्रसन्ना) पर छात्रों के सामने न्यायपालिका की नकारात्मक छवि पेश करने के उद्देश्य से तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की टिप्पणी की गई थी। पीठ ने यह फैसला तीनों शिक्षाविदों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि पाठ्य सामग्री तैयार करना एक सामूहिक प्रक्रिया थी और किसी एक व्यक्ति का निर्णय अंतिम नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी पूर्व टिप्पणियां विषयवस्तु के संदर्भ में थीं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ।

कुछ ना कहना

आज से 5 दिनों तक सभी एसबीआई बैंक रहेंगे बंद, शाखाओं में लटकेंगे ताले

25 और 26 मई को होंगी एसबीआई बैंकों में हड़ताल, 2 दिनों की हड़ताल और अवकाश के चलते 5 दिनों तक बैंक रहेंगे बंद, जिले की 18 शाखाओं के करीब,600 कर्मचारी भी हड़ताल में होंगे शामिल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हड़ताल से प्रभावित होगा कामकाज

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

यदि आपका बैंक खाता एसबीआई बैंक में है और बैंक जाकर अगर आप पैसो के लेन देन व बैंक सम्बंधित अन्य कोई काम कराना चाहते है तो यह खबर आपके लिए है।क्यो की देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के कर्मचारियों ने वर्षो से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का एलान किया है।जहा एसबीआई अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा 25 और 26 मई को 02 दिनों की देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। लेकिन इस 02 दिनों की देशव्यापी हड़ताल व अवकाश को मिलाकर कुल 5 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे।जिसका सीधा असर बैंक के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।एसबीआई बैंक कर्मचारियों की इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल और अवकाश के चलते बालाघाट जिले की 18 शाखाओं में भी आगामी 5 दिनों तक ताले लटके नजर आएंगे।जहा के लगभग 600 कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल होंगे।ऐसे में एसबीआई की विभिन्न शाखाओं में आपके बैंक सम्बधित कार्य प्रभावित हो सकते है।

बे-नतीजा निकली यूनियन और सरकार प्रतिनिधियों की बातचीत, किया हड़ताल का एलान

बैंक कर्मचारियों द्वारा यह हड़ताल ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (एआईएसबीआई एसएफ) के आव्हान पर की जा रही है।यहां यूनियन के बैनर तले 25 और 26 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया गया है।बताया गया कि यूनियन की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पिछले दिनों हुई बातचीत बे-नतीजा निकली,जिसके चलते यूनियन के पास आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है. इस मामले में यूनियन ने सांसदों और केंद्र सरकार से भी दखल देने की मांग की है।साथ ही 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान कर दिया है।

इसलिए हड़ताल पर जा रहे कर्मचारी

यूनियन का आरोप है कि बैंक में आपसी बातचीत और समझौतों के नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है. इसके अलावा, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को लेकर भी एक बड़ा विवाद है।नियम के मुताबिक, कर्मचारियों को हर साल अपना पेंशन फंड मैनेजर बदलने की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन एसबीआई ने इसे अब तक लागू नहीं किया है।यूनियन का दावा है कि सही फंड मैनेजर न चुन पाने के कारण देश भर के लगभग 55,000 कर्मचारियों और 55,000 अधिकारियों के रिटायरमेंट फंड पर बुरा असर पड़ रहा है. इसके साथ ही, 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के इंटर-सर्कल ट्रांसफर पर भी बैंक ने एकतरफा रोक लगा दी है।कई बार आवेदन निवेदन पर जब बात नही तो यूनियन को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है।

नौकरियों को लेकर भी विवाद, भर्ती की जगह ठेके पर काम कर रहे लोग

यूनियन का सबसे बड़ा विरोध स्थाई नौकरियों की जगह आउटसोर्सिंग (ठेके पर काम देना) को लेकर है. उनका कहना है कि ट्रेड फाइनेंस, एग्रीकल्चर एसोसिएट और सुरक्षा जैसे जरूरी कामों को बाहरी एजेंसियों को सौंपा जा रहा है, जो पुराने समझौतों के खिलाफ है।इससे युवाओं के लिए रोजगार के मौके कम हो रहे हैं।इसके अलावा,बैंक में जरूरी डॉक्युमेंट्स और कैश लाने-ले जाने वाले 'मैसेंजर्स' की भर्ती पिछले 30 सालों से नहीं हुई है।वहीं, एटीएम चोरी और बैंक शाखाओं पर हमलों के बावजूद साल 2022 के बाद से हथियारों से लैस सुरक्षा गार्ड की नई भर्ती भी नहीं की गई है

जिले में स्थित 18 शाखाओं में 5 दिनों तक लटके रहेंगे ताले

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के आव्हान पर 25-26 मई को होने वाली एसबीआई बैंक हड़ताल से अवकाश को मिलाकर 5 दिन तक बैंकिंग सेवाएं, प्रभावित रहेंगी,जिससे बालाघाट जिले की 18 शाखाओं में भी 5 दिनों तक ताले लटके रहेंगे। हड़ताल के चलते जिले की 18 शाखाओं में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा और करीब 600 कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। लगातार अवकाश और हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं 5 दिनों तक प्रभावित रहने की संभावना है।

ऐसे रहेगा अवकाश का क्रम

23 मई, शनिवार - चौथा शनिवार, बैंक बंद
24 मई, रविवार - साप्ताहिक अवकाश
25 मई, सोमवार - एसबीआई हड़ताल
26 मई, मंगलवार - एसबीआई हड़ताल
27 मई, बुधवार - बकरीद अवकाश। हालांकि देश भर में बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाना है।लेकिन बैंक कलेंडर के अनुसार बैंक कर्मचारी को बकरीद की छुट्टी 27 मई बुधवार को दी गई है।जिसके चलते शनिवार 23 मई से लेकर बुधवार 27 मई तक बैंक बंद रहेंगे जहा बैंक सम्बंधित काम काम नही होगा।जिसका सीधा असर बैंक के लाखों खाता धाराको पर पड़ेगा।

भौरगढ़ में अवैध रेत भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई, 8 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 21 मई 2026 को उपसंचालक (खनिज प्रशासन) सुश्री फरहत जहां के निर्देश पर तहसील खैरलांजी के ग्राम भौरगढ़ में संयुक्त रूप से आकस्मिक जांच अभियान चलाया गया।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार खैरलांजी, खनिज निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल, नायब तहसीलदार डी.एल. परते तथा थाना खैरलांजी के पुलिस अमले ने ग्राम भौरगढ़ में मुख्य सड़क किनारे खनिज रेत का अवैध भंडारण पाए जाने पर जांच की। मौके पर लगभग 8 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत का भंडारण पाया गया।

जांच के दौरान उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त रेत के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या मालिकाना हक प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके चलते प्रशासन ने रेत को लावारिस मानते हुए अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जप्ती की कार्रवाई की।

जप्त की गई रेत को अन्य वाहनों की सहायता से थाना खैरलांजी लाकर सुरक्षार्थ पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। मामले में नियमानुसार प्रकरण तैयार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

कार्यालय तहसीलदार तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. 0013/ब-154/2026-27
मौजा बल्हारपुर, रा.नि.मं. खमरिया

आम सूचना

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक फतनलाल शिवनकर पिता चेतनलाल शिवनकर जाति नाई, निवासी ग्राम बल्हारपुर, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौजा बल्हारपुर, रा.नि.मं. खमरिया, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट में स्थित आवेदक द्वारा अपनी बड़ी माता येशुबाई पति चेतनलाल का अनुज्ञा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 (2), म.प्र. मृत्यु पंजीयन 1999 नियम 12 (2) प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त मृत्यु की घटना दिनांक 16.02.2002 मृत्यु की घटना स्थल ग्राम बल्हारपुर के अंतर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह दिनांक 08.06.2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

स्थान - लालबर्रा
दिनांक - 23.05.2026

भूपेन्द्र अहिरवार
तहसीलदार
तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. 0014/ड-154/2026-27
मौजा बल्हारपुर, रा.नि.मं. खमरिया

आम सूचना

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक फतनलाल शिवनकर पिता चेतनलाल शिवनकर जाति नाई, निवासी ग्राम बल्हारपुर, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौजा बल्हारपुर, रा.नि.मं. खमरिया, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट में स्थित आवेदक द्वारा अपनी माता पुस्ताबाई पति चेतनलाल का अनुज्ञा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 (2), म.प्र. मृत्यु पंजीयन 1999 नियम 12 (2) प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त मृत्यु की घटना दिनांक 05.08.2000 मृत्यु की घटना स्थल ग्राम बल्हारपुर के अंतर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह दिनांक 08.06.2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

स्थान - लालबर्रा
दिनांक - 23.05.2026

भूपेन्द्र अहिरवार
तहसीलदार
तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र.

मलाजखंड के बाकीगुडा गांव में महिला की हत्या

पति पर शक- पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र में एक महिला की उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना ग्राम बाकीगुडा की है।जहां पुलिस ने 46 वर्षीय नीलू धुर्वे पति केशव धुर्वे का खून से सना शव उसके घर से बरामद किया। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में मृतिका के पति केशव धुर्वे पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है और पुलिस उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है।

परिवार के साथ खेती-किसानी करता था केशव

प्राप्त जानकारी के अनुसार केशव धुर्वे अपने परिवार के साथ गांव में रहकर खेती-किसानी का कार्य करता है। परिवार में उसकी पत्नी नीलू धुर्वे के अलावा तीन बेटियां और एक बेटा और पिता धनसिंह धुर्वे हैं। मंझली बेटी सोनिका की शादी बिलासपुर में हो चुकी है। बताया गया कि घटना से करीब पांच दिन पहले बड़ी बेटी सोनम और बेटा सूरज अपनी बड़ी बहन के घर बिलासपुर गए हुए थे। जबकि छोटी बेटी संध्या धुर्वे बालाघाट में रहकर पढ़ाई करती है।

घटना के समय घर में अकेले थे पति-पत्नी

बताया जा रहा है कि 20 मई की सुबह करीब 9 बजे केशव धुर्वे अपनी पत्नी नीलू के साथ घर में मौजूद था। उसी दिन उसका पिता धनसिंह धुर्वे रिश्तेदारी में तरेगांव मंडई गया हुआ था। अगले दिन 21 मई की सुबह केशव धुर्वे गांव के सरपंच झामसिंह के घर पहुंचा और बताया कि तुम्हारी बहन नीलू घर में मौत हो गई है।सूचना मिलते ही सरपंच झामसिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि नीलू धुर्वे घर के अंदर जमीन पर बिस्तर में पड़ी हुई थी। उसके सिर, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान थे तथा नाक और मुंह से खून निकल रहा था। घटना की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।घटना की जानकारी मिलने पर केशव का पिता धनसिंह धुर्वे भी गांव पहुंचा। उसने बेटे केशव से घटना के बारे में पूछताछ की,लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद धनसिंह धुर्वे ने मलाजखंड पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।सूचना मिलते ही मलाजखंड पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे गये। पुलिस ने घर से नीलू का शव बरामद कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

शराब और घरेलू विवाद बना हत्या की वजह

ग्रामीणों के अनुसार केशव धुर्वे शराब पीने का आदी था और उसका अपनी पत्नी नीलू से आए दिन विवाद होता रहता था। आशंका जताई जा रही है कि 20 और 21 मई की दरमियानी रात पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ जिसके बाद गुस्से में आकर केशव ने किसी ठोस वस्तु से नीलू के सिर और पीठ पर हमला कर दिया।जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।हालांकि पुलिस ने अभी हत्या के कारणों और आरोपी की भूमिका को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस संदेह के आधार पर केशव धुर्वे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की करीब कर रही है।

वन विभाग से सेवानिवृत कर्मचारी बेनीप्रसाद तिलासी का निधन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी रेल्वे क्रासिंग समीप निवासरत वन विभाग से सेवानिवृत कर्मचारी बेनीप्रसाद तिलासी उम्र करीब 72 वर्ष का 22 मई की सुबह करीब 6:30 आकस्मिक निधन हो गया। वे काफी समय से अस्वस्थ थे। जिनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे वैनगंगा नदी तट डीमरटोला बूढ़ी मोक्षधाम में किया गया। बताया गया कि बेनीप्रसाद तिलासी के चार पुत्र व एक पुत्री है, उनके निधन पर जिला सर्ववर्गीय कलार समाज द्वारा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित कर ईश्वर से इस गहन दुख को सहन करने की कामना की है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 18 वर्षीय युवक को 20 साल का कठोर कारावास

विशेष न्यायाधीश गौतम सिह मरकाम की अदालत का फैसला

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में विशेष न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश गौतम सिह मरकाम की अदालत ने आरोपी पीयूष पिता अनिल जामरे, 18 वर्ष वार्ड नंबर 8 मरारी मोहल्ला, बालाघाट निवासी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डहेरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा की गई।

वर्ष 2024 की घटना-घर में अकेली थी नाबालिग

अभियोजन के अनुसार मामला वर्ष 2024 का है। 16 मार्च 2024 को सुबह करीब 11:30 बजे वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ला निवासी नाबालिग लड़की के माता-पिता और भाई रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में गए हुए थे। उस समय लड़की घर में अकेली थी। बताया गया कि उसी दिन शाम करीब 4:30 बजे लड़की ने घर में सीलिंग फैन से स्टॉल बांधकर फांसी लगा ली थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घर पहुंचे। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया था।मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने साक्षियों के बयान दर्ज किए। मृतका के परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी पीयूष जामरे कई दिनों से उनकी पुत्री को परेशान कर रहा था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जिसके कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।शंका के आधार पर पुलिस ने आरोपी पीयूष जामरे को गिरफ्तार किया। शव परीक्षण के दौरान प्राप्त अवयवों को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया।जहां से प्राप्त रिपोर्ट और विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 450, 305, 376(3) भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

16 गवाहों के बयान के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 16 साक्षियों के बयान कराए। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी के विरुद्ध धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता के तहत लगाए गए आरोप प्रमाणित पाये।मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश गौतम सिंह मरकाम की अदालत ने आरोपी पीयूष जामरे को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पॉक्सो अदालत ने पीड़िता के माता-पिता को 2 लाख रुपये प्रतिकर देने का दिया आदेश

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सुनाए गए फैसले में विशेष न्यायालय ने पीड़ित बालिका के परिजनों को प्रतिकर प्रदान किए जाने को आवश्यक माना। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पीड़िता लगभग 14 वर्षीय नाबालिग बालिका थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा उसके साथ गंभीर अपराध किया गया, जिससे उसके माता-पिता और परिवार को गहरा मानसिक आघात एवं असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा।

विद्वान अदालत ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं केवल एक अपराध नहीं होतीं, बल्कि पीड़ित परिवार के सामाजिक और मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, पीड़िता की कम आयु तथा उसके परिजनों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीड़िता के माता-पिता को संयुक्त रूप से 2 लाख रुपये प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने का आदेश दिया।

आवश्यकता है
10वीं/12वीं या पदवीधर/आई.टी.आई. की यश एलईडी टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड कम्पनी नागपुर में इंटरव्यू के लिये।
-संपर्क करें-
शिव प्रसाद परिहार
9823234770
9823020378

किरनाई माँ शिक्षा समिति किरनापुर द्वारा संचालित राणा हनुमान सिंह कॉलेज किरनापुर जिला बालाघाट (म.प्र)

आवश्यकता है

राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा परिनियम कॉलेज कोड 28 के अन्तर्गत राणा हनुमानसिंह कॉलेज किरनापुर जिला बालाघाट में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्राचार्य की आवश्यकता है। आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों, बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ महाविद्यालय में कॉलेज कोड-28 के तहत नियुक्ति हेतु दिनाँक 14/06/2025 तक आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करें।

क्र.	पद	विषय	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
01	प्राचार्य	शिक्षा या शिक्षाशास्त्र में पी.एच.डी.	01	स्नातकोत्तर किसी भी विषय में 55प्रतिशत, एवं एम.एड से 55प्रतिशत, शिक्षा या शिक्षाशास्त्र में पी. एच.डी. अनुभव सहायक प्राध्यापक के रूप में 10 वर्ष अनिवार्य

नोटः- उपरोक्त पद के लिये चयन लष्ट/इष्टअध के नियमों के आधार पर किया जायेगा। वेतनमान एवं आरक्षण में बस यू.जी.सी एवं म.प्र. शासन के नियमों का पालन किया जायेगा। आवेदक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय के पते पर डाक/स्पीड पोष्ट द्वारा 21 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में दिनांक 14/06/2026 तक जमा कर सकते है।

पता- राणा हनुमानसिंह कॉलेज किरनापुर
शासकीय आई.टी.आई. के बाजू में
किन्ही रोड किरनापुर जिला
बालाघाट(म.प्र.)
पिन-481115

संचालक/प्रभारी प्राचार्य
राणा हनुमानसिंह कॉलेज किरनापुर
जिला बालाघाट (म0,प्र0)
संपर्क हेतु मो.न.
6261090434,9303405200

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध

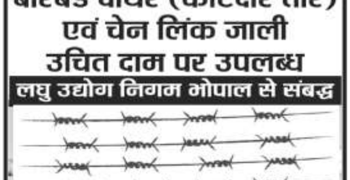

-निर्माता-
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

न्यूज गैलरी

जनपद पंचायत खैरलांजी अध्यक्ष आशु बघेले का निर्वाचन निरस्त

हाईकोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर न्यायालय का बड़ा फैसला, OBC प्रमाण-पत्र विवाद में कार्रवाई

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। खैरलांजी में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे बहुचर्चित निर्वाचन विवाद में कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य श्रीमती आशु बघेले का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। यह आदेश 14 मई 2026 को पारित किया गया।

प्रकरण की शुरुआत जनपद सदस्य खुशबू बिसेन द्वारा दायर निर्वाचन याचिका से हुई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि श्रीमती आशु बघेले ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) महिला हेतु आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते समय मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उनके पास केवल महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी पिंजारा जाति प्रमाण-पत्र था, जबकि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियमों के अनुसार आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मध्यप्रदेश का जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

मामला पहले कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा था, जहां से पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचा। हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को पूर्व आदेश निरस्त करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि 1 फरवरी 2019 को संशोधित पंचायत निर्वाचन नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य है और केवल शपथ-पत्र इसके स्थान पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पुनः सुनवाई के दौरान अनावेदक पक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग के परिपत्र एवं शपथ-पत्र के आधार पर नामांकन वैध बताए जाने की दलील दी, वहीं आवेदिका पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए निर्वाचन निरस्त करने की मांग की।

कलेक्टर न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि श्रीमती आशु बघेले ने नामांकन पत्र के संबंधित कॉलम में स्वयं नहीं अंकित कर यह स्वीकार किया था कि उनके पास मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं था। न्यायालय ने माना कि महाराष्ट्र का प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश में आरक्षण लाभ के लिए मान्य नहीं माना जा सकता तथा नामांकन स्वीकार किया जाना वैधानिक त्रुटि थी।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण याचिका दायर होने मात्र से मूल आदेश पर स्वतः रोक नहीं लगती। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसके बाद कलेक्टर न्यायालय ने अंतिम निर्णय पारित किया। आदेश के अनुसार श्रीमती आशु बघेले को जनपद पंचायत खैरलांजी के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 से जनपद सदस्य तथा अध्यक्ष पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए दोनों निर्वाचन शून्य एवं निरस्त घोषित किए गए हैं। साथ ही सक्षम प्राधिकारी को रिक्त पदों पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क पर चल रही इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में लगी अचानक आग, स्कूटी जलकर खाक

आग लगने से मचा हड़कंप,वाहन छोड़कर दूर भागे युवक, नगर के डेंजर रोड़ का मामला, चार्जर के काम से गर्रा गए थे युवक, वापस आते समय हुआ हादसा, बैटरी से धुआं निकलने के बाद लगी आग

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं अक्सर देखी जाती है। जहां कभी चार्जिंग करते समय तो, कभी स्टार्ट करते समय तो कभी चलते वाहन में अचानक आग लग जाने से वाहन मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।आए दिनों सामने आ रही इन्ही घटनाओं के बीच शुक्रवार की शाम नगर के डेंजर रोड़ बायपास पर उस वक्त अफरातफरी का माहौल बन गया जब सड़क पर चलते एक इलेक्ट्रिक वाहन में अचानक से आग लग गई। जहा बैटरी में अचानक स्पार्किंग के साथ सीट के नीचे से धुआं निकलने लगा और इस आग ने पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस नजारे को देखकर आसपास के लोग सकते में आ गए और वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। इसी बीच स्कूटी मालिक और अन्य स्थानीय लोगों ने स्कूटी में धूल मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और देखते ही देखते इलेक्ट्रिक स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई।जहा उक्त आग ने पूरी स्कूटी को ही अपनी चपेट में ले लिया, जहा कुछ ही पल में पूरी स्कूटी जलकर खाक हो गई।

युवक ने खरीदी थी सेकंड हैंड स्कूटी, गर्रा से लौटते वक्त हुआ हादसा

बताया गया कि ग्राम भटेरा रामेश्वरम नगर वार्ड नंबर 19 निवासी युवक केशव पिता दिनेश साहू ने पिछले वर्ष की लक्ष्मी पूजा के दिन किसी व्यक्ति से यह सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी, कुछ दिन पूर्व से इस स्कूटी में चार्जिंग की समस्या आ रही थी।प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को युवक केशव साहू अपने एक साथी को लेकर चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए गर्रा गया हुआ था, जहां से युवक अपने साथी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी में सवार होकर वापस बालाघाट आ रहा था।जिन्होंने घूमते हुए डेंजर रोड़ से घर जाने की सोची।जब युवक डेंजर रोड़ से जागपुर घाट की ओर जा रहे थे, तभी चलती स्कूटी में सीट के नीचे से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसे देख युवकों ने स्कूटी खड़ी की और धुआ कहां से निकल रहा है यह देखने लगे इसी दरमियान बैटरी में एक चिंगारी के साथ अचानक स्कूटी में आग लग गई और देखते ही देखते यह स्कूटी पूरी तरह से जलकर हो गई।

बुझाने से भी नही बुझी आग

बताया जा रहा है कि यह आग इतनी भयानक थी कि मिट्टी डालने पर भी नहीं बुझ रही थी। जहां आगजनी की इस घटना से चेचिस का भाग छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की सीट, बैटरी पीछे का फाइबर सहित सब कुछ जल गया।आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक मात्रा में बैटरी चार्ज होने के चलते उसमें अचानक शार्ट सर्किट हुआ होगा और बैटरी से धुआं निकालने के साथ उसमे आग लग गई।उधर घटना के दौरान इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता की शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग ने पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया और स्कूटी में आग लग गई।वहीं अचानक हुई इस घटना से स्कूटी मालिक को नुकसान उठाना पड़ा है।

करीब आधे घण्टे तक लगा रहा जाम

हालांकि यह अच्छी बात रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग से पूरी ईव्ही स्कूटी जलकर खाक हो गई है।बताया गया कि गर्मी के दिनो में अकसर चलते वाहनों में आग रही है।लगातार सामने आ रही वाहनों में आगजनी की घटना ने लोगों को डरा दिया है।डेंजर रोड़ पर हुई इस घटना के बाद वहां कुछ देर के लिए आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया।जहा तकरीबन आधा घंटे तक जाम लगा रहा। जिसके बाद लोग किनारे से वाहन निकलकर अपने गंतव्य की ओर जाते नजर आए।

जनजाति गर्जना डीलिस्टिंग महारैली में शामिल होने दिल्ली रवाना होंगे जिले के 600 से अधिक लोग

जनजाति सुरक्षा मंच ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण को लेकर होगा आयोजन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जनजाति सुरक्षा मंच के आवाहन पर 24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में वृहद स्तर पर जनजाति संस्कृति समागम का आयोजन किया जा रहा हैं। कार्यक्रम को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी संबंध में मंच के पदाधिकारी लखन मरावी ने स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी दीं। प्रेस वार्ता के दौरान लखन मरावी ने बताया कि जनजाति समाज की संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से इस विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए समाज को एकजुट करना आवश्यक है, इसी उद्देश्य के साथ देशभर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि महाकौशल क्षेत्र सहित आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग दिल्ली पहुंचेंगे। बालाघाट से भी समाज के लोग 23 मई की सुबह 7 बजे रवाना होंगे। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, परंपरा, सामाजिक अधिकार और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने अनुसूचित जनजाति समुदाय से धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को मिलने वाले आरक्षण और शासकीय लाभों को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। मंच का कहना है कि जो लोग जनजातीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं को छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत मिलने वाले संवैधानिक अधिकार, आरक्षण और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर 24 मई 2026 को देश की राजधानी दिल्ली में जनजाति गर्जना डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशभर से बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे। इस संबंध में जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारी लखन मरावी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में लोग जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी ऐसे लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण, शासकीय योजनाओं और अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक जनजातीय समाज के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। लखन मरावी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की मूल संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज और धार्मिक पहचान को छोड़ देता है, तो उसे उसी धर्म के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के लिए संविधान द्वारा दिए गए विशेष अधिकार और आरक्षण उन लोगों के लिए हैं जो आज भी अपनी पारंपरिक जनजातीय जीवनशैली और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो जनजातीय समाज को छोड़कर अन्य धर्म अपना चुके हैं, लेकिन फिर भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के नाम पर शासकीय योजनाओं और आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। मंच का कहना है कि इससे वास्तविक जरूरतमंद जनजातीय समाज के लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा मंच के आह्वान पर दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम एवं जनजाति गर्जना डीलिस्टिंग महारैली आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में देशभर के विभिन्न जनजातीय समाजों के प्रतिनिधि शामिल होकर अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज और धार्मिक पहचान के संरक्षण एवं संवर्धन की मांग उठाएंगे लखन मरावी ने बताया कि बालाघाट जिले से लगभग 600 लोग विशेष ट्रेन के माध्यम से 23 मई की सुबह 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं पूरे महाकौशल क्षेत्र से लगभग 15 हजार से अधिक लोगों के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजातीय समाज के अधिकारों और पहचान से जुड़ा बड़ा आंदोलन है, जिसे आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा। मंच की प्रमुख मांग यह है कि अनुसूचित जनजाति से अन्य धर्म में जाने वाले लोगों की डीलिस्टिंग की जाए। यानी ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची से हटाकर उन्हें मिलने वाले आरक्षण और शासकीय लाभों को समाप्त किया जाए, ताकि वास्तविक जनजातीय समाज के लोगों को उनका अधिकार मिल सके।

जंगलों में गीत-संगीत के सहारे तेंदूपत्ता तुड़ाई, वन विभाग का अनोखा प्रयोग

भालू, बाघ और तेंदुए के हमलों से बचाने मोबाइल-रेडियो लेकर जंगल भेजे जा रहे संग्राहक

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के जंगलों में इन दिनों तेंदूपत्ता तुड़ाई का कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा है, लेकिन इस बार जंगलों में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं मोबाइल पर पुराने गीत बज रहे हैं तो कहीं रेडियो की आवाज जंगलों में गूंज रही है। यह कोई मनोरंजन नहीं, बल्कि वन विभाग की नई सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। वन विभाग ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को जंगल में मोबाइल और रेडियो के माध्यम से गीत-संगीत बजाते हुए तेंदूपत्ता तोड़ने की सलाह दी है, ताकि हिंसक वन्यप्राणियों के हमलों से बचा जा सके।

हर वर्ष तेंदूपत्ता सीजन के दौरान जंगलों में भालू, बाघ और तेंदुए जैसे वन्यप्राणियों के हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं। कई बार तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण घायल हो जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में जान तक चली जाती है। इसी खतरे को कम करने के उद्देश्य से इस बार उत्तर वन मंडल बालाघाट सामान्य ने यह नया प्रयोग शुरू किया है। वन विभाग का मानना है कि जंगल में लगातार गीत-संगीत या मानवीय गतिविधियों की आवाज सुनकर वन्यप्राणी पहले से सतर्क हो जाते हैं और इंसानों के करीब आने की बजाय दूसरी दिशा में चले जाते हैं। इससे अचानक आमना-सामना होने की संभावना कम हो जाती है और मानव-वन्यप्राणी संघर्ष को रोका जा सकता है। इस प्रयोग को लागू करने से पहले वन विभाग ने गांव-गांव जाकर चौपाल आयोजित की। अधिकारियों और कर्मचारियों ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को जंगल में सुरक्षित तरीके से काम करने की जानकारी दी। ग्रामीणों को समझाया गया कि वे अकेले जंगल में न जाएं, समूह में कार्य करें, अंधेरे में जंगल में प्रवेश न करें और मोबाइल या रेडियो के जरिए लगातार आवाज बनाए रखें। वन विभाग ने यह भी बताया कि जंगल में लंबे समय तक सन्नाटा रहने पर वन्यप्राणी इंसानों के बेहद करीब तक आ जाते हैं, लेकिन यदि पहले से मानव गतिविधियों की आवाज आती रहे तो वे दूरी बनाए रखते हैं। उत्तर वन मंडल बालाघाट सामान्य के अंतर्गत इस वर्ष सात परिक्षेत्रों , उत्तर लामता, दक्षिण लामता, उत्तर उकवा, दक्षिण उकवा, पश्चिम बैहर, पूर्व बैहर और बिरसा दमोह सामान्य क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों से जुड़े लगभग कई गांवों के लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। उत्तर वन मंडल के अधिकांश जंगल कान्हा टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां बड़ी संख्या में भालू, तेंदुआ और अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में हर साल तेंदूपत्ता तुड़ाई के दौरान खतरा बना रहता है। इसी कारण विभाग ने पारंपरिक व्यवस्था से हटकर यह नई रणनीति अपनाई है। इस बार तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ाई गई है। कई जगह पुरुषों की बजाय महिलाओं को संग्राहक समूहों का मुखिया बनाया गया है। संग्राहक कार्ड भी महिलाओं के नाम से जारी किए गए हैं और तेंदूपत्ता की राशि व बोनस सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। वन विभाग का मानना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। तेंदूपत्ता संग्रहण वन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन माना जाता है। वन विभाग ने संग्राहकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। लोगों से कहा गया है कि वे सुबह उजाला होने के बाद ही जंगल जाएं, अकेले कार्य न करें, बच्चों को साथ न ले जाएं और किसी भी वन्यप्राणी के दिखने पर घबराने की बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फिलहाल जंगलों में गीत-संगीत के सहारे तेंदूपत्ता तुड़ाई का यह अनोखा प्रयोग लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और वन विभाग इसे वन्यप्राणी-मानव संघर्ष रोकने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मान रहा है।

सरकार ने की पेशा मोबेलाइजर कर्मचारियों की सेवा समाप्त

विरोध में उतरेंगे कर्मचारी, 25 को करेंगे अर्धनग्न प्रदर्शन, भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आंदोलन की बनाई रणनीति

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन द्वारा पेशा मोबेलाइजर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में अब कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों का आंदोलन तेज होने लगा है। भारतीय मजदूर संघ जिला बालाघाट के बैनर तले 25 मई को जिला मुख्यालय में आमसभा, अर्धनग्न प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया जाएगा।आंदोलन के माध्यम से कर्मचारियों की सेवा बहाली तथा लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।जिसकी तमाम जानकारी शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष योगेश यादव एवं जिला महामंत्री मनोज सोहागपुरे ने प्रेसविज्ञप्ति जारी कर दी है।जारी विज्ञप्ति में बताया कि वर्ष 2020 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा पेशा एक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्रों में पेशा मोबेलाइजर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इन कर्मचारियों का मुख्य कार्य पंचायतों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीण और आदिवासी समुदाय तक पहुंचाना था। कर्मचारियों ने कई वर्षों तक गांव-गांव जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन और जागरूकता का कार्य किया।लेकिन हाल ही में 18 मई 2026 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी कर प्रदेशभर में कार्यरत सभी पेशा मोबेलाइजर कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था और पूर्व सूचना के सेवा समाप्त करना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। भारतीय मजदूर संघ ने शासन के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन की घोषणा की है। तय कार्यक्रम के अनुसार 25 मई को दोपहर 2 बजे काली पुतली चौक में आमसभा आयोजित की जाएगी।इसके बाद कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगी। वहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पेशा मोबेलाइजर कर्मचारियों की सेवाएं पुनः बहाल करने की मांग की जाएगी।ज्ञापन में कर्मचारियों को नियमित सेवा लाभ देने, सेवा समाप्ति आदेश वापस लेने तथा रुका हुआ मानदेय एकमुश्त भुगतान करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि यदि शासन ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।भारतीय मजदूर संघ ने जिले के सभी प्रभावित पेशा मोबेलाइजर कर्मचारियों से आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की है। वहीं प्रशासन से रैली और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सहयोग की मांग की गई है।

आस-पास की खबरें

जाम के शास. उमावि. में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से लगभग 10 किमी. दूर ग्राम पंचायत जाम स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। पर्यावरण

शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने इस वर्ष की निर्धारित थीम के अनुरूप उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां प्रस्तुत की। यह कार्यक्रम स्कूल प्राचार्य आरसी बिसेन, इको क्लब प्रभारी श्रीमती ममता शरणागत सहित अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए निबंध लेखन, ड्राइंग (चित्रकला) एवं स्वच्छता संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी कला और विचारों के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। वहीं संस्था के प्राचार्य आर. सी. बिसेन एवं इको क्लब प्रभारी श्रीमती ममता शरणागत (उ.मा.शि.) ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मानवीय गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रजातियां तेजी से घट रही हैं और उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसके प्रति हमें तत्काल जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरी मानव जाति का अस्तित्व पारिस्थितिक संतुलन पर ही निर्भर है, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) को मजबूत करना आज के समय की सबसे बड़ी और वर्तमान आवश्यकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के शिक्षक विनय दमाहे, विवेक शुक्ला, रितेश ब्रम्हवंशी, रविन्द्र नागेश्वर, संजय पंचेश्वर, दिलीप कावडे, कु. अमृता नामदेव एवं प्रतियोगी छात्र नमीता लिल्हारे, मुरलीकुमार, ललित पंचेश्वर, अतुल दमाहे, दीपक लिल्हारे सहित सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा।

सर्राटी जलाशय की माइनर नहर जगह-जगह से हुई क्षतिग्रस्त, झाड़ियों का लगा अंबार

नहर में पानी छोड़ने पर रूकावट बनेगी गंदगी, किसानों ने की मरम्मत और सफाई करवाने की प्रशासन से मांग

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

नगर मुख्यालय से लगभग 8 किमी. दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी ला. स्थित सर्राटी जलाशय से निकली माइनर नहर प्रशासन की अनदेखी के कारण बदहाली के आंसू बहा रही है। दो से तीन वर्ष पूर्व लाखों रूपयों की लागत से इस नहर का सीमेंटीकरण (पक्कीकरण) किया गया था। लेकिन घटिया निर्माण कार्य के चलते महज कुछ ही वर्षों में यह नहर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होने लगी है। स्थिति यह है कि नहर के कुलापे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पक्का निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा है। वहीं लंबे समय से साफ- सफाई न होने के कारण नहर के अंदर भारी मात्रा में कचरा और गंदगी जमा हो चुकी है एवं झाड़ियां उग आई हैं। ऐसी स्थिति में नहर में पानी छोड़ने पर ये कचरा, झाड़िया रूकावट बनेगी और किसानों के खेतों तक पानी नही पहुंचेगा। इसलिए क्षेत्रीय किसानों ने जल संसाधन विभाग से सर्राटी जलाशय टेकाड़ी ला. से रामजीटोला माइनर नहर की मानसूनी सीजन शुरू होने के पहले साफ-सफाई, क्षतिग्रस्त स्थान का मरम्मत एवं अधुरे कार्य को बरसात के पूर्व पूर्ण करवाने की मांग की है।

फसलें प्रभावित होने की आशंका

आपकों बता दे कि किसानों के खेतों में लगने वाली फसल की सिंचाई के लिए सर्राटी जलाशय से छोटी माइनर नहर निकली है। जिसका निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में 100 वर्ष पूर्व कच्चा निर्माण किया गया था और यह नहर ग्राम टेकाड़ी ला., बघोली, औल्याकन्हार, पांढरवानी व रामजीटोला की ओर बहती थी। जिसकी मदद से किसान अपनी फसल में सिंचाई करते थे परन्तु यह माइनर नहर पुरी तरह से जीर्णशीर्ण हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। इसलिए क्षेत्रीय किसानों ने शासन-प्रशासन से माइनर नहर का सीमेन्टीकरण करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किये थे। जिसके बाद सरकार से लाखों रूपयों की लागत से माइनर नहर का सीमेन्टीकरण हेतु राशि स्वीकृत होने के बाद लगभग 3 वर्ष पूर्व इस माइनर नहर का सीमेन्टीकरण निर्माण किया गया है लेकिन निर्माण कंपनी के द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य करवाया गया है। जिस कारण से निर्माण के कुछ साल बाद ही नहर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होने लगी है। साथ ही कुछ स्थानों से निर्माण कार्य भी अधुरा है और नहर के अंदर गंदगी व झाड़िया होने के कारण टेल क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी नही पहुंच पाता है जिससे किसानों की फसलें पानी के अभाव में प्रभावित हो जाती है। वहीं लंबे समय से क्षेत्रीय किसानों के द्वारा अधुरे कार्य को जल्द पूरा करने, नहर की साफ-सफाई एवं मरम्मत कार्य करवाने की मांग कर रहे है। लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि आगामी मानसूनी सीजन में जब सिंचाई के लिए जलाशय से नहर में पानी छोड़ा जायेगा तो यह गंदगी और झाड़ियां पानी के बहाव में बड़ी रूकावट बनेंगी। ऐसी स्थिति में पानी टेल (अंतिम छोर) तक नहीं पहुंच पायेगा और किसानों के खेतों तक पानी न मिलने से उनकी फसलें बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। लाखों रूपये खर्च होने के बाद भी किसानों को इसका समुचित लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। इसलिए जल संसाधन विभाग से मांग है कि बरसात शुरू होने से पूर्व सर्राटी जलाशय टेकाड़ी ला. से रामजीटोला माइनर नहर के किनारों (पारो) और अंदर उग चुकी झाड़ियों की साफ-सफाई करवाये। साथ ही नहर के अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि किसानों को सिंचाई के लिए सुचारू रूप से पानी मिल सके।

झाड़ियों की सफाई एवं मरम्मत कार्य करवाये प्रशासन - ओमप्रकाश

औल्याकन्हार सरपंच प्रतिनिधि ओमप्रकाश बिसेन ने बताया कि टेकाड़ी ला. जलाशय से निकलने वाली मुख्य नहरों से क्षेत्र के लगभग 52 गांवों की कृषि भूमि सिंचित होती है। यह नहर इन गांवों के किसानों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। विगत वर्ष पूर्व सर्राटी जलाशय टेकाड़ी ला. से रामजीटोला माइनर नहर का सीमेन्टीकरण किया गया है लेकिन दो से तीन वर्ष पूर्व हुआ नहर का निर्माण कार्य बेहद घटिया किस्म का था, जिससे क्षेत्र के लोग भली-भांति वाकिफ हैं। आज स्थिति यह है कि नहर कई स्थानों से टूट-फूट चुकी है। साथ ही देखरेख के अभाव में नहर के अंदर बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आई हैं। जगह-जगह कचरा और गंदगी जमा होने के कारण पानी का प्रवाह पूरी तरह से अवरूध्द होने की कगार पर है। जिससे नहर में पानी छोड़ने पर ये झाड़ियां रूकावट बनेगी। श्री बिसेन ने बताया कि कुछ महीनों बाद बरसात शुरू होने वाली है और मानसूनी सीजन में नहर में पानी छोड़ा जायेगा इसलिए प्रशासन से मांग है कि नहर के जितने भी क्षतिग्रस्त (डैमेज) हिस्से हैं, उन्हें तत्काल दुरूस्त करें, नहर के अंदर जमा कचरे, झाड़ियों की सफाई करवाये, अधूरा पड़ा निर्माण कार्य बारिश शुरू होने से पहले उसे पूरा करवाये। ताकि किसानों को समय पर और बिना किसी रूकावट के सुचारू रूप से पानी मिल सके।

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का अंतिम दिन आज

538 किसानों से 15 हजार क्विंटल से अधिक की हुई खरीदी

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। शासन के निर्देशानुसार रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य गत दिवस से जारी है। सरकार द्वारा तय की गई समयसीमा के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अंतिम दिन आज यानि 23 मई है। आज शाम तक खरीदी केंद्रों पर आने वाले पंजीकृत किसानों से गेहूं की अंतिम खेप खरीदी जायेगी। इसके बाद इस सीजन के लिए खरीदी बंद कर दी जायेगी। वहीं अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो क्षेत्र के किसानों में समर्थन मूल्य पर फसल बेचने को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा गया। साथ ही लालबर्रा वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति के द्वारा पांढरवानी-टेंगनीकला पहुंच मार्ग स्थित वेयर हाउस में समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है और उपज विक्रय करने के लिए 584 किसानों ने स्लॉट बुकिंग करवाये है। जिसमें से 22 मई तक 538 किसानों से 15,504 क्विंटल गेंहू समर्थन मूल्य में खरीदी की गई है एवं शेष किसानों से आज खरीदी की जायेगी। वहीं उपज विक्रय करने के बाद भी समय पर भुगतान खाते में नही आने से किसान परेशान है। किसानों ने उपज खरीदी के दुसरे दिन खाते में भुगतान करवाने की प्रशासन से मांग की है।

अंतिम दिन इन पर रहेगी नजर

आपकों बता दे कि शासन के निर्देश पर गत दिवस से समर्थन मूल्य में गेंहू खरीदी की जा रही है और वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा के द्वारा पांढरवानी रोड़ स्थित वेयर हाउस में खरीदी की जा रही है। लेकिन स्लॉट बुकिंग का पोर्टल गत दिवस से बंद हो गया था जो दोबारा शुरू नही हो पाया। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के बहुत से किसान उपज विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग करवाने पहुंचे लेकिन नही हुआ और उन्हे बैरंग वापस होना पड़ा है। पूर्व में जिन किसानों ने स्लॉट बुकिंग करवा लिये थे उन्ही किसानों से समर्थन मूल्य में गेंहू उपज की समिति के द्वारा खरीदी की गई है। जिसका अंतिम दिन आज 23 मई है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों का स्लॉट बुकिंग नही हुआ है ऐसे किसान समर्थन मूल्य में उपज विक्रय नही कर पायेगें उन्होने खरीदी की तिथि बढ़ाकर पोर्टल चालू करवाने की मांग प्रशासन को है ताकि समर्थन मूल्य में उपज विक्रय कर सके। नही तो मजबूरी में उन्हे कम दाम में व्यापारियों को अपनी उपज विक्रय करना पडेगा। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, स्लॉट बुकिंग कराने वाले कुल किसानों में से 538 किसान अपनी उपज बेच चुके हैं। अब शेष बचे किसानों के पास अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने का आज आखिरी मौका है। आज अंतिम दिन कितने और किसान केंद्र पर पहुंचते हैं और कुल खरीदी का आंकड़ा कहां तक जाता है, इस पर विभाग और प्रशासन की नजर बनी हुई है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए छांव, ठंडे पानी और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों ने शेष बचे किसानों से अपील की है कि वे समय रहते केंद्र पर पहुंचकर अपनी उपज की तौल करवा लें, ताकि अंतिम समय में किसी भी तरह की तकनीकी या व्यावहारिक परेशानी से बचा जा सके।

शेष किसान समयावधि पर पहुंचकर उपज करें विक्रय - गणेश

दूरभाष पर चर्चा में वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा के खरीदी प्रभारी गणेश लांजेवार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गत दिवस से समर्थन मूल्य में गेंहू खरीदी की जा रही है और उपज विक्रय के लिए 584 किसानों ने स्लॉट बुकिंग करवाये थे। जिसमें से 538 किसानों से 15,504 क्विंटल गेंहू की खरीदी की गई है एवं शेष किसानों से आज खरीदी की जायेगी। श्री लांझेवार ने बताया कि खरीदी का आखिरी दिन 23 मई है, इसलिए जिन किसानों ने स्लॉट बुकिंग करवा लिये है, उपज विक्रय नही किये है, ऐसे किसान समयावधि पर खरीदी केन्द्र पहुंचकर उपज विक्रय करें।

डोंकरबंदी में बह रही ज्ञान की गंगा

बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा के प्रसंग पर झूमे श्रध्दालु, कथा श्रवण कर प्राप्त कर रहे धर्मलाभ

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डोंकरबंदी इन दिनों पूरी तरह से भक्ति के रंग में सराबोर है। राधा रानी और शिव-शक्ति की असीम अनुकम्पा से ग्राम के राधा कृष्ण, शिव-शक्ति स्कूल ग्राउंड में समस्त नारी शक्ति महिला मंडल एवं ग्रामीणजनों के द्वारा आयोजित नौ दिवसीय भव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बह रही है। 17 मई से शुरू हुआ यह आध्यात्मिक महोत्सव आगामी 25 मई तक निरंतर चलेगा। कथा के मुख्य वाचक एवं प्रखर कथाव्यास पं. घनश्याम शुक्ला के मुखारविंद से बरस रहे कथा अमृत और संगीतमय भजनों का रसपान करने के लिए प्रतिदिन आसपास के ग्रामीण अंचलों से भारी संख्या में श्रध्दालुगण आयोजन स्थल पर पहुंचकर कथा श्रवण कर धर्मलाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ से पूरे ग्राम में ज्ञान की गंगा बह रही है। इस नौ दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथावाचक के द्वारा 22 मई को कृष्ण लीला, माखन चोरी एवं गोवर्धन पूजा पर प्रवचन दिया गया। इस दौरान उपस्थित श्रध्दालुओं ने झुमते हुए भक्ति में भाव-विभोर हो गये और पुण्य लाभ अर्जित किये। वहीं प्रतिदिन प्रात: 8 बजे से 10 बजे तक मुख्य पीठ का विधि-विधान से पूजन संपन्न किया जाता है एवं दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्य कथा का वाचन होता है, जिसमें मुख्य प्रसंगों की व्याख्या की जा रही है। वहीं शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा तक विशेष भजनों, आरती और दिव्य प्रसंगों का क्रम चलता है, जिसमें देर रात तक भक्त लीन रहते हैं।

भगवान की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा का जीवंत वर्णन

17 मई से जारी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ में अब तक भव्य कलश शोभा यात्रा, व्यास पूजन, कपिल देव व सुखदेव आगमन, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रह्लाद चरित्र, भगवान नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार तथा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा चुका है। 22 मई (शुक्रवार) को दोपहर के सत्र में कथाव्यास पं. घनश्याम जी शुक्ला ने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक बाल लीलाओं, माखन चोरी के नटखट प्रसंगों और गोवर्धन पूजा का अत्यंत मनोहारी व जीवंत वर्णन किया। छप्पन भोग और गोवर्धन पर्वत की झांकी के सम्मुख श्रध्दालु भावविभोर होकर झूम उठे। कथाव्यास ने संदेश दिया कि गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के संरक्षण और अहंकार के त्याग की प्रेरणा देती है। वहीं 23 मई को उध्दव संवाद, रासलीला, कृष्ण विवाह, 24 मई को सुदामा चरित्र, द्वारिका लीला, यदोवंशीय उध्दार, गवलोक गमन, परिक्षित मोक्ष पर कथावाचक के द्वारा प्रवचन दिया जायेगा तत्पश्चात कथा विश्राम एवं 25 मई को यज्ञ पूर्णाहुति एवं विशाल महाप्रसादी वितरण के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का समापन किया जायेगा। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं ग्रामीणजनों ने क्षेत्र के सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से इस मंगलमय आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है।

कनकी में रात्रि कालीन चौपाल लगाकर कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्या

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के कलेक्टर मृणाल मीना ने गुरुवार 22 मई को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम कनकी में रात्रिकालीन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। चौपाल में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के खंड एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। चौपाल की शुरुआत में ग्राम पंचायत कनकी के सरपंच श्री दुर्गा प्रसाद पगरवार ने गांव की प्रमुख समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने बताया कि गांव के आधे हिस्से को धपेरा फीडर और शेष हिस्से को गर्रा फीडर से बिजली आपूर्ति होने के कारण नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बांडा तालाब की भूमि का सीमांकन नहीं होने, नहरों की सफाई नहीं होने, रेत खदान से ग्रामीणों को रेत नहीं मिलने तथा नल-जल योजना का पानी आवास टोला तक नहीं पहुंचने जैसी समस्याएं बताई। कलेक्टर श्री मीना ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री ने 15 दिनों के भीतर बिजली फीडर संबंधी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लवादा की पानी टंकी में क्षमता अनुसार जल भंडारण नहीं होने से पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग को बांडा तालाब की नहरों की सफाई कराने के निर्देश भी दिए गए।ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए सड़क किनारे नाली निर्माण की मांग रखी। इस पर पंचायत सचिव को जेसीबी मशीन से नाली खुलवाने की कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं कनकी के बंजारी आवास टोला में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र नहीं होने की समस्या पर कलेक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के लिए वैकल्पिक शाला व्यवस्था करने तथा आंगनवाड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चौपाल में खाद्यान्न पात्रता पर्ची और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर श्री मीना ने स्पष्ट किया कि अपात्र लोगों के नाम सूची से हटने के बाद पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची जारी की जाएगी। वहीं जिन लोगों के नाम आवास प्लस सर्वे सूची में शामिल हो चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। कृषि एवं पशुपालन विभाग से संबंधित समस्याओं पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को जानकारी दी। कृषि विभाग ने किसानों को मिट्टी परीक्षण सुविधा का लाभ लेने की अपील की, जबकि पशुपालन विभाग ने बताया कि मादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा के लिए पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर श्री मीना ने पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कृषि विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, एएनएम तथा पंचायत स्तर के अन्य कर्मचारियों की ग्राम पंचायत में उपलब्धता का साप्ताहिक शेड्यूल पंचायत भवन में चस्पा करने के निर्देश दिए।

विधायक विवेक पटेल ने वारासिवनी और रामपायली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया निरीक्षण

भर्ती मरीजो से अच्छा व्यवहार करें चिकित्सक अन्यथा होगी कठोर कार्यवाही-विवेक पटेल

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी/रामपायली।

वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक पटेल ने शुक्रवार को वारासिवनी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपायली का आकस्मिक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की समस्त व्यवस्थाओं मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं स्वच्छता दवा वितरण उपचार व्यवस्था स्टाफ की उपस्थिति एवं अस्पताल संचालन की गुणवत्ता का गंभीरता से अवलोकन किया गया। विधायक के अचानक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में सक्रियता और जवाबदेही का वातावरण दिखाई दिया। इस अवसर पर मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.परेश उपल्व, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्यम शर्मा, मेडिकल ऑफि सर डॉ.किरण बंसोड, मेडिकल ऑफि सर डॉ.प्रिया बिसेन, सेक्टर सुपरवाइजर अनिल तिवारी, फार्मासिस्ट कार्तिक शरणागत, रेडियोग्राफर कपिल बघेल, कंप्यूटर ऑपरेटर नरसिंह नगपुरे , नर्सिंग ऑफिसर चांदनी साखरे,जनपद सदस्य जीतू राजपूत, जगदीश बंसोड, रामपायली सरपंच संदीप बाघमारे, केवल शिवहरे, बुद्धेश बिसेन , रजनीश नकाशे सहित अनेक ग्रामीणजन मौजूद रहे। सभी ने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं एवं आवश्यकताओं से विधायक को अवगत कराते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के शीघ्र विस्तार एवं आधुनिक सुविधाओं की मांग रखी। ग्रामीणों ने अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित उपलब्धता पर्याप्त बेड व्यवस्था आधुनिक जांच सुविधाए एक्स.रे एवं

पैथोलॉजी सेवाओं को और मजबूत करने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने तथा आपातकालीन उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग प्रमुखता से उठाई।

साफ सफाई व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया

विधायक विवेक पटेल ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर वार्ड प्रसूति कक्ष शौचालय एवं मरीज प्रतीक्षालय की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। ताकि मरीजों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पताल जनता के विश्वास का केंद्र होते हैं और यहां आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान ओपीडी कक्ष दवा वितरण कक्ष प्रसूति वार्ड टीकाकरण कक्ष रिकॉर्ड संधारण व्यवस्था एवं मरीज पंजीयन प्रणाली का भी अवलोकन किया गया। विधायक ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आवश्यक जीवनरक्षक दवाइयों का पर्याप्त भंडारण हमेशा उपलब्ध रहे तथा किसी भी मरीज को अनावश्यक रूप से बाहर से दवा खरीदने की स्थिति निर्मित ना हो। उन्होंने स्वास्थ्य स्टाफ को समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर उपचार देने, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल करने, नियमित टीकाकरण अभियान चलाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि शासन की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ पहुंचना चाहिए। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.परेश उपल्व एवं खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्यम शर्मा ने भी अस्पताल की वर्तमान व्यवस्थाओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं की जानकारी विधायक को दी। मेडिकल ऑफिसर डॉ.किरण बांसोड एवं डॉ. प्रिया बिसेन ने मरीजों की बढ़ती संख्या एवं संसाधनों की जरूरत पर चर्चा की।

भर्ती मरीजो से अच्छा व्यवहार करें चिकित्सक अन्यथा होगी कठोर कार्यवाही

वारासिवनी में बन रही १०० बिस्तरीय निर्माणाधीन बिल्डिंग का विधायक विवेक पटेल ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। और संबधित ठेकेदार को समय के पूर्व बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस बिल्डिंग का निर्माण ग्वालियर की मेसर्स पलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर परवेश उपलव, वारासिवनी बीएमओ सत्यम शर्मा, खैरलांजी बीएमओ खिलेंद्र पाल,सहायक यंत्री कमलेश मंडरा,सब इंजीनियर अंजू बिसेन, जीतू राजपूत, सुदेश गुड्डु सोनी मौजूद रहे।

भर्ती मरीजो के प्रति अपना व्यवहार सुधारे चिकित्सक

विधायक विवेक पटेल ओपीडी पहुंचे और रोजाना भर्ती मरीजो की संख्या के बारे में जानकारी ली और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजो से मिलकर उनका हालचाल जाना। और मरीजों को रही परेशानियों का समाधान करने अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं उन्होंने चिकित्सकों को निर्देशित किया वे भर्ती मरीजो के प्रति अपना व्यवहार ठीक रखे। हमेशा मुझे शोसल मीडिया से शिकायत मिलती रहती है अन्यथा वे कार्यवाही के लिए तैयार रहे।

शराब पीकर ड्यूटी के रहे डाक्टरों पर तत्काल सस्पेंड करने के दिए निर्देश

विधायक विवेक पटेल ने सीएमएचओ डॉक्टर परवेश उपलव को निर्देशित किया कि मुझे लगातार शराब पीकर ड्यूटी करने की शिकायत मिल रही है। जिससे हॉस्पिटल का माहौल खराब हो रहा है मरीज परेशान हो रहा है मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे शराब पीने वाले डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए है।

रात्रि में गार्ड रखा जाए-स्टाप नर्स

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपायली में मौजूद नर्स ने विधायक से कहा से रात्रि के समय भर्ती मरीजो के साथ वाले शराब के नशे में स्टाफ से अभद्र व्यवहार करते है। हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों को इस विषय में कई बार अवगत कराया गया था। मगर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। जल्द से जल्द रात्रि में एक गार्ड की ड्यूटी लगाई जाए जिससे हमें डियूटी करने में परेशानी ना हो।

राईस मिल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ऑपरेटर गंभीर रूप से झुलसा

मजदूरों की तत्परता से चैतराम की बची जान

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेहंदीवाड़ा के खापा मार्ग पर स्थित लक्ष्मी राइस मिल में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मिल में काम करने के दौरान अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण एक कर्मचारी करेंट और आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घायल कर्मचारी को तत्काल स्थानीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार जारी है।

मशीन का जाम खोलने गया था कर्मचारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार खापा निवासी चेतराम चौहान ४९ वर्ष पिछले लंबे समय से इस राइस मिल में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। रोज की तरह शुक्रवार सुबह करीब १० बजे वे मिल में अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। काम शुरू करने के लिए जब उन्होंने मिल की मशीनें चालू कीं तो पाया कि मैदा फेंकने वाली मशीन यानि साइक्लोन जाम थी। चेतराम जैसे ही उस मशीन की खराबी को दूर करने और उसे खोलने के लिए पास पहुंचे तभी अचानक वहां जोरदार शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण तेज करेंट फैला और वहां आग लग गई। इस अप्रत्याशित हादसे में चेतराम चौहान बुरी तरह झुलस गए।

मजदूरों और संचालक ने दिखाया तत्परता

घटना के वक्त मिल में काम कर रहे अन्य मजदूरों और मिल संचालक को जैसे ही हादसे की भनक लगी वे तुरंत मौके की ओर दौड़े। उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए झुलस रहे चेतराम को सुरक्षित बाहर निकाला और मिल के कार्यालय ऑफिस में बैठाया। इसके बाद तत्काल घटना की सूचना घायल के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल चेतराम को तुरंत वारासिवनी के सिविल अस्पताल लेकर आए । जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे में पीड़ित के हाथ पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और वे काफी झुलस गए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार जारी है।

राइस मिल वालों ने मुझे ऑफिस में बैठल दिया कहा कि सब ठीक हो जाएगा-चैतराम चौहान

घायल चैतराम चौहान ने बताया की मैं खापा रहता हूं लक्ष्मी राइस मिल में काम करता हूँ। कल मैं राइस मिल नहीं गया था तो मुझे जानकारी नहीं थी आज गया राइस मिल तो चालू करने के दौरान मैदा साइक्लोन जाम समझ आया। जिसे सुधारने के लिए उसके पास गया तो उसे खोलते समय अचानक शार्ट सर्किट हो गया मैंदे का जो तेल वहां रहता है उसमें आग भड़कने से मैं झुलस गया। अचानक यह घटना हुई जिससे आग लग गई यदि समय रहते मैं बाहर नहीं निकलता तो मैं जल जाता अस्पताल मुझे मेरा भतीजा लेकर आया हैं। राइस मिल वालों ने तो मुझे ऑफि स में बैठल दिया था कहा कि दो.चार घंटे बैठ सब ठीक हो जाएगा मेरे चेहरे हाथ पैर सहित विभिन्न स्थानों पर चोट आई है।

इनका कहना हैं

दूरभाष पर बताया की घायल चैतराम हमारे घर के सदस्य के जैसा हैं। घटना की तत्परता देखते हुए हमारे द्वारा उसे मौके से हटाया गया । उसे उपचार के लिए डॉक्टर चौधरी के अस्पताल में जाने के लिए कहा गया था कि हम उसका अच्छा उपचार कर सके। परंतु उसके परिजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल ले जाया गया है जहां मेरे भतीजे के द्वारा घायल से मुलाकात भी की गई है। हमारे द्वारा उसका बेहतर उपचार करने का प्रयास किया जा रहा है।

गुनेश कटरे
राईस मील संचालक

लंबित भुगतान को लेकर वारासिवनी की आशा कार्यकर्ताओं में आक्रोश

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा मेल समस्या का निराकरण करने की मांग

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। पिछले छह महीनों से मानदेय और विभिन्न कार्यों के भुगतान नही होने से नाराज आशा कार्यकर्ता संगठन वारासिवनी ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर सीधे देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को ईमेल के जरिए एक लिखित शिकायत भेजी है। इस शिकायत में उन्होंने परेशान करने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द लंबित भुगतान जारी करने की गुहार लगाई है।

जनवरी २०२६ से नहीं मिला मानदेय भुखमरी की कगार पर परिवार

शिकायत में आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। इसके बावजूद वर्ष २०२६ के शुरुआती महीने जनवरी से लेकर वर्तमान समय तक उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का भुगतान अटका हुआ है। पिछले छह महीनों से किसी भी आशा कार्यकर्ता को राशि नहीं मिली है। जब भी वे इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों से बात करते हैं तो उन्हें हर बार ऊपर से बजट आते ही भुगतान करने का रटा रटाया आश्वासन थमा दिया जाता है। छह महीने से खाली हाथ बैठी कार्यकर्ताओं के सामने अब अपने परिवारों के पालन पोषण और रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कार्यकर्ताओं का आक्रोश सिर्फ मौजूदा छह महीनों के भुगतान को लेकर नहीं है बल्कि विभाग पर उनका पुराना पैसा भी बकाया है।

शिकायत के अनुसार कोरोना काल के दौरान जान जोखिम में डालकर किए गए ऐतिहासिक कार्यों का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने और पल्स पोलियो जैसे राष्ट्रीय अभियानों में दिन रात एक करने के बाद भी आशा कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिला है। पूर्व के इन बकायों और वर्तमान के छह महीनों के लंबित भुगतान के कारण कार्यकर्ताओं में भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं को उनके हक का पैसा देने में नाकाम साबित हो रहा है वहीं दूसरी तरफ काम के लिए दबाव लगातार बनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भुगतान नही होने के बावजूद उन पर लगातार फील्ड में काम करने का दबाव डाला जाता है। यदि कोई कार्यकर्ता अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देती है तो जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उन्हें कार्य से हटाने या नौकरी से निकालने की सीधी चेतावनी दी जाती है। इस प्रशासनिक तानाशाही और धमकी के कारण कार्यकर्ता भय के साए में काम करने को मजबूर हैं। आशा कार्यकर्ता संगठन वारासिवनी ने शासन को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि उनकी जायज मांगों पर तत्परता से विचार नहीं किया गया और छह माह के लंबित भुगतान सहित पुराने बकायों का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो वे अपने अधिकारों के लिए आगे की रणनीति तय करेंगी।

काम करने के बाद भी राशि समय पर नहीं मिल रही है-देवकन पटले

आशा कार्यकर्ता देवकन पटले ने बताया कि हम लोग समय पर काम कर रहे हैं पर राशि समय पर नहीं मिल रही है। यह लोग काम की पूरी राशि भी नहीं देते हैं कोरोना काल का पैसा भी अभी तक नहीं दिया है। वर्तमान में गर्मी का दौर है लू चल रही है प्रशासन लोगों को घर में रहने के लिए बोल रहा है लेकिन हमें सर्वे करने बोल रहे हैं कि घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करो। अब यह हमारा पैसा नहीं देंगे तो हम खाएंगे क्या पालन पोषण कैसे करेंगे हर बार बजट की समस्या बताते हैं। जबकि दूसरे कर्मचारियों का वेतन देने के लिए उनके पास बजट हैं वारासिवनी में १४० आशा कार्यकर्ता है सभी के साथ यही स्थिति है।

शासन प्रशासन हमें काम करने कहते है ६ माह हो गया राशि नही दिये -गीता कटरे

आशा कार्यकर्ता गीता कटरे ने बताया कि हम लोगों का ६ माह से पैसा नहीं आया है आशा कार्यकर्ता जो काम करती है विवाह, जन्म, मृत्यु पंजी का सारा काम यह करवाते हैं। शासन प्रशासन हमें काम करने कहता है हम लोग करते भी है परंतु ६ माह हो गया है जनवरी से अभी तक आशा कार्यकर्ता का एक भी पैसा नहीं आया है। इसके पहले भी आशा कार्यकर्ता ने आयुष्मान कार्ड पल्स पोलियो में काम किया है उसका भी पैसा नहीं मिला है। यह काम करने के लिए बोलते हैं अन्यथा कााम से निकलने की बात करते हैं। अब हम अपने पैसे के लिए किसके पास बात रखेंगे इसके लिए हमने जिला चिकित्सा अधिकारी और जिला कलेक्टर दोनों को शिकायत दिए थे पर कुछ हुआ नहीं। अभी हमने प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार को मेल किया है। बहुत दिक्कत है हमारा घर कैसा चलेगा पालन पोषण कैसे होगा कई प्रकार की समस्याएं हर आशा कार्यकर्ता के साथ है।

नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पति गिरफ्तार भेजा गया जेल

मर्ग जांच में हुआ खुलासा दम घुटने और चोट के निशानों ने बयां की वारदात की हकीकत

पद्मेश न्यूज।वारासिवनी। नगर के वार्ड नंबर ८ चंदोरी में हुई नवविवाहिता अनेश्वरी सोनवाने की संदिग्ध मौत के मामले में वारासिवनी पुलिस ने बेहद त्वरित और कड़ी कानूनी कार्यवाही की है। मर्ग जांच घटना स्थल के सूक्ष्म निरीक्षण परिजनों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले को दहेज हत्या मानते हुए आरोपी पति राकेश सोनवाने को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।

मर्ग जांच और पीएम रिपोर्ट से खुला राज

घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एसडीओपी अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में थाना वारासिवनी के द्वारा मर्ग क्रमांक २४/२०२६ की बारीकी से जांच की गई। पुलिस टीम और एफएसएल विशेषज्ञों ने जब घटना स्थल का निरीक्षण किया तो मृतिका के घर के अंदर जगह जगह टूटी हुई चूडीयों के टुकड़े और फांसी के लिए उपयोग की गई साड़ी के कटे हुए हिस्से

बरामद हुए जो घटना के वक्त हुए गंभीर शारीरिक संघर्ष की बयां कर रहे थे। शासकीय अस्पताल वारासिवनी के डॉक्टरों की टीम के द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले की पूरी तस्वीर साफकर दी। शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मौत का कारण दम घुटने के साथ साथ उसकी ठुड्डी और सीने पर चोट के निशान होना पाया गया।

दहेज उत्पीड़न और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज

मृतिका के मायके पक्ष लेंडेझरी के परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही आरोपी राकेश सोनवाने के द्वारा मृतिका को प्रताड़ित किया जा रहा था। सामाजिक स्तर पर बैठकों के बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदला और उसने बेरहमी से मारपीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट घटना स्थल से जब्त साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध क्रमांक २२७/२०२६ भारतीय न्याय संहिता की धारा ८०,२ एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा ३,४ के तहत दहेज हत्या का संगीन मामला दर्ज किया।

आरोपी पति गिरफ्तार न्यायालय ने भेजा जेल

एसडीओपी अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी पति राकेश सोनवाने उम्र ३३ वर्ष निवासी वार्ड नं. ०८चंदोरी को गिरफ्तार कर न्यायालय वारासिवनी के समक्ष पेश किया गया जहाँ से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कार्यवाही में वारासिवनी पुलिस प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों की मुस्तैदी की नगरवासियों के द्वारा सराहना की जा रही है।

इनका कहना हैं

दूरभाष पर चर्चा में बताया कि ८ मई की यह घटना थी जिसमें नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। मामले में मौका स्थल की बारीकी से जांच करवाई गई थी पोस्टमार्टम करवाने के साथ परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए। बयान में दहेज के लेनदेन को लेकर प्रताड़ित करने की बात सामने आई थी। वहीं रिपोर्ट में भी आपसी संघर्ष उपरांत मृत्यु सिद्ध हुई जिसके आधार पर अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। मामले में अभी बारीकी से विवेचना कर और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

अभिषेक चौधरी
एसडीओपी वारासिवनी

जाति हटाओः अदालत और जाति की गिनती

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को रद्द करने के मामले में गलत नहीं है जिसमें जातिगत जनगणना ह्न जो अभी चल रही 'जनगणना 2027' का हिस्सा है – रोकने की मांग की गयी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जातिगत गिनती के समर्थन में टिप्पणी करते हुए कि, 卐आज किसी भी सरकार को यह पता होना चाहिए कि कितने लोग पिछड़े हैं और कितनों को कल्याण की जरूरत है 卐 अप्रैल 2025 में, नरेन्द्र मोदी सरकार ने एकदम से दिशा बदलते हुए ताजा जनगणना के साथ जाति गणना का एलान किया। यह 1931 के बाद ऐसी पहली गणना होगी। मोदी ने इससे पहले इस विचार को 卐अर्बन नक्सल卐 सोच की निशानी बताकर इसकी खिल्ली उड़ायी थी और आरएसएस ने आगाह किया था कि ऐसे सर्वेक्षण हिंदू समाज को खंडित करने की कोशिशें हैं। कांग्रेस ने भी अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को नाटकीय ढंग से बदलते हुए जातिगत जनगणना की मांग की थी। आजाद भारत की शुरुआती सरकारों ने जनगणना के साथ जाति गणना नहीं कराने का निर्णय लिया। तब प्रबल सोच यह थी कि जातीय समुदायों की गिनती कराने से वह जाति संस्था और मजबूत होगी जिसे राज्य छिन्न-भिन्न करना चाहता था। एक तरफ, राज्य की नीतियों ने एक जातिविहीन समाज के निर्माण की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ, विधायी प्रतिनिधित्व और रोजगार में सकारात्मक भेदभाव के लिए जातीय पहचानों को भी ध्यान में रखा। राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों में रचे-बसे, जाति को लेकर इस दोहरे दृष्टिकोण ने एक ऐसा विरोधाभास निर्मित किया है जो आज तक कायम है। जातिगत जनगणना कराने के लिए हो-हल्ला इसका ताजातरीन प्रकटीकरण है।

खुद जनगणना काफी विलंब हो चुकी है। हर दस वर्ष पर होने वाला यह जनसंख्या सर्वेक्षण साल 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी और प्रबंध संबंधी बाधाओं के कारण इसमें देर हुई। जाति गणना दूसरे चरण में की जायेगी और इसमें हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जायेगी। पूर्व की जनगणनाओं की तरह, इतना भर दर्ज नहीं किया जायेगा कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं या नहीं। जनगणना में देरी का असर सभी तरह की योजनाएं बनाने पर पड़ता है। भारत में, राज्य की नीतियों का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लक्षित समूह के जातीय प्रोफाइल से जुड़ा होता है। आजादी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गिनती की एक कोशिश साल 2011 में हुई। इस सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की ओपेन-एंडेड जातीय पहचान प्रक्रिया के फलस्वरूप जातियों के 46 लाख अलग-अलग नाम और 8 करोड़ डेटा त्रुटियां सामने आयीं, जिसने पूरे डेटासेट को इस्तेमाल के अयोग्य बना दिया। इसके ज्यादातर निष्कर्ष अब भी अप्रकाशित हैं। मोदी सरकार जातीय समुदायों की सटीक गिनती के लिए उपयुक्त तरीका तलाशने की चुनौती से अब भी जूझ रही है। जातिगत जनगणना जाति उन्मूलन के प्रयासों को धूमिल करती है क्योंकि यह पहचानों को और सख्त बनाती है। लेकिन अन्य सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के साथ देखने पर यह कल्याणकारी उपायों को बेहतर ढंग से लक्षित करने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मददगार है। जाति के खात्मे को एक लक्ष्य बनाये रखना होगा और लोगों को इस बात की इजाजत देनी होगी कि वे अगर चाहें तो खुद को जातिविहीन की श्रेणी में रख सकें।

जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक मुहर

वैश्विक स्तरपर भारत में वर्षों से चल रही जातिगत जनगणना की बहस को बुधवार 20 मई 2026 को एक निर्णायक मोड़ तब मिला, जब भारतीय सुप्रीमकोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले ने केवल एक कानूनी विवाद का अंत नहीं किया,बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि भारत में होने वाली जनगणना 2027 पूरी तरह संवैधानिक,कानूनी और नीतिगत अधिकारों केदायरे में संचालित की जा रही है। बता दें इसके पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 अप्रैल, 2026) को केंद्र को जाति जनगणना रोकने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दियाथा और जनहित याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए याचिकाकर्ता की कड़ी आलोचना की। पिछले कुछ महीनों से जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर तीखी बहस चल रही थी। कुछ वर्ग इसे सामाजिक न्याय का आधार बता रहे थे, जबकि विरोधी पक्ष इसे सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाला कदम कह रहा था। किंतु सर्वोच्च अदालत के ताजा निर्णय ने यह स्थापित कर दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को यह अधिकार है कि वह देश की सामाजिक संरचना, विशेषकर पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और स्थिति को समझने के लिए डेटा एकत्र करे, ताकि उसके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत की जनगणना 2027 केवल एक पारंपरिक जनगणना नहीं मानी जा रही,बल्कि इसे डिजिटल इंडिया और डेटा-आधारित गवर्नेंस के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक माना जा रहा है। लगभग डेढ़ सौ वर्षों से चली आ रही जनगणना व्यवस्था अब तकनीकी रूप से आधुनिक स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है।

साथियों इस बार की जनगणना दो बड़े चरणों में आयोजित की जा रही है।पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ,जिसमें हाउस लिस्टिंग और आवासीय गणना की प्रक्रिया अपनाई गई। 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक चले इस चरण में देशभर के घरों,संपत्तियों,भवनों, आवासीय सुविधाओं, जल स्रोतों, बिजली, इंटरनेट, शौचालय, रसोई, वाहन और सामाजिक- आर्थिक आधारभूत संरचनाओं से संबंधित डेटा संकलित किया गया।यह चरण केवल जनसंख्या गिनने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह देश की जीवन- स्थितियों का व्यापक सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण भी बन गया।जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में प्रारंभ होगा, जिसमें प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों की विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, टैबलेट आधारित डेटा एंट्री, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों को अब सामाजिक न्याय और संसाधन वितरण के दृष्टिकोण से सटीक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि जातिगत जनगणना करना या न करना सरकार का नीतिगत अधिकार है।अदालत ने कहाकि जब तक कोई नीति संविधान या कानून का उल्लंघन नहीं करती, तब तक न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत की यह टिप्पणी भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी मजबूती देती है, जहां नीति निर्माण कार्यपालिका का क्षेत्र माना जाता है और न्यायपालिका केवल वैधानिकता की समीक्षा करती है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक रूप से वंचित समूहों की वास्तविक संख्या कितनी है,ताकिउनके लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जाति आधारित गणना अपने आप में असंवैधानिक नहीं है।यदि सरकार सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंकड़े जुटाना चाहती है, तो यह उसका वैध प्रशासनिक अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी नीति के संभावित दुरुपयोग की आशंका मात्र से उसे रोका नहीं जा सकता। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यही था कि जातिगत आंकड़ों का राजनीतिक और सामाजिक दुरुपयोग हो सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त सामाजिक डेटा उपलब्ध है, इसलिए अलग से जातिगत गणना की आवश्यकता नहीं है। किंतु अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि सरकार को समकालीन और प्रमाणिक आंकड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुराने डेटा के आधार पर प्रभावी नीति निर्माण सटीक रूप से संभव नहीं है। साथियों, यह फैसला सामाजिक न्याय की राजनीति और प्रशासनिक नीति दोनों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक आधार क्या होना चाहिए। अनेक विशेषज्ञों का मानना रहा है कि बिना अद्यतन जातिगत आंकड़ों के सामाजिक न्याय की नीतियां अधूरी रहती हैं। स्वतंत्र भारत में 1931 के बाद व्यापक स्तर पर जातिगत आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे, जिसके कारण पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और उनकी सामाजिक- आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार विवाद बना रहा। ऐसे में जनगणना 2027 को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की सामाजिक संरचना का वास्तविक चित्र सामने ला सकती है। साथियों, राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। कई राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण और सामाजिक गणना पहले ही राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुके हैं। बिहार, कर्नाटक और अन्य राज्यों में किए गए जातीय सर्वेक्षणों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस को और तेज किया। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की दिशा में आगे बढ़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भविष्य की नीतियां अधिक डेटा-आधारित और लक्ष्य केंद्रित होंगी। इससे यह भी संभावना बढ़ेगी कि सामाजिक योजनाओं में संसाधनों का वितरण वास्तविक जनसंख्या अनुपात और जरूरतों के आधार पर किया जा सके। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 11 अप्रैल 2026 को भी ऐसी ही एक याचिका को खारिज किया था, जिसमें केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उस समय अदालत ने याचिका में प्रयुक्त भाषा पर भी कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत का यह लगातार रुख स्पष्ट करता है कि वह जनगणना जैसे प्रशासनिक और नीतिगत विषयों में अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप से बचना चाहती है। इससे यह संदेश भी गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नीति निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाचित सरकारों की होती है।जातिगत जनगणना के समर्थकों का तर्क है कि भारत जैसे बहुस्तरीय सामाजिक ढांचे वाले देश में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक आंकड़े अत्यंत आवश्यक हैं। यदि सरकार को यह ज्ञात ही नहीं होगा कि किस समुदाय की आबादी कितनी है, उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति कैसी है, तो योजनाओं का सही लक्ष्य निर्धारण संभव नहीं होगा। यही कारण है कि अदालत ने भी सरकार की इस आवश्यकता को स्वीकार किया कि पिछड़े वर्गों की संख्या और स्थिति जानना शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है।दूसरी ओर, विरोधियों की आशंका यह रही है कि जातिगत पहचान को फिर से केंद्र में लाने से सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। उनका मानना है कि आधुनिक भारत को जाति से ऊपर उठकर आर्थिक और मानव विकास के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि सरकार और अदालत दोनों ने यह स्पष्ट किया कि आंकड़े जुटाना और उनका दुरुपयोग करना दो अलग बातें हैं। यदि किसी नीति का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार है, तो केवल संभावित राजनीतिक उपयोग के आधार पर उसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। साथियों, जनगणना 2027 की डिजिटल प्रकृति भी इसे ऐतिहासिक बना रही है। पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है। डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की गई है। इससे फर्जी या दोहराव वाले आंकड़ों को कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत की प्रशासनिक क्षमता और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की बड़ी परीक्षा भी होगी। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की यह पहल ध्यान आकर्षित कर रही है। दुनिया के कई देशों में जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर सामाजिक नीतियां बनाई जाती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देशों में नस्ल, जातीयता और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े आंकड़े नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में जातिगत जनगणना को उसी व्यापक वैश्विक संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां डेटा आधारित सामाजिक नीति को लोकतांत्रिक शासन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक याचिका खारिज करने तक सीमित नहीं है। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय की अवधारणा और डेटा-आधारित शासन प्रणाली के भविष्य को दिशा देने वाला निर्णय माना जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि जनगणना 2027 अब कानूनी और संवैधानिक रूप से मजबूत आधार पर आगे बढ़ेगी। सरकार को न केवल प्रशासनिक समर्थन मिला है, बल्कि न्यायपालिका की ओर से भी यह संकेत मिला है कि सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाना लोकतांत्रिक शासन का वैध हिस्सा है। आने वाले वर्षों में यह जनगणना भारत की सामाजिक संरचना, राजनीतिक विमर्श और आर्थिक नीतियों को गहराई से प्रभावित कर सकती है।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

वकीलों पर लाठी नहीं लोकतंत्र पर प्रहार

-कांतिलाल मांडोत

लखनऊ जिला अदालत परिसर के बाहर जो कुछ हुआ वह केवल अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की एक गंभीर परीक्षा थी। अदालतों में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ उसने पूरे न्यायिक तंत्र को झकझोर दिया है। पुलिस और प्रशासन की यह कार्रवाई केवल चैंबर तोड़ने तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने उस संवैधानिक गरिमा को भी आहत किया जिस पर भारतीय लोकतंत्र टिका हुआ है।

घटना की शुरुआत हाईकोर्ट के आदेश के पालन के नाम पर हुई। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर लेकर अदालत परिसर के

बाहर पहुंची और कथित अवैध निर्माण हटाने लगी। जिन चैंबरों में वर्षों से वकील अपने पेशे का संचालन कर रहे थे उन्हें अचानक ढहाया जाने लगा। कई अधिवक्ताओं का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय और स्पष्ट सूचना तक नहीं दी गई। जिन लोगों ने जीवन के कई दशक अदालत परिसर में बिताए उनके सामने अचानक रोजी रोटी और सम्मान दोनों पर संकट खड़ा हो गया।

विरोध होना स्वाभाविक था। वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। कुछ सड़क पर बैठ गए। कुछ हाथ जोड़कर अपने चैंबर बचाने की गुहार लगाते रहे। लेकिन प्रशासन ने संवाद और समाधान का रास्ता चुनने के बजाय शक्ति प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की में बदली और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जिस समाज में वकील संविधान और कानून के रक्षक माने जाते हैं उसी समाज में उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर पीटना बेहद चिंताजनक दृश्य था।

सबसे दुखद पहलू यह रहा कि पुलिस की कार्रवाई में संवेदनशीलता लगभग दिखाई नहीं दी। एक अधिवक्ता ने आत्महत्या की धमकी दी। दूसरे अधिवक्ता रोते हुए कह रहे थे कि उनका चैंबर अवैध नहीं है और यदि उसे तोड़ा गया तो वे जीवित नहीं रहेंगे। इन आवाजों में केवल विरोध नहीं था बल्कि वर्षों की मेहनत और असुरक्षा का दर्द भी था। प्रशासन यदि चाहता तो बातचीत कर स्थिति संभाल सकता था। लेकिन जब राज्य की मशीनरी संवाद के स्थान पर डंडे को प्राथमिकता देती है तब हालात हिंसक बन जाते हैं।

इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या बुलडोजर अब प्रशासनिक कार्रवाई का स्थायी प्रतीक बन चुका है। कानून का शासन केवल कार्रवाई से नहीं बल्कि न्यायपूर्ण प्रक्रिया से चलता है। यदि किसी निर्माण को अवैध माना गया था तो उसके लिए स्पष्ट नोटिस पुनर्वास और सम्मानजनक विकल्प देने चाहिए थे। अदालत परिसर में दशकों से बैठे अधिवक्ताओं को अचानक अपराधियों की तरह खदेड़ना किसी सभ्य व्यवस्था का संकेत नहीं हो सकता।

घटना के दौरान पथराव भी हुआ जो निंदनीय है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा समाधान नहीं हो सकती। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब प्रशासन संयम खो देता है तो भीड़ भी उग्र हो जाती है। पुलिस का दायित्व केवल बल प्रयोग करना नहीं बल्कि स्थिति को नियंत्रित रखना भी होता है। यदि पुलिसकर्मी स्वयं पत्थर उठाते दिखाई दें तो यह कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। जनता पुलिस से निष्पक्षता और संयम की अपेक्षा करती है न कि प्रतिशोध की।

वकीलों पर लाठीचार्ज का असर केवल बार एसोसिएशन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव आम जनता के न्यायिक विश्वास पर भी पड़ेगा। वकील अदालत और समाज के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि वही अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे तो न्याय व्यवस्था का वातावरण भी प्रभावित होगा। अदालत परिसर हमेशा गरिमा और संवाद का स्थान माना जाता रहा है। वहां हिंसा और टकराव लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को कमजोर करते हैं।

यह भी विचारणीय है कि प्रशासनिक कार्रवाई में समानता दिखाई दी या नहीं। कई अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ अन्य निर्माणों को छोड़ दिया गया जबकि केवल चुनिंदा चैंबरों पर कार्रवाई हुई। यदि ऐसा है तो यह और गंभीर विषय है क्योंकि कानून की नजर में सब समान होने चाहिए। चयनात्मक कार्रवाई हमेशा अविश्वास और आक्रोश को जन्म देती है।

सरकार और प्रशासन को समझना होगा कि कानून का पालन केवल शक्ति से नहीं कराया जा सकता। संवेदनशील मामलों में संवाद धैर्य और मानवीय दृष्टिकोण अधिक प्रभावी होते हैं। अधिवक्ताओं के साथ बैठकर समाधान निकाला जा सकता था। पुनर्वास की स्पष्ट योजना बनाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरह बुलडोजर और पुलिस बल के सहारे कार्रवाई की गई उसने पूरे मामले को संघर्ष में बदल दिया।

लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं होती। विरोध को सुनना और उसका सम्मान करना शासन की जिम्मेदारी है। यदि हर विरोध का उत्तर लाठी से दिया जाएगा तो समाज में भय और अविश्वास ही बढ़ेगा। पुलिस की भूमिका जनता की सुरक्षा करना है न कि उन्हें अपमानित करना। अदालत परिसर में हुई यह घटना प्रशासनिक असंवेदनशीलता का उदाहरण बन गई है।

आज जरूरत इस बात की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। यह तय होना चाहिए कि लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई। किसके आदेश पर बल प्रयोग हुआ। क्या वैकल्पिक उपाय संभव थे। साथ ही घायल अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों दोनों के प्रति संवेदना दिखाते हुए समाधान खोजा जाना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत संवाद में होती है दमन में नहीं।

लखनऊ की यह घटना केवल एक शहर का विवाद नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। यदि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग ही सड़कों पर असुरक्षित महसूस करने लगें तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। कानून की रक्षा करने वालों के साथ कानूनसम्मत व्यवहार होना ही चाहिए। तभी जनता का विश्वास व्यवस्था में बना रहेगा।

राजनीति सनातन विरोध की बजाय आममुद्दों पर केंद्रित हो

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसा विमर्श लगातार उभर रहा है, जिसने राजनीतिक बहस को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मूल प्रश्नों से हटाकर धार्मिक पहचान और आस्था के इर्द-गिर्द खड़ा कर दिया है। यह विमर्श है-सनातन समर्थन बनाम सनातन विरोध। आज देश में एक ओर सनातन संस्कृति को भारतीय जीवन का शाश्वत आधार मानने वाली शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर कुछ राजनीतिक वक्तव्य और प्रवृत्तियां ऐसी दिखती हैं जिन्हें जनमानस सनातन विरोध के रूप में देखता है। प्रश्न यह नहीं कि किसी विचारधारा से सहमति या असहमति क्यों है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या राजनीति का केंद्र धर्म होना चाहिए या जनजीवन के वास्तविक मुद्दे? भारत का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष संविधान पर आधारित है, जहां राज्य का कार्य किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजनीतिक दलों का दायित्व भी यही होना चाहिए कि वे जनता की समस्याओं, विकास और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक विमर्श राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है।

सनातन केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना, जीवन-दर्शन और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। सत्यं वद, धर्मं चर, वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सूत्र इसी सनातन दृष्टि के अंग हैं। इसलिए जब कोई राजनीतिक वक्तव्य सनातन को लेकर अपमानजनक या आक्रामक भाषा का उपयोग करता है, तो उसका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। तमिलनाडु में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने वाला वक्तव्य इसी कारण व्यापक विवाद का कारण बना। विपक्ष के अनेक दलों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत जैसे देश में करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला कथन राजनीतिक रूप से भी असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। यहां यह समझना आवश्यक है कि द्रविड आंदोलन की अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। उसका मूल संघर्ष सामाजिक विषमताओं और जातीय वर्चस्व के विरुद्ध था। लेकिन जब सामाजिक सुधार का विमर्श पूरे धर्म या संस्कृति के विरोध जैसा प्रतीत होने लगे, तब वह जनस्वीकृति खो देता है।

यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। स्वयं भारतीय दर्शन में भी संवाद, बहस और आत्मचिंतन की परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दयानंद और गांधी-सभी ने समाज की विसंगतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने समाज को तोड़ने नहीं, सुधारने का मार्ग चुना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक भाषा संतुलन खो देती है। जब आलोचना सुधार की जगह अस्वीकार की भाषा बन जाती है, तब वह समाज में ध्रुवीकरण को जन्म देती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं कही जा सकती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विमर्श अधिक प्रभावी होकर उभरा है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान जैसे विषयों ने एक बड़े वर्ग में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिला। दूसरी ओर विपक्षी दल इस बदलते राजनीतिक मानस को समझने में कई बार असहज दिखाई दिए। कहीं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आस्था के बीच संतुलन बनाने में चूक की, तो कहीं उनके कुछ नेताओं के बयान उन्हें कठिन स्थिति में ले आए। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी राजनीति में यह देखा गया कि केवल जातीय समीकरण या पारंपरिक वोट बैंक अब पर्याप्त नहीं हैं। जनता सांस्कृतिक पहचान, विकास और राष्ट्रीय विमर्श को भी महत्व देने लगी है। ऐसे में यदि कोई दल हिंदू आस्था के प्रति असंवेदनशील दिखता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे विमर्श का दूसरा पक्ष भी है। क्या राजनीति का उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान के आधार पर समर्थन जुटाना होना चाहिए? क्या देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि संकट, आर्थिक असमानता और सामाजिक विघटन जैसे प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए? यह चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धर्म, विशेषकर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमूक आदि विपक्षी दलों एवं उनके कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को व्यापक जनसमुदाय ने सनातन पर आक्षेप या हिंदू भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता के रूप में देखा, जिसके राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दिए। किंतु इस विषय को केवल हिंदू विरोध बनाम राजनीतिक विरोध के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राष्ट्र है, जहां किसी भी राजनीतिक दल को सरकार, नीतियों या नेतृत्व का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यदि वह विरोध आस्था, संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से टकराता हुआ प्रतीत हो, तो उसका राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई दलों के लिए यह धारणा चुनौती बनी कि वे सत्ता-विरोध की राजनीति करते-करते सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं से दूर हो गए हैं। भारत में सनातन केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन, परंपरा, संस्कृति, सहिष्णुता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति असावधान भाषा या नकारात्मक संकेत जनमानस में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करते रहे हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यह भी अपेक्षा करती है कि राजनीतिक विमर्श व्यक्तियों, नीतियों और शासन के मुद्दों पर केंद्रित रहे, न कि धार्मिक ध्रूवीकरण पर। राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि वे मतभेद रखें, आलोचना करें, लेकिन भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक संवेदनशीलता और आस्था के सम्मान का संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जनता अंततः उसी नेतृत्व को स्वीकार करती है जो उसकी भावनाओं, परंपराओं और राष्ट्रीय मानस को समझने का प्रयास करता है।

भारत की राजनीति को धर्म बनाम धर्म की लड़ाई से ऊपर उठकर जन बनाम जनसमस्या के विमर्श की ओर ब?ना होगा। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता मंदिर भी चाहती है और रोजगार भी, आस्था भी चाहती है और अवसर भी, संस्कृति भी चाहती है और आधुनिकता भी। केवल धार्मिक ध्रुवीकरण किसी राष्ट्र की स्थायी प्रगति का आधार नहीं बन सकता। आज आवश्यकता है कि राजनीतिक दल सनातन विरोध या हिंदू विरोध जैसे आरोप-प्रत्यारोपों को राजनीति से बाहर निकलें। यदि किसी परंपरा में सुधार की बात करनी है, तो वह सम्मानजनक भाषा और रचनात्मक दृष्टि से हो। सामाजिक न्याय का अर्थ सांस्कृतिक अस्वीकार नहीं होना चाहिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ अन्य दृष्टियों का निषेध भी नहीं होना चाहिए। भारतीय सभ्यता की शक्ति उसकी विविधता और सहिष्णुता रही है। यहां शंकराचार्य भी हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, कबीर भी हैं, वेद भी हैं और संविधान भी। भारत ने सदैव संवाद को संघर्ष से ऊपर रखा है। इसलिए राजनीति का भी दायित्व है कि वह समाज को जोड़ने वाली भाषा बोले। आज जब विश्व संघर्षों, सांस्कृतिक तनावों और पहचान की राजनीति से जूझ रहा है, तब भारत के पास वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश है। यही सनातन का वास्तविक स्वरूप भी है-समावेश, करुणा और सहअस्तित्व।

राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना होगा कि वे जनता को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं-धार्मिक टकराव की ओर या राष्ट्रीय निर्माण की ओर? यदि राजनीति केवल आस्था के विवादों में उलझी रही, तो जनजीवन के वास्तविक प्रश्न पीछे छूट जाएंगे। लेकिन यदि राजनीति संस्कृति का सम्मान करते हुए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता को केंद्र बनाएगी, तो भारत एक संतुलित और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। सनातन का अर्थ शाश्वत है, और शाश्वत वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। इसलिए किसी भी प्रकार का अंध-विरोध या अंध-समर्थन समाधान नहीं हो सकता। आवश्यकता है विवेकपूर्ण दृष्टि, संतुलित राजनीति और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की। भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है कि वह आस्था का सम्मान करे, लेकिन राजनीति को जनहित का माध्यम बनाए। तभी लोकतंत्र भी मजबूत होगा और समाज भी समरस बनेगा।

-ललित गर्ग

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। कमजोर आवकों के चलते शुक्रवार को तिलहनों में सरसो बाजार बढ़त पर रहे। खाद्य तेलों में मजबूती कायम रही। दलहनों में चना 6100-6125 रू. प्रति क्विंटल पर मजबूत देखा गया। किराना जिंसों में जीरा सुर्खी पर रहा। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार सरसो में माँग का सीजन है। कमजोर आवकों के बीच बाजार तेजी के रहे। सरसो आज 8000-8300 रू. प्रति क्विंटल पर आ गयी। खाद्य तेलों में मजबूती देखी गयी। दलहनों में 6100-6125 रू. प्रति क्विंटल पर मजबूत देखा गया। उधर, किराना जिंसों में जीरा सुर्ख रहा। दिसावरी तेजी से जीरे में तेजी है। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शकर 4220-4270, खोपरा गोला 375-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 120-150, बेस्ट 275-350, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 740-745, मीनी मटरदाना 770-785, मटरदाना 800-815, खसखस अनक्लीन 800-950, क्लीन 1050-1400, दालचीनी 245-260, जायफल 815-880, वाधान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 2050-2100, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाड़ा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची एवरेज 1675-1775, बेस्ट 1925-2350, पानबार 1550-1600, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 500-625, काजू (240) 920-950, काजू (320) 830-880, काजू डब्ल्यू (300) 790-810, काजू जे.एच. 820-840, टुकड़ी 760-800, बादाम मगज 760-800, अमेरिकन 825-950, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 850-1000, बेस्ट 1150-1350, अंजीर 851-1075, मखाना 850-1200, बेस्ट 1350-1400, खारक एवरेज 75-80, मीडि?यम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 2200-2250, (160) 2500-2550, (200) 2300-2350, (250) 2600-2650

तेल- सींगदाना 1620-1640, मुम्बई 1650, राजकोट तेलिया 2550, सोया साल्वेंट 1445-1450, सोया रिफाइंड 1500-1510, कपास्या 1500-1510, धूलिया 1510, कड़ी 1510,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1600-1610, मुम्बई पाम 1530, मुम्बई सोया 1550,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2525, देवास-उज्जैन 2525, खंडवा-बुरहानपुर 2500, अकोला 3900 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 8000-8300, रायडा 6800-7200, सोयाबीन 7200-7400, टोली (महुआ बीज) 4400-4600, करंज 4400-4500, अलसी 6800-7000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6100-6125, एवरेज 5600-5700, विशाल 6000-6050, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7600-8700, काबूली चना रशि?यन 5400-5700, बिटकी 5000-5300, मसूर बेस्ट 6100-6200, एवरेज 6000-6050, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7700-7800, मूंग पुराना बोल्ड 8500-8800, मीडियम 7800-7900, एवरेज 7000-7400, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7700-7800, एवरेज 7200-7300, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7500-7600, उड़द बेस्ट 8500-9000, एवरेज 7000-8000, हल्की 4000-6000,

दाल- चना दाल एवरेज 7000-7200, मीडि?यम 7300-7400, बोल्ड 7600-7800, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल फूल 9400-10000, तुअर दाल बोल्ड 10600-11700, मसूर दाल एवरेज 7900-8000, बेस्ट 8000-8100, मूंग दाल 9500-9700, बोल्ड 9900-10500, मूंग मोगर 10500-10700, बोल्ड 10900-11100, उड़द दाल 9800-10000, बोल्ड 10400-10500, मोगर 10600-10800, बोल्ड 11000-11400,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2525, लोकवन एवरेज 2550-2600, बेस्ट 2700-3000, मालवराज 2450-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 2000-2025, बेस्ट 1850-1900,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000, बासमती दुबार 9500-10000, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11500, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 280 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। शुक्रवार को स्थानीय सराफा बाजार में व्यापार की मात्रा कम ही रही। दोनों ही मूल्यवान धातुओं में बाजार बने रहे। भाव इस प्रकार रहे-

चाँदी (9999) 259000, चाँदी (99) 258800, टंच 258100, सिक्का 2800, सोना 10 ग्राम 151900,

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई। एजेंसी। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की तेजी के साथ ही 95.96 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह शुरुआती कारोबार में रुपयास 18 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.18 पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में मामूली नरमी, भू-राजनीतिक तनाव में कमी के शुरुआती संकेतों और रिजर्व बैंक के सक्रिय हस्तक्षेप से घरेलू मुद्रा को थोड़ा समर्थन मिला है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.30 पर खुला और शुरुआती कारोबार में 96.18 तक पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे अधिक था। रुपया गुरुवार को 50 पैसे की बढ़त के साथ 96.36 पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई। एजेंसी। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बाद भी बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में खरीदारी हावी होने से आई है। इसके अलावा रुपये में आई मजबूती से भी बाजार को बल मिला है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 231.99 अंक बढ़कर 75,415.35 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 64.60 अंक उछलकर 23,719.30 अंक पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, कोटक बैंक और बजाज फिनसर्व में एक फीसदी से अधिक तेजी आई। दूसरी ओर आईटीसी, पावरग्रिड, बीईएल, भारती एयरटेल, इन्फोसिस के शेयर गिरे हैं। निफ्टी के शेयरों में श्रीराम फाइनेंस और एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा तेजी रही।

ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिडकैप 0.14 फीसदी उछला जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.15 फीसदी गिरा। निजी निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक में तेजी रही जबकि निफ्टी फार्मा,निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी मीडिया के शेयर टूटे। इससे पहले आज सुबह निफ्टी 127.40 अंक चढ़कर 23,786.65 पर पहुंच गया। वहीं, बीएसई सेंसेक्स 488.97 अंक उछलकर 75,681.20 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। हालांकि, मुख्य सूचकांकों में बढ़त के बावजूद, बाजार के व्यापक हिस्से में कमजोरी का माहौल देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.13 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.08 फीसदी की गिरावट रही। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ताओं पर निवेशकों की करीबी नजर है, खासकर ऐसी रिपोर्ट्स के बाद कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को देश के भीतर ही रखने की योजना बना रहा है। यह स्थिति परमाणु समझौते को लेकर चल रही बातचीत को जटिल बना सकती है और वैश्विक तेल कीमतों तथा बाजार की धारणा पर असर डाल सकती है।

डीजल मूल्य अंतर ने बढ़ाई परेशानी, थोक खरीदार खुदरा पंपों पर उमड़े

नई दिल्ली। एजेंसी। देश के कुछ पेट्रोल पंपों पर डीजल की संभावित कमी की खबरों के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह स्थिति घबराहट में खरीद और थोक व खुदरा डीजल कीमतों में भारी अंतर के कारण उत्पन्न हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में एक अधिकारी ने बताया कि थोक खरीदार अब खुदरा पंपों का रुख कर रहे हैं, जिससे कुछ ईंधन खुदरा दुकानों पर मांग में लगभग 20-30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में थोक डीजल की कीमत लगभग 149 रुपये प्रति लीटर है, जबकि खुदरा डीजल की दर 91.58 रुपये प्रति लीटर है, जो 40-42 रुपए प्रति लीटर का एक बड़ा अंतर है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 1 मई को कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद थोक डीजल की कीमतों में 12 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी, जबकि खुदरा डीजल की कीमतें पिछले सप्ताह में केवल लगभग 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों में आमतौर पर दो से तीन दिनों का स्टॉक होता है, और मांग में 20-30 प्रतिशत की अचानक वृद्धि से उन्हें अस्थायी रूप से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ऐसे स्थानों की लगातार निगरानी की जा रही है और उन्हें नियमित रूप से फिर से भरा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य परिवहन निगमों, कारखानों और दूरसंचार टॉवर ऑपरेटरों जैसे थोक डीजल खरीदारों को अपनी जरूरतों के लिए सीधे तेल कंपनियों के थोक आपूर्ति केंद्रों से खरीदारी करनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि देश की रिफाइनरियां पर्याप्त ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी क्षमता से चल रही हैं। हाल के हफ्तों में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर संभावित कमी के कारण लंबी कतारें देखी गई थीं।

भारत के असंगठित क्षेत्र में रोजगार पहली बार 15 करोड़ के पार

नई दिल्ली। एजेंसी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी तिमाही बुलेटिन के अनुसार, भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार ने जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में पहली बार 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यह पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 15.51 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है, जो 13.13 करोड़ से बढ़कर 15.17 करोड़ हो गया है। एनएसओ ने इस वृद्धि को क्षेत्र में स्वस्थ श्रम बाजार और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए रोजगार के प्रमुख स्रोत के रूप में बताया है। एनएसओ के तिमाही बुलेटिन के मुताबिक अनुमानित प्रतिष्ठानों की संख्या 16.7 प्रतिशत बढ़कर 9.16 करोड़ हो गई। यह विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मजबूत रहा, जहां प्रतिष्ठानों में सालाना 20.46 प्रतिशत और रोजगार में 21.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो शहरी क्षेत्रों (क्रमश: 12.59 और 10.39 फीसदी) की तुलना में काफी अधिक है। सेवा क्षेत्र इस वृद्धि का मुख्य चालक रहा, जहां प्रतिष्ठानों में 24.82 प्रतिशत और रोजगार में 31.13 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे यह असंगठित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता खंड बन गया। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में 10 फीसदी की वृद्धि देखी गई, जबकि व्यापार क्षेत्र में 2.2 फीसदी की वृद्धि हुई। कुल कार्यबल में वर्किंग ओनर्स का दबदबा रहा, जिनकी हिस्सेदारी बढ़कर 60.97 फीसदी हो गई। महिला श्रमिकों का इस क्षेत्र के कुल रोजगार में लगभग 29 फीसदी योगदान रहा। डिजिटल अपनाने में भी तेजी देखी गई, जहां 81 प्रतिशत प्रतिष्ठानों ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग किया और समान प्रतिशत ने कैशलेस लेनदेन को अपनाया। इसके अतिरिक्त, औपचारिकता की दिशा में भी प्रगति हुई है, पंजीकृत प्रतिष्ठानों का हिस्सा एक साल पहले के 36.2 फीसदी से बढ़कर 41.37 फीसदी हो गया है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती संरचनात्मक मजबूती को दर्शाता है।

आज का राशिफल

मेष- आज आपका मान-सम्मान और प्रभाव दोनों बढ़ने वाले हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की छवि और मजबूत होगी। हालांकि किसी की बात दिल पर लेना आपको परेशान कर सकता है। मनमौजी स्वभाव के कारण छोटी बात बड़ी बन सकती है, इसलिए धैर्य रखें। माताजी की सेहत, खासकर पैरों से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें। कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी।

वृषभ- आज संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में किस्मत आपका साथ दे सकती है। कई काम एक साथ आने से व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का सपना पूरा हो सकता है। बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने से मन खुश रहेगा। किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कानूनी मामलों में थोड़ी भी लापरवाही आगे परेशानी बढ़ा सकती है।

मिथुन- आज आपका नाम समाजसेवा और अच्छे कार्यों से चमक सकता है। आपकी नई कोशिशें रंग लाएंगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। मन मौज-मस्ती में रहेगा, जिससे काम टालने का मन करेगा। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी रुकावट दूर करने में किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है।

कर्क- आज का दिन सकारात्मक रहेगा, लेकिन मन किसी बात को लेकर बेचैन रह सकता है। भाई-बहनों के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में कोई आप पर गलत आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए समझदारी से अपनी बात रखें। संतान की सफलता आपको गर्व महसूस कराएगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, लेकिन पेट से जुड़ी दिक्कतों से सावधान रहें।

सिंह- आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। पड़ोस या आसपास के विवादों से दूरी बनाकर रखें। पुराने लेनदेन की उलझन सुलझ सकती है। अपने कामों की जिम्मेदारी खुद उठाएं और दूसरों पर ज्यादा निर्भर न रहें। संतान के साथ घूमने-फिरने का मौका मिलेगा। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात दिन को खास बना सकती है।

कन्या- आज सफलता और तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। लंबे समय से अटका सरकारी काम पूरा होने की संभावना है। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। माताजी से हुई बातचीत आपकी कई उलझनों का हल निकाल देगी। लाइफस्टाइल में सुधार लाने की कोशिश सफल रहेगी।

तुला- आज मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए धन निवेश की नई योजनाएँ बना सकते हैं। कानूनी मामलों में लापरवाही नुकसान दे सकती है, इसलिए सतर्क रहें। किसी सहयोगी की बात दिल को चुभ सकती है। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के लिए दूर जाना पड़ सकता है, जिससे भावुक माहौल बन सकता है।

वृश्चिक- आज आपके दिमाग में नए और शानदार आइडिया लगातार आते रहेंगे। बिजनेस में नई शुरुआत लाभ दे सकती है। जीवनसाथी के करियर में भी नया अवसर दस्तक दे सकता है। आय बढ़ने से मन खुश रहेगा। लंबे समय से रुका काम पूरा होने से राहत मिलेगी। किसी जरूरी फैसले में पिताजी की सलाह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।

धनु- आज लेनदेन के मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर फैसला लेने से बचें। माताजी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई सहयोगी परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकता है। विद्यार्थियों का मानसिक दबाव कम होगा। पूजा-पाठ और धार्मिक माहौल में मन को सुकून मिलेगा।

मकर- आज का दिन नई संभावनाएँ लेकर आएगा। यात्रा या घूमने के दौरान कोई खास जानकारी हाथ लग सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है। नया वाहन खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। पुराने लेनदेन से जुड़ी परेशानी थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। संतान की ओर से मिली खुशखबरी आपका दिन बना देगी।

कुंभ- आज मौज-मस्ती और खुशी का माहौल बना रहेगा। छोटे बच्चों के साथ बिताया गया समय आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। पिताजी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का खास ध्यान रखें। धन और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। सेहत से जुड़ी पुरानी परेशानी में राहत मिलने से मन हल्का महसूस करेगा। आपकी कोई खास इच्छा भी पूरी हो सकती है।

मीन- आज भागदौड़ ज्यादा रहेगी और मन थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर सकता है। कामों में लापरवाही भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए हर जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने की जरूरत है, वरना परीक्षा में दिक्कत हो सकती है। दूसरों के मामलों में बेवजह सलाह देने से बचें। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा रहेगी, जिसे सही दिशा में लगाना आपके लिए सफलता के रास्ते खोलेगा।

शब्दजाल - 8267

शब्द जाल में 10 प्रसिद्ध हास्य फिल्मों के नाम ढूंढिए. दिए गए शब्द उपर से नीचे एवं तिरछे भी हैं.

दो जासूस, अलबेला, गोलमाल, शौकीन, चालबाज, हीरो हीरालाल, आगे की सोच, झूठी, अंगूर, पुष्पक.

शब्दजाल - 8266 का हल

फिल्म वर्ग पहेली- 7211

ऊपर से नीचे:-

१. 'मेरा नाम है चमेली' गीत वाली संजीव कुमार, नाज़िमा, कुमकुम की फिल्म-२,२,२
२. तुषार कपूर, अंतरा माली की 'मैं तब तुमसे' गीत वाली फिल्म-३
४. 'सिर्फ तुम ही तो हो जिसपे' गीत वाली शम्मीकपूर, साधना की फिल्म-५
५. अभिषेक बच्चन, भूमिका चावला की 'दिल में जो बात' गीत वाली फिल्म-२
७. 'मधुबन में जो कन्हैया' गीत वाली अमितखान, प्रेमसिंह की फिल्म-३
९. संजयखान, बबीता की 'आ लगजा गले' गीत वाली फिल्म-२,२
१३. 'रूखी सूखी रोटी' गीत वाली अनिल कपूर, रानी मुखर्जी की फिल्म-३
१५. 'क्या सही प्यार है' गीत वाली फिल्म 'रॉकी' में संजयदत्त के साथ नायिका कौन थी-३
१६. जीतेंद्र, श्रीदेवी की 'आई लव यू आई लव यू' गीत वाली फिल्म-५
१८. 'ओफ्फो जलता है बुझता है' गीत वाली सनी, सोहेल, सुनील, जॉन अब्राहम, नौहीद की फिल्म-३
२०. संजय दत्त, माधुरी दीक्षित की 'तम्मा तम्मा लोगे' गीत वाली फिल्म-४
२१. 'लो आगई उनकी याद' गीत वाली मनोज कुमार, आशा पारेख की फिल्म-१,३
२४. अक्षय कुमार, करीना कपूर की 'तूने कहा जब से हाँ' गीत वाली फिल्म-३
२७. 'और क्या अहद ए वफा' गीत वाली सनी देओल, अमृतसिंह की फिल्म-२

बायें से दायें:-

१. जतिन ग्रेवाल, यश पाठक, नेहा की 'चलती है पुरवाई' गीतवाली फिल्म-३
३. 'मेरा मन तेरा प्यासा' गीत वाली देव आनंद, वहीदा, जाहिरा की फिल्म-४
६. सनी, मीनाक्षी की 'सोचना क्या जो भी होगा' गीत वाली फिल्म-३
८. 'कब तक हुजूर रूठे होंगे' गीत वाली जीतेंद्र, बबीता की फिल्म-३
१०. धर्मेन्द्र, हेमा, रीना राय की 'नागिन सा रूप है तेरा' गीत वाली फिल्म-४
११. 'सपने में मिलती है' गीत वाली डॉ. चक्रवर्ती, मनोज, उर्मिला की फिल्म-२
१२. रघुवीर यादव, कुणालकपूर, तब्बू, नादिरा बब्बर की 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' गीत वाली फिल्म-३
१४. 'क्या करें क्या ना करें' गीत वाली जैकी श्रॉफ, उर्मिला की फिल्म-३
१६. सनी देओल, करिश्मा की 'छम्मक छल्लो जरा धीरे' गीत वाली फिल्म-३
१७. जैकी श्रॉफ, संजय, माधुरी की फिल्म-५
१९. फारूख शेख, नसीरुद्दीनशाह, दीप्ति नवल की सई परांजपे निर्देशित एक फिल्म-२
२२. 'कंधों से मिलते हैं कंधे' गीत वाली अमिताभ, रितिक, प्रीति की फिल्म-२
२३. राकेश रोशन, रेखा की 'सुन सुन सुन दीदी तेरे लिये' गीत वाली फिल्म-५
२५. 'पर्दे में कोई बैठा है' गीत वाली अमजद खान, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी की फिल्म-२
२६. संजय दत्त, सलमान खान, रवीना की 'सुनो गौर से' गीत वाली फिल्म-२
२८. 'जिसका मुझे था इंतजार' गीत वाली अमिताभ, जीनत अमान की फिल्म-२
२९. मिलिंद सोमण, विक्रम मालूजा, किरण झवेरी की फिल्म-३
३०. फिल्म 'रफूचक्कर' में नायिका थी-२

फिल्म वर्ग पहेली- 7210

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

23 मई 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	वृष में	मिथुन	06.50 बजे से
चंद्र	सिंह में	कर्क	09.03 बजे से
मंगल	मेष में	सिंह	11.19 बजे से
बुध	वृष में	कन्या	13.31 बजे से
गुरु	मिथुन में	तुला	15.42 बजे से
शुक्र	मिथुन में	वृश्चिक	17.56 ब.से
शनि	मीन में	धनु	20.12 बजे से
राहु	कुंभ में	मकर	22.18 बजे से
केतु	सिंह में	कुंभ	00.04 बजे से
		मीन	01.37 बजे से
		मेष	03.07 बजे से
		वृष	04.48 बजे से

राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक

शनिवार 2026 वर्ष का 143 वा दिन दिशाशूल पूर्व ऋतु ग्रीष्म। विक्रम संवत् 2083 शक संवत् 1948 मास ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल तिथि अष्टमी 04.28 बजे प्रातः को समाप्त। नक्षत्र मघा 02.10 बजे रात्र को समाप्त। योग ध्रुव 06.14 बजे तदनन्तर व्याघात 04.43 बजे प्रातः को समाप्त। करण विष्टि 16.41 बजे तदनन्तर बव 04.28 बजे प्रातः को समाप्त। चन्द्रायु 6.2 घण्टे रवि क्रान्ति उत्तर 20° 32' सूर्य उत्तरायन कलि अहर्गण 1872718 जूलियन दिन 2461183.5 कलियुग संवत् 5128 कल्पारंभ संवत् 1972949128 सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128 वीरनिर्वाण संवत् 2552 हिजरी सन् 1447 महीना जिल्हेज तारीख 06 विशेष अधिक मासिक दुर्गाष्टमी।

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया		
काल	05.55 से	07.23 बजे तक		लाभ	05.37 से	07.10 बजे तक
शुभ	07.23 से	08.51 बजे तक		उद्वेग	07.10 से	08.42 बजे तक
रोग	08.51 से	10.19 बजे तक		शुभ	08.42 से	10.14 बजे तक
उद्वेग	10.19 से	11.46 बजे तक		अमृत	10.14 से	11.47 बजे तक
चर	11.46 से	01.14 बजे तक		चर	11.47 से	01.19 बजे तक
लाभ	01.14 से	02.42 बजे तक		रोग	01.19 से	02.51 बजे तक
अमृत	02.42 से	04.10 बजे तक		काल	02.51 से	04.23 बजे तक
काल	04.10 से	05.37 बजे तक		लाभ	04.23 से	05.56 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभस्थ श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगतः वे तीन

एक बार एक बुढ़िया को उसके बेटे का पत्र मिला। बेटा दूर देश में रहता था। बुढ़िया को पत्र पढ़ना नहीं आता था। वह अपने घर के सामने प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आए, तो पत्र पढ़ कर उसको सुना दे। आखिर एक सैनिक आया। उसने पत्र देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर बाद वह फूट-फूट कर रोने लगा। बुढ़िया ने घबरा कर पूछा, मेरे बेटे को कुछ हो गया क्या? लेकिन सैनिक ने कोई जवाब नहीं दिया। बस, रोता ही रहा। बेचारी बुढ़िया ने सोचा कि उसके बेटे पर कोई भयंकर मुसीबत आ गई है। वह भी सैनिक के साथ रोने लगी। कुछ देर बाद एक व्यापारी आया। उसने उन दोनों को रोते देखा तो वह भी उनके साथ रोने लगा। वे तीनों रो रहे थे इतने में एक और आदमी आया। उन तीनों को रोते देखकर उसने पूछा कि मामला क्या है? पहले व्यापारी बोला, साल भर पहले मैं मिट्टी के कुछ बर्तन बेचने निकला था। मेरी किस्मत खराब थी। सारे बर्तन टूट गए। मैं तब रोना चाहता था लेकिन मुझे समय नहीं मिला क्योंकि मैं अपने नुकसान को पूरा करने में लगा था। इन दोनों तो रोते देखकर मुझे याद आया कि तब मैं रोया ही नहीं। मैंने सोचा चलो अभी रो लेता हूं। इसीलिए मैं रो रहा था। जब बुढ़िया से पूछा तो उसने कहा- मुझे मेरे बेटे का पत्र मिला था। मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने इस सैनिक से पढ़ने को कहा और वह पत्र देखते ही रोने लगा। पत्र में जरूर कोई बुरी खबर लिखी है। यह सोचकर मैं रोने लगी। आखिर में सैनिक से पूछा तो वह बोला- सच तो यह है कि बचपन में मैंने थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की। अपने अनाड़ीपन पर मुझे दुख हुआ कि इस पत्र को मैं पढ़ नहीं सकता। मुझे इतनी शर्म आई कि मैं रोने लगा। तानों की बात सुनकर वह आदमी समझ गया कि इनके रोने का कारण इनकी बेवकूफी है। उसने पत्र पढ़ा और बुढ़िया को बताया कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक-ठाक है। सभी को समझाकर उसने अपना रास्ता पकड़ा।

सूडोकू नवताल- 7520

★★★★☆ कठिन

	8	5						
3								
			6			7	4	
6			2		4			
1								8
			7		5			3
	4	7			1			
								6
						5	2	

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकू नवताल -7519 का हल

4	3	9	2	6	8	5	1	7
8	1	6	7	4	5	9	2	3
7	5	2	3	9	1	6	4	8
1	7	5	4	2	6	8	3	9
6	4	3	8	5	9	2	7	1
2	9	8	1	7	3	4	5	6
5	2	1	6	8	7	3	9	4
9	8	7	5	3	4	1	6	2
3	6	4	9	1	2	7	8	5

शब्द पहेली - 8735

बाएँ से दाएँ

1. खटपट,ठनाठनी-4
4. पंजाब की एक नदी-4
6. चित्रमेल,लम्बी गर्दनवाला पशु-3
8. दंड,दम,शासन-3
9. धरा,भूमि-3
11. शासन व्यवस्था,रहस्य-2
13. नवचंद्राकार-5
15. अकेला-2
16. दया,करुणा-3
18. बंदर का खेल दिखाने वाला-3
19. देवर्षि,देवमुनि-3
20. सब्जी,भाजी-4
22. कुंए पर पानी भरने का चबूतरा-4

ऊपर से नीचे

1. गुनाह,दोष,जुर्म-3
2. अपराधमुक्त,निवृत्त-2
3. सौत,दूसरी स्त्री-3
4. होशियार,गुणवान-5
5. भूकम्प-4
7. भेद,तुलना-3
10. परिचर्या-5
12. स्वभाव-4
14. स्थित होना-3
17. श्मशान-4
18. गृह,भवन-3
21. जीवन,जीव,स्फूर्ति-2

शब्द पहेली -8734 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

लांजी में खाद्य सुरक्षा टीम का छापा, ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थों की जांच

लस्सी, छाछ और कोल्ड ड्रिंक के नमूने लिए, स्वच्छता की पोल खुली

पद्मेश न्यूज। लांजी। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग बालाघाट ने आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में विगत दिनों लांजी क्षेत्र में अचानक छापेमारी की गई। टीम ने लोकप्रिय होटलों और मिष्ठान भंडारों पर एक साथ दबिश दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने लांजी स्थित कृष्ण बीकानेर मिष्ठान भंडार, होटल शिवराज और श्री नैवेद्यम होटल में गहन जांच अभियान चलाया। टीम ने इन प्रतिष्ठानों के किचन, स्टोर रूम और सम्पूर्ण परिसर की साफ-सफाई का मुआयना किया। साथ ही मौके पर बिक रहे ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थों — लस्सी, छाछ एवं कोल्ड ड्रिंक के नमूने जांच के लिए जब्त कर लिए गए।

सभी प्रतिष्ठानों में मिले खाद्य लाइसेंस

जांच के दौरान पाया गया कि तीनों प्रतिष्ठानों के पास वैध खाद्य लाइसेंस उपलब्ध हैं। पूर्व में जारी किए गए सुधार नोटिसों पर भी इन प्रतिष्ठानों द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने स्वच्छता मानकों की अनुपालन स्थिति पर संतोष जताते हुए कुछ बिंदुओं पर सुझाव भी दिए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में लस्सी, छाछ, शरबत, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की खपत काफी बढ़ जाती है। ऐसे में इन पेय पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और विक्रय में किसी भी प्रकार की लापरवाही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए जिले भर में यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने कहा, उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। लांजी के बाद अब जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की जांच अभियान चलाए जाएंगे। जो प्रतिष्ठान स्वच्छता और गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लांजी बाजार में दुकानदारों और उपभोक्ताओं ने इस अभियान का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार को बीमार कर सकती है।

शराब दुकानों पर आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन

अखबारों में सुर्खियां बनने के बाद जागा विभाग, लांजी की दुकान पर लाखों की कार्रवाई

पद्मेश न्यूज। लांजी। लंबे समय से शराब दुकानों में निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन आबकारी विभाग मानो कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ था। पत्रकारों और आम लोगों द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझ रहे थे। अब जब मामला अखबारों की सुर्खियां बना और प्रशासनिक सख्ती बढ़ी, तब जाकर विभाग ने धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त लांजी द्वारा 07 मई 2026 को की गई आकस्मिक टेस्ट परचेस कार्रवाई में कम्पोजिट मदिरा दुकान लांजी-बी में गंभीर अनियमितता पकड़ी गई। निरीक्षण के दौरान विदेशी मदिरा रॉयल स्टेग व्हिस्की पाव (180 एमएल) निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 260 रुपये के स्थान पर 300 रुपये में बेची जाती पाई गई। यानी ग्राहकों से खुलेआम प्रति पाव 40 रुपये अधिक वसूले जा रहे थे। मामले में म.प्र. राजपत्र (असाधारण) 20 फरवरी 2026 की कंडिका 21.1 तथा सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 7, 18, 20 एवं 22 का उल्लंघन पाया गया। इस संबंध में विनो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद आबकारी विभाग ने प्रथम अपराध मानते हुए 2 लाख 25 हजार 736 रुपये की शास्ति तथा 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित कर प्रकरण का शमन किया। हालांकि बड़ा सवाल अब भी यही है कि यह कार्रवाई आखिर कब तक जारी रहेगी? क्या यह केवल कुछ दिनों की दिखावटी सख्ती है या वास्तव में शराब दुकानों में चल रही मनमानी पर स्थायी लगाम लगेगी? क्षेत्र में लंबे समय से एमआरपी से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन कार्रवाई तब शुरू हुई जब मीडिया ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अब आबकारी अधिकारी स्वयं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी भेजकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मगर जनता यह जानना चाहती है कि जब उपभोक्ताओं से खुलेआम अधिक वसूली हो रही थी तब विभाग की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां थी। फिलहाल कार्रवाई ने जरूर विभाग की सक्रियता दिखाई है, लेकिन यह सक्रियता स्थायी रहेगी या फिर शिकायतों का दौर लौटते ही सब पहले जैसा हो जाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा।

विशेष रात्रिकालीन शिविर आयोजित कर किसानों की बनाई जा रही फॉर्मर रजिस्ट्री

पद्मेश न्यूज। लांजी। जिले में आम जनता एवं किसानों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए कलेक्टर बालाघाट द्वारा लगातार नवाचारपूर्ण पहले की जा रही हैं। प्रशासन की कोशिश है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सुविधाएं सरल और सहज रूप से पहुंचें। ग्रामीण अंचलों में रात्रिकालीन शिविर आयोजित कर किसानों को मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध कराना कलेक्टर की दूरगामी सोच, जनहितैषी कार्यशैली एवं कार्यकुशल प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रमाण माना जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर बालाघाट के निर्देशानुसार 21 मई 2026 को लांजी तहसील के ग्राम टेमनी में शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक फॉर्मर रजिस्ट्री हेतु रात्रिकालीन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हल्का पटवारी प्रिंशु दुबे, कृषि विस्तार अधिकारी अमित नारनौरे एवं ग्राम रोजगार सहायक संतोष पंचाले उपस्थित रहे तथा किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य किया गया। कैंप के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को नरवाई प्रबंधन, हरी खाद के उपयोग, ई-टोकन व्यवस्था एवं धान की डीएसआर पद्धति के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया। अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने एवं शासन की योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने बताया कि शासन की ई-विकास प्रणाली के माध्यम से खाद प्रदाय सहित विभिन्न कृषि सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसलिए सभी किसान भाइयों से समय पर अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री करवाने की अपील की गई।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से मनाई स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि

पद्मेश न्यूज। लांजी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लांजी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहेला एवं नगर कांग्रेस कमेटी लांजी के संयुक्त तत्वावधान में 21 मई 2026 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा, संचार क्रांति के जनक एवं पंचायती राज के पुरोधा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन नगर कांग्रेस कमेटी लांजी के अध्यक्ष एवं पार्षद सौरभ मोनू पशीने के निवास स्थान पर किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय राजीव गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात उपस्थित वक्ताओं ने अपने उद्बोधनों में राजीव गांधी के जीवन, व्यक्तित्व एवं देश के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लांजी के अध्यक्ष रेवाजी करहाटकरे ने कहा कि भारत में कंप्यूटर एवं संचार क्रांति की नींव रखने में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आईटी क्षेत्र में उनके कार्यों को देश कभी नहीं भूल सकता। जनपद पंचायत लांजी के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र यशवंतराव खोंगल ने कहा कि देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का परिणाम थी। उन्होंने कहा कि युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना ऐतिहासिक निर्णय था। सेवानिवृत्त शिक्षक शाहजहां बेग ने राजीव गांधी को असाधारण प्रतिभा का धनी एवं आधुनिक भारत की आधारशिला रखने वाला नेता बताया। वहीं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ज्योति उमरे ने कहा कि राजीव गांधी की दूरदृष्टि आज भी देश के विकास और आमजन के उत्थान में मार्गदर्शक बनी हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लांजी-किरनापुर क्षेत्र की पूर्व विधायक, मध्यप्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव सुश्री हिना कावरे ने कहा कि जिस सोच और दूरदर्शिता के साथ राजीव गांधी ने देश को आईटी और आधुनिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, वही जज्बा आज राहुल गांधी में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानती है। कार्यक्रम का संचालन नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ मोनू पशीने ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन जनपद पंचायत लांजी के सभापति दिनेश लांडे ने व्यक्त किया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना खोंगल, सरपंच संघ अध्यक्ष ललित कबीरे, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मनीष जुझार, एडवोकेट अनमोल तिडके, अशोक पालीवाल, चन्दु किरनापुरे,नीलोफर खान, गणेश बागड़े, अमन रमेंद्र श्रीवास्तव, भरतलाल बड़मे, सीताराम बड़मे, नरेंद्र नाथ मोतीचूर, सिद्धीक अंसारी, प्रभुदयाल किरमे,ज्ञानवंती भलावी, माणिकराव वानखेड़े, दीपक वानखेड़े, रविकिरण बड़मे, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, किशनलाल मेहरबान, रियाज शेख, सपना अनुराग पशीने, विवेक राऊत, स्मिता राऊत, रामराज चौहान, अफसाना अंसारी, मनीषा रविंद्र धारने, आशीष सोनू श्रीवास्तव, पार्षद मुकेश रणदीवे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

बेनेगांव में संबल योजना अंतर्गत मृतक के परिजनों को प्रदान की सहायता राशि

पद्मेश न्यूज। लांजी। मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना संबल 2.0 के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेनेगांव में मृतक हितग्राहियों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। इस दौरान स्वर्गीय यशवंतराव पिता स्व. नोहरलाल बुढ़ावने के निधन पर उनके पुत्र सतीश बुढ़ावने को 5000 रुपये, स्व. यनटुदास गजभीये के निधन पर उनके पुत्र शुभम गजभीये को 5000 रुपये, स्व. हरिश्चंद्र बावनकर के निधन पर उनके पुत्र धनराज बावनकर को 5000 रुपये तथा स्व. खेलन बाई शक्करपुड़े के निधन पर उनके पुत्र सीताराम शक्करपुड़े को 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष परसराम बुढ़ावने, उपसरपंच दीपक महेंद्र उके, रोजगार सहायक नरेश शक्करपुड़े पंच गण एवं पंचायत भृत्य फुलचंद धारने सहित ग्राम के गणमान्य गण अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने मध्यप्रदेश सरकार की जनहितकारी संबल 2.0 योजना की सराहना करते हुए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इनका कहना है

मध्यप्रदेश शासन की संबल 2.0 योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। आज ग्राम पंचायत बेनेगांव में पात्र हितग्राहियों के परिजनों को सहायता राशि प्रदान की गई। शासन की मंशा है कि संकट की घड़ी में परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। मैं मध्यप्रदेश सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है।

संतोष परसराम बुढ़ावने
सरपंच, ग्राम पंचायत बेनेगांव

लांजी में "पद्मेश"
इंटरनेट (ब्राडबेंड)
कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

मप्र की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान

कांग्रेस से कमलनाथ, पटवारी, अरुण यादव में रेस; कुरियन को रिपीट कर सकती है बीजेपी

भोपाल । भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को कर दिया है। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। इनमें मध्य प्रदेश की तीन सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के तीन सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इनमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जबकि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। उनकी सीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा के नाम रेस में हैं। वहीं, बीजेपी कुरियन को दोबारा उच्च सदन भेज सकती है। सुमेर सिंह की सीट पर भी किसी और आदिवासी चेहरे को उतारा जा सकता है।

अधिसूचना के मुताबिक, खाली सीटों पर 8 जून तक नामांकन किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच के बाद 11 जून तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग के बाद उसी दिन रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। चुनावी घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस के सामने अपनी एक सीट के लिए विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता जा चुकी है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। बीना विधायक निर्मला सप्रे भाजपा और कांग्रेस के बीच झूल रही हैं। ऐसे में वो किस दल के पक्ष में मतदान करेंगी, फिलहाल निश्चित नहीं है। भारती की सदस्यता जाने के बाद संख्याबल के हिसाब से विधानसभा में भाजपा के 164, कांग्रेस के 64 जबकि एक भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं। एक सीट रिक्त है।

कुरियन को रिपीट कर सकती है भाजपा

जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे भाजपा के उन पुराने और वफादार नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने पार्टी के गठन के समय से ही इसका झंडा थाम रखा है। वे 1980 से पार्टी से जुड़े हैं। हाल ही में उन्होंने केरलम विधानसभा चुनाव में कांजिरापल्ली सीट से किस्मत आजमाई थी, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। केरलम जैसे राज्य में पार्टी का ईसाई चेहरा होने और केंद्र सरकार में सक्रिय भूमिका के कारण यह माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें एक बार फिर मध्य प्रदेश के कोटे से ही उच्च सदन भेज सकती है।

सुमेर की सीट पर विकल्प के लिए मंथन

डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बनाए जा चुके हैं। वे संघनिष्ठ आदिवासी चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में 22 फीसदी आदिवासी आबादी है। ऐसे में बीजेपी के अंदरखाने उनकी सीट पर आदिवासी नेताओं के नामों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा। इससे पहले साल 2020 में जब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा था, तब बीजेपी ने सोलंकी के नाम की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। उस समय वे सरकारी नौकरी में थे, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने तत्काल प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दिया। तकनीकी कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर होने में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अंततः वे चुनावी मैदान में उतरे और राज्यसभा पहुंचे थे।

खुले में शौच मुक्त प्रदेश के दावों पर उठे सवाल

-जनगणना में कई इलाकों के आधे घरों में शौचालय नहीं होने का खुलासा, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

भोपाल। मध्य प्रदेश को सात वर्ष पहले 'ओडीएफ प्लस' यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन हालिया जनगणना के मकान सूचीकरण में सामने आए आंकड़ों ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई क्षेत्रों में ऐसे घर पाए गए, जहां आज भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित कर विकास के बड़े दावे किए थे, लेकिन अब जनगणना के आंकड़ों ने उन दावों की पोल खोल दी है। कांग्रेस का आरोप है कि कई इलाकों में आज भी आधे घरों में शौचालय तक नहीं हैं और अब सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए कभी जनता तो कभी सर्वे कर्मचारियों पर दोष मढ़ रही है। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि प्रदेश पूरी तरह ओडीएफ था, तो फिर जनगणना के आंकड़ों में इतनी बड़ी विसंगतियां कैसे सामने आईं। जानकारी अनुसार रायसेन नगर पालिका क्षेत्र में जनगणना-2027 के पहले चरण के मकान सूचीकरण के दौरान वार्ड-13 में 60 परिवारों के रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी सामने आई थी। शहर पहले से ओडीएफ घोषित है, लेकिन रिकॉर्ड में इन परिवारों के पास शौचालय नहीं होने और खुले में शौच जाने का उल्लेख दर्ज हो गया था। सत्यापन के बाद बताया गया कि प्रगणक द्वारा शौचालय संबंधी कॉलम में गलत कोड दर्ज कर दिया गया था। पर यह मामला सिर्फ रायसेन जिले तक सीमित नहीं है, प्रदेश के कई अन्य इलाकों से इसी तरह के आंकड़े सामने आने के दावे मीडिया रिपोर्ट में हुए हैं, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ संबंधित अधिकारियों का इस मामले में कहना था, कि कई परिवार सार्वजनिक या साझा शौचालय का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रविष्टि में 'कोड-4' भर दिया गया।

30 मई से बदलेगी श्रीधाम एक्सप्रेस की सूरत

भोपाल। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में भारतीय रेलवे लगातार अपने कोच और ट्रेनों को आधुनिक बना रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल से गुजरने वाली जबलपुर-निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस को अब एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) कोच के साथ चलाने का फैसला लिया गया है। यह बदलाव मई के अंत से लागू होगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा।

रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर-निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 30 मई 2026 से जबलपुर से एलएचबी रैक के साथ रवाना होगी। वहीं, गाड़ी संख्या 12191 निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 31 मई 2026 से निजामुद्दीन से एलएचबी कोच के साथ संचालित की जाएगी। यह बदलाव भोपाल मंडल के यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह ट्रेन इस रूट से होकर गुजरती है।

22 कोच, हर वर्ग के यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प

नए एलएचबी रैक में कुल 22 कोच होंगे। इसमें प्रथम एसी, द्वितीय एसी, तृतीय एसी, थर्ड एसी इकॉनमी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं। साथ ही एसएलआरडी और जनरेटर कार भी जोड़ी गई हैं। इस नई संरचना से ट्रेन की क्षमता और संचालन दोनों में सुधार होगा।

अब 1128 बर्थ की सुविधा, भीड़ में मिलेगी राहत

एलएचबी कोच लगने के बाद इस ट्रेन में कुल 1128 आरक्षित बर्थ उपलब्ध होंगी। इनमें प्रथम एसी में 24, द्वितीय एसी में 104, तृतीय एसी में 360, थर्ड एसी इकॉनमी में 80 और स्लीपर क्लास में 560 बर्थ शामिल हैं। इससे यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और वेटिंग की समस्या में भी कमी आएगी। एलएचबी कोच पारंपरिक आईसीएफ कोच की तुलना में अधिक आधुनिक माने जाते हैं। इनकी डिजाइन बेहतर होती है, वजन कम होता है और हाई स्पीड पर भी स्थिरता बनाए रखते हैं। दुर्घटना की स्थिति में इनकी सुरक्षा क्षमता अधिक होती है, जिससे यात्रियों की जान-माल का जोखिम कम होता है। भोपाल मंडल की यह पहल साफ संकेत देती है कि रेलवे अब सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि सफर की गुणवत्ता पर भी गंभीरता से काम कर रहा है। यात्रियों के लिए यह बदलाव आने वाले समय में और भी बेहतर रेल अनुभव का आधार बन सकता है।

युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने जन्म तिथि में बदलाव कर हुए 35 के

-नियमों की उड़ा रहे धज्जियां, उम्र के काईटेरिया के लिए रसूख के दम पर दस्तावेजों में बदली जन्म तिथि

शहडोल । पद की चाह में कोई व्यक्ति किस स्तर तक जा सकता है और अपने परिजनों के राजनीति रसूख का इस्तेमाल कितना कर सकता है। इसका उदाहरण शहडोल में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पद के दावेदार जानू सिंह छाबड़ा ने पेश किया हैं। उन्होंने पद की चाह में एक बार नही तीन बार अपनी जन्मतिथि में बदलाव कराया है। वह भी इस लिए क्योकि इस पद के लिए पार्टी के क्राइटेरिया के हिसाब से उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। पद की जाह में अपने परिजनों के रसूख का उपयोग करके दस्तावेजों में ही हेरफेर की है।

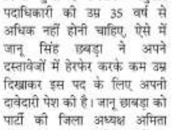

शहडोल जिले में युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष इंदरजीत सिंह छाबड़ा और धनपुरी नगर पालिका अध्यक्ष रविन्दर कौर छबड़ा के पुत्र जानू सिंह छाबड़ा का नाम सामने आ रहा है। पार्टी द्वारा युवा मोर्चा में उम्र का क्राईटेरिया तय किया हुआ है जिसके अनुसार पदाधिकारी की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसे में जानू सिंह छबड़ा ने अपने दस्तावेजों में हेरफेर करके कम उम्र दिखाकर इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। जानू छाबड़ा को पार्टी की जिला अध्यक्ष अमिता चापरा का भी आर्शीवाद प्राप्त है वह भी जानू को युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए प्रयास रत है।

समग्र आईडी में जन्म तिथि में बदलाव, आधार कार्ड में अलग

जानू सिंह छाबड़ा की नगर पालिका से समग्र आईडी में तीन बार बदलाव किया गया है जिसमें पहली बार की जन्म तिथि 01/12 1988 थी, जिसे 01/12/89 कराया गया इसके बाद दूसरी बार में 01/12/1989 से बदलबा कर 01/12/1991 कराया गया है। जानू छाबड़ा के आधार काड में उनकी जन्मतिथि 01/12/1989 लिखी हुई है। वही नगर पालिका की बोटर लिस्ट जो वर्ष 2021 की है उसमें जानू छाबड़ा की उम्र 33 वर्ष लिखी है।

पिता और मां के रसूख का उपयोग

जानू छाबड़ा के पिता इंदरजीत सिंह छाबड़ा शहडोल के वर्ष 2016 से 2019 तक जिला अध्यक्ष रहे है। उनकी मां रविंदर कौर छबड़ा वर्तमान में धनपुरी नगरपालिका की अध्यक्ष है। इसी रसूख का उपयोग करके समग्र आईडी में जन्मतिथि में बदलाव करया गया है।

संगठन की साख दाव पर

शहडोल के भाजपा कार्यकर्ता जानू सिंह छाबड़ा की दावेदारी को लेकर दबी जुबान से संगठन की साख को दाव पर लगाने की बात कह रहे है। उनका मानना है कि पूर्व में जिला अध्यक्ष के लिए तय क्राईटेरिया से बाहर के लोगों को संगठन ने बाद में पद से हटा दिया था कही ऐसा ही शहडोल के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ न हो जिससें संगठन की साख पर दाग लगें।

ट्विशा मौत मामला - डेडबॉडी का होगा दूसरा पोस्टमॉर्टम

मप्र सरकार की सीबीआई जांच को मंजूरी

भोपाल/जबलपुर। एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की डेडबॉडी का सेकंड पोस्टमॉर्टम होगा। इसे दिल्ली एम्स की टीम करेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को शव को सुरक्षित रखने को भी कहा है। मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। 20 मई को जब ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तब उन्होंने इसका आश्वासन दिया था।

टाइगर रिजर्व के आसपास स्थापित करेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर

आईआईएफएम में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट में मुख्यमंत्री बोले

भोपाल। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि घायल वन्य जीवों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही हो सके। अब तक जंगल में घायल होने वाले जानवरों को इलाज के लिए भोपाल लाना पड़ता था, जिससे उन्हें अनावश्यक तकलीफ होती थी। स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू सेंटर बनने से वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर नहीं ले जाना पड़ेगा और उनका उपचार भी तेजी से हो सकेगा।

यह बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। वे भोपाल स्थित आईआईएफएम में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस प्री-समिट को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

चीता प्रोजेक्ट ने मप्र को नई पहचान दिलाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तब कई लोगों ने इसे लेकर आशंकाएं जताई थीं और डर का माहौल बनाया था, लेकिन अब इस परियोजना की सफलता ने मध्यप्रदेश को वन्य जीव विविधता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में मगरमच्छ नहीं होने की बात सामने आने पर यह चर्चा होती थी कि यदि वाहन मगरमच्छ नहीं है तो मां नर्मदा की सवारी कैसे होगी। शुरुआत में कोई भी मगरमच्छ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में भी कार्य पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार तीसरे वर्ष चलाया गया है। इस अभियान के तहत करीब तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से 56 हजार से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में एक हजार से अधिक अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और दो लाख से ज्यादा जलदूत तैयार किए गए हैं।

देश में जल्दी ही 100 रामसर साइट घोषित होंगी

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इंदौर वेटलैंड सिटी घोषित हुआ है। देश में जल्दी ही 100 रामसर साइट घोषित होंगी, अब तक 94 साइट्स घोषित की जा चुकी हैं। विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकता है, लेकिन इसमें सोसायटी, पॉलिसीमेकर, साइंटिस्ट, सिविल सोसायटी समेत हर व्यक्ति को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली के लिए काम करना होगा। जब जैव विविधता समृद्ध होगी तो मानवता समृद्ध होगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि जैव विविधता मानव जीवन और प्रकृति के संतुलन के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की थाली में केवल गेहूं और चावल ही हों, तो कुछ समय बाद भोजन नीरस लगने लगता है। इसी तरह प्रकृति में विविधता ही जीवन को समृद्ध और मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि हर वनस्पति और जीव के अस्तित्व की एक सीमा और भूमिका होती है तथा प्रकृति का पूरा एक संतुलित तंत्र है।

टाइगर नदियों और प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा करते

भूपेन्द्र यादव ने कहा कि हाल ही में प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा की गई है और इस परियोजना ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि चीता मुख्य रूप से ग्रासलैंड क्षेत्र में पनपता है और घास के मैदान जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि टाइगर केवल अपनी टेरिटरी ही नहीं बल्कि नदियों और प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा करते हैं।

एमपी के पहले डीजीपी से धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

भोपाल। शहर की हबीबगंज थाना पुलिस ने प्रदेश के पहले डीजीपी रहे हरिवल्लभ मोहनलाल (एचएम) जोशी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी फेथ ग्रुप के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर को बीती रात रातीबढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धोखाधड़ी के मामले में चार साल से फरार चल रहा था। आरोप है कि राघवेंद्र ने पूर्व डीजीपी एचएम जोशी को फर्जीवाड़ा कर एक पार्टनरशिप फर्म से बाहर कर दिया था।

थाना पुलि से मिली जानकारी के मुताबिक, रिटायर्ड डीजीपी एचएम जोशी ई-5 अरेरा कॉलोनी में रहते थे। उनकी रातीबड़ थाना इलाके के ग्राम सेमरी में जमीन थी। यहां क्रिकेट अकादमी बनाने के लिए फेथ ग्रुप के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर ने जोशी के साथ पार्टनरशिप की थी। इस पार्टनरशिप फर्म का नाम मैसर्स फेथ क्रिकेट क्लब रखा गया था। लेकिन साल 2017 में आरोपी राघवेंद्र ने जोशी को डीड से बाहर करने के लिए फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया। इस पर जोशी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षरों के जरिए उन्हें पार्टनरशिप से बाहर दिखाकर जमीन अपने नाम करा ली। करीब दो साल बाद एचएम जोशी को मामले की जानकारी लगी। उन्होंने पहले रातीबढ़ थाने में शिकायत की। जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेज हबीबगंज थाना क्षेत्र में तैयार किए गए थे। इसके बाद केस ट्रांसफर हुआ और 2022 में हबीबगंज पुलिस ने जांच के बाद राघवेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, आखिरकार गुरुवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार कब्जाई गई जमीन पर ही बाद में फेथ क्रिकेट क्लब बनाया गया। इस मामले के बाद आयकर विभाग ने भी राघवेंद्र के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। आरोपी राघवेंद्र सिंह तोमर के पिता पीएस तोमर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, और आईजी पद से रिटायर हुए थे। राघवेंद्र ने पहले सरकारी ठेकेदारी का काम किया, बाद में फेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जरिए भोपाल और इंदौर में कारोबार बढ़ाया।

भोपाल के ट्रैफिक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर एनजीटी में याचिका

भोपाल। भोपाल के ट्रैफिक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण का मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंच गया है। पर्यावरणविद् राशिद नूर की याचिका पर एनजीटी ने प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सेंट्रल जोन बेंच ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी ने पक्ष रखा। सुनवाई में न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल रहे।

याचिका में बताया गया है कि भोपाल में स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक पुलिस ने कई चौराहों और सडकों पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए हैं। इनसे पूरे दिन तेज आवाज में ट्रैफिक संदेश, चेतावनी और निर्देश चलते रहते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, इनकी आवाज बहुत तेज है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और यह स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है।

अस्पताल और साइलेंस जोन में भी शोर का आरोप

याचिकाकर्ता का कहना है कि ये सिस्टम कई बार अस्पताल, स्कूल, कोर्ट और रिहायशी इलाकों के पास भी चलाए जा रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इन जगहों पर शोर पर सख्त रोक होती है। इसे पर्यावरण कानून और ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन बताया गया है। एनजीटी ने माना कि लगातार तेज आवाज सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि यह लोगों की सेहत के लिए गंभीर समस्या है। इससे तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद में दिक्कत और ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है। अदालत ने कहा कि हर नागरिक को शांत और प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है।

तत्काल कार्रवाई के निर्देश

एनजीटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी सिस्टम जो बिना अनुमति या तय डेसिबल सीमा से ज्यादा आवाज कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद या नियंत्रित किया जाए। एनजीटी ने सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार हफ्ते में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा मृत व्यक्ति का फर्जी वारिस बनकर जमीन हडपने वाले आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोश्ठ मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 772/25 के सत्यापन पर ग्राम बैसला निवासी भगवान मीणा पिता भेरूलाल मीणा, ग्राम पंचायत बैंसला-सरपंच श्रीमती प्रेमलता अमर रावत, सचिव-आनंद सक्सेना, तत्कालीन तहसीलदार रामपुरा बालकृष्ण मकवाना एवं अन्य ने अनावेदक भगवान को मृतक केदार पिता धूरा के स्वामित्व की भूमि का भूमि स्वामी बनाने के उद्देश्य से भगवान पिता भेरुलाल मीणा को भूमि स्वामी मृतक केदार का पुत्र एवं एक मात्र वारिस बताकर, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने एवं वैध वारिसों को सदोष हानि पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी- भगवान मीणा पिता भेरूलाल मीणा निवासी बैंसला तहसील रामपुरा नीमच, श्रीमती प्रेमलता पति अमर रावत सरपंच बेंसला रामपुरा जिला नीमच, आनंद सक्सेना सचिव ग्राम पंचायत बैंसला तहसील रामपुरा जिला नीमच, अनुराग पाटीदार तत्कालीन पटवारी बेंसला तहसील रामपुरा नीमच निवासी ग्राम देवरी खवासा जिला नीमच, बी.के. मकवाना तत्कालीन तहसीलदार रामपुरा जिला नीमच एवं अन्य।

नीमच जिले के ग्राम बैसला में आरोपी भगवान पिता भेरूलाल मीणा ने बैसला स्थित कृषि भूमि में मृतक केदार मीणा के स्वामित्व की भूमि का भूमिस्वामी बनने के लिए तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बैसला आरोपी प्रेमलता अमर रावत, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत बैसला आरोपी आनंद सक्सेना से स्वयं के लिए केदार का वैध वारिस और पुत्र होने संबंधी असत्य वारिसान प्रमाण पत्र बनवा कर जारी करवाया। तत्पश्चात उक्त भूमि का फौती नामान्तरण अपने पक्ष में कराने के लिए न्यायालय तहसीलदार रामपुरा में आवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद तत्कालीन पटवारी बैसला आरोपी अनुराग पाटीदार से स्वयं के लिए केदार का वैध वारिस और पुत्र होने संबंधी असत्य वंशावली, पंचनामा एवं प्रतिवेदन तैयार करवाकर प्रकरण में प्रस्तुत करवाया। तत्कालीन तहसीलदार रामपुरा बालकृष्ण मकवाना ने मृतक केदार के वैध वारिसान के संबंध में जांच किए बगैर उक्त असत्य एवं कूटरचित प्रमाण पत्र, पंचनामा, वंशावली एवं प्रतिवेदन को आधार बनाकर अनावेदक भगवान के पक्ष में फौती नामान्तरण आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार उक्त आरोपीगण एवं अन्य ने आरोपी भगवान को मृतक केदार पिता धूरा के स्वामित्व की भूमि का भूमिस्वामी बनाकर उसे सदोष लाभ पहुंचाकर और वैध वारिसों को सदोष हानि कारित कर धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से आपराधिक षडयंत्र कर, षडयंत्र के अनुसरण में आरोपी भगवान को भूमिस्वामी मृतक केदार का वैध पुत्र एवं एकमात्र वारिस बताकर, तत्संबंधी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, कूटरचित दस्तावेजों को असली की तरह प्रयुक्त कर, मृतक केदार की भूमि पर आरोपी भगवान का नामान्तरण कर दिया और भू राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित कर दिया। उक्त सभी लोकसेवकों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग भी किया गया और आरोपी भगवान के द्वारा इसका दुष्प्रेरण किया गया। इस प्रकार उक्त आरोपीगण ने षडयंत्रपूर्वक आरोपी भगवान के पक्ष में फौती नामान्तरण आदेश पारित करवाकर आरोपी भगवान को उक्त कृषि भूमि में सहखातेदार बना दिया। उक्त फौती नामान्तरण के संबंध में आरोपीगण द्वारा किए गए कृत्य आपराधिक षडयंत्र, धोखाधडी, कूटरचना, पद का दुरूपयोग एवं दुष्प्रेरण के अन्तर्गत होकर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्र.नि.अ. 1988, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधि. 2018 की धाराओं 7(ग) एवं 12 के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराध होना प्रथमदृष्टया पाया जाने से उक्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है जिसमें त्वरित कार्यवाही संपादित की जावेगी।

प्लेऑफ के लिए अपनी संभावनाएं बनाये रखने उतरेगी पंजाब

लखनऊ । आईपीएल में शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने अंतिम लीग मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला करेगी। लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो गयी है और उसका लक्ष्य इस मैच को जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाना रहेगा। सुपरजायंटस इस सत्र में अभी अंतिम स्थान पर है और उसके केवल 8 अंक हैं। ऐमें उसका लक्ष्य इस मैच को जीतकर पंजाब के खेल को बिगाड़ना रहेगा। वहीं दूसरी ओर पंजाब किग्स टीम किस भी हाल में ये मैच बड़े अंतर से जीतकर प्लेऑफ के लिए अपनी संभावनाएं बनाये रखने उतरेगी । अभी पंजाब के अभी 13 अंक हैं और वह अगर ये मैच जीतती है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे। टीम के लिए हालांकि ये आसान नहीं होगा क्योंकि पिछले छह मैचों से मिली हार से उसका मनोबल कमजोर हुआ है। इसके अलावा टीम पर अतिरिक्त दबाव भी रहेगा। वहीं सुपर जायंट्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है ऐसे में वह निडर होकर आक्रामक अंदाज में उतरेगी जिसको देखते हुए पंजाब को सावधान रहना होगा।

पंजाब की बल्लेबाजी कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह पर आधारित रहेगी। वहीं गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह और लॉकी फर्ग्यूसन के पास रहेगी। दूसरी ओर सुपरजायंट की बल्लेबाजी मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस के अलावा कप्तान ऋषभ पंत पर आधारित रहेगी। गेंदबाजी की कमान प्रिंस यादव , शाहबाज अहमद के पास रहेगी

आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक दोनो ही टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 जबकि पंजाब किंग्स ने 4 मैच जीते हैं। ऐसे में दोनो ही टीमें जीत के लिए बराबर की दावेदार नजर आती हैं पर जिस प्रकार से सुपर जायंट्स ने हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को भी हराया था उससे प्रेरित होकर टीम का लक्ष्य इस प्रदर्शन को फिर दोहराना रहेगा। ऐसे में पंजाब को विशेष रुप से सतर्क रहना होगा।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं :

लखनऊ सुपर जाइंट्स - ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, मैथ्यू ब्रीट्ज़्के, हिम्मत सिंह, एडेन मार्कम, निकोलस पूरन, अर्शिन कुलकर्णी, मिचेल मार्श, शाहबाज़ अहमद, अवेश खान, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक प्रभु यादव, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नोर्किया, जोश इंग्लिस, मोहसिन खान, नमन तिवारी, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अर्जुन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी।

पंजाब किंग्स - श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवेन, विष्णु विनोद, नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन, मुशीर खान, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विजयकुमार विशाक, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, पाइला अविनाश, यश ठाकुर, हरनूर सिंह, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद।

शुभमन ने तीसरी बार आईपीएल में 600 से अधिक रनों के साथ बनाया रिकार्ड

अहमदाबाद। गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए शुभमन गिल ने आईपीएल के इस सत्र में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 600 से अधिक रन बनाये हैं। इस प्रकार वह तीन बार इस टूर्नामेंट में ये अहम उपलब्धि हासिल करने वाले कप्तानों की सूची में नंबर एक पर पहुंच गये हैं। शुभमन ने अपने करियर में तीसरी बार और कप्तान के रूप में दूसरी बार यह 600 से अधिक रन किसी एक सत्र में बनाये। इसी के साथ ही शुभमन आईपीएल इतिहास में चौथे ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने एक सत्र में 600 से ज्यादा रन बनाये हैं। इससे पहले विराट ने 2025 सत्र में 600 से अधिक रन बनाये थे। वहीं शुभमन ने करियर में तीसरी बार 600 से अधिक रन बनाये हैं। इससे पहले उन्होंने 2023 में 890 रन बनाए थे, जो एक सत्र में किसी खिलाड़ी द्वारा बनाये दूसरे सबसे ज्यादा रन है। इस शानदार उपलब्धि के साथ ही शुभमन कप्तान के रूप में एक से अधिक बार 600 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरीसबी) के विराट कोहली ने साल 2013 में एक बार उपलब्धि हासिल की थी। तब कोहली भी सबसे कम उम्र में एक से अधिक बार 600 से अधिक रन सीजन बनाने वाले खिलाड़ी थे। दिग्गज कोहली ने साल 2016 में अपने करियर में दूसरी बार 600 रन से अधिक बनाये थे। वहीं डेविड वॉर्नर एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार सत्र में कप्तान रहते हुए 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं।

गिरजा/ ईएमएस 22मई 2026

शिवरामकृष्णन ने बीसीसीआई पर लगाया गंभीर आरोप

मुम्बई । पूर्व स्पिनर एल. शिवरामकृष्णन ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) पर निशाना साधा है। शिवरामकृष्णन ने कहा है कि कुछ साल पहले अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार लिए वह घर लौटे थे पर कुछ ही समय के बाद उन्हें वापस लौटने को कहा गया था।

शिवरामकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि तब उनके पास बीसीसीआई के एक अधिकारी का फोन आया। अधिकारी ने उनसे पूछा, अब जब अंतिम संस्कार हो गया है तो क्या आप अगली उड़ान से मोहाली में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की कमेंट्री करने आ सकते हैं? शिवरामकृष्णन ने कहा कि इस कठिन समय में भी उन्होंने अपनरे काम को महत्व दिया और वह मैच के लिए वापस लौटे।

इस खिलाड़ी ने कहा कि इसके बाद भी उनको पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने एक और दुखद घटना का जिक्र किया और कहा कि पुणे में जब वह कमेंट्री कर रहे थे तो उनकी माँ का निधन हो गया था। इसके बाद भी वह काम पूरा होने पर ही घर गये थे। शिवरामकृष्णन का कहना है कि इन बलिदानों और समर्पण भाव के बाद भी उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया और कभी भी पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए।

गौरतब है कि इससे पहले शिवरामकृष्णन ने बीसीसीआई पर भेदभाव का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि उन्हें काले रंग के कारण भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। इसी कारण से उन्होंने परेशान होकर हाल में कमेंट्री कसे भी संन्यास ले लिया था।

शिवरामकृष्णन ने अपने करियर में साल 1983 से 1987 के बीच भारतीय टीम के लिए 9 टेस्ट और 16 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (वनडे) मैच खेले, जिसमें कुल 41 विकेट हासिल किए। बाद में वह दशक तक कमेंट्री करते रहे। शिवरामकृष्णन ने पहले भी कई बार कहा है कि उन्होंने अपने जीवन भर रंगभेद का सामना किया है और अब वे इसके आदी हो चुके हैं। उनका यह हालिया खुलासा भारतीय क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

आरसीए का सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ट्रॉयल 23 मई को होगा

दौसा । राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए दौसा जिले की लड़कियों के लिए चयन ट्रायल शनिवार, 23 मई को आयोजित किया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार भी इस ट्रॉयल के जरिये जिले की लड़कियों को टीम में आने आ अवसर मिलेगा।

दौसा जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृज किशोर उपाध्याय ने इसी को लेकर कहा कि आरसीए की राज्य स्तरीय सीनियर महिला प्रतियोगिता की शुरुआत 2 जून से होगी। इसी प्रतियोगिता में दौसा की ओर से एक मजबूत और प्रतिस्पर्धात्मक टीम उतारी जाएगी। इसके लिए राजेश पायलट राजकीय स्टेडियम में 23 मई को सुबह 8ः00 बजे से चयन प्रक्रिया शुरू होगी।

चयन ट्रायल में 15 वर्ष से अधिक उम्र की कोई भी महिला खिलाड़ी भाग ले सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र खिलाड़ी ही टीम का हिस्सा बनें, ट्रायल के समय सभी महिला खिलाड़ियों के मूल दस्तावेजों की सघन जांच की जाएगी। इसमें उम्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेज शामिल होंगे।खिलाड़ियों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आएं जिससे उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

सचिव उपाध्याय ने दौसा की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले वर्ष हमारी बेटियों ने पुरुष टीम के मुकाबले कहीं अधिक शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में दौसा का नाम रोशन किया था। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष भी हमारा लक्ष्य एक बेहद संतुलित और खिताब जीतने वाली टीम तैयार करने का है।

प्रिंस से बोले अर्शदीप अब मुझे नाम से बुलाओ

मुम्बई । आईपीएल के इस 19 वें सत्र में शानदार गेंदबाजी कर सभी का ध्यान खींचने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए शामिल किया गया है। ये पहली बार है जब प्रिंस भारतीय टीम से खेलते हुए दिखेंगे। इसी को देखते हुए उन्हें भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने मजेदार अंदाज में बधाई दी। प्रिंस अर्शदीप को भैया कहकर बुलाते हैं। इसी को देखते हुए अर्शदीप ने कहा है कि अब टीम में आ गया है इसीलिए नाम से बुला। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह मजेदार और सहज बातचीत दोनों खिलाड़ियों के बीच की अच्छी केमिस्ट्री और अर्शदीप के परिपक्व रवैये को दर्शाती है, जो एक जूनियर खिलाड़ी को बड़े सम्मान के साथ संबोधित करने के लिए कह रहे हैं।

नेमार फिर चोटिल हुए, विश्वकप में खेलने पर संशय छाया

यो डी जनेरियो । ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार एक बार फिर चोटिल हो गये हैं। ऐसे में अगले माह होने वाले फीफा विश्वकप में उनके खेलने को लेकर एक बार फिर संशय छा गया है। नेमार लंबे समय के बाद हाल ही में मैदान पर लौटे थे जिसके बाद उन्हें विश्वकप के लिए टीम में भी शामिल किया गया था पर अब उनके चोटिल होने से प्रशंसकों में निराशा का भाव है। इसका कारण है कि अब विश्वकप में एक माह से भी कम समय है। 34 साल के नेमार सैंटोस आजकर अपने क्लब की ओर से खेलकर फिटनेस हासिल करने में लगे थे पर सैन लोरेंजो के खिलाफ अपनी टीम के घरेलू कोपा सुदामेरिकाना मैच में वह नहीं उतरे। इसका कारण उनकी पिंडली में लगी चोट को बताया गया है हालांकि क्लब का कहना है कि उनकी चोट गंभीर नहीं है और चिंता की जरूरत नहीं है।

सैंटोस टीम के डॉक्टर रोड्रिगो ज़ोगैब ने उम्मीद जतायी है कि नेमार 27 मई को ब्राजील के विश्व कप से पहले होने वाले पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए फिट हो जायेंगे। जोगैब ने कहा, नेमार नेशनल टीम में पूरी तरह फिट या लगभग फिट होकर शामिल होंगे। इस बात की भी संभावना है कि वह अगले मंगलवार को डेपोर्टिवो कुएन्का के खिलाफ खेल सकते हैं। गौरतब है कि नेमार ब्राजील के लिए अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।

विनेश मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को लगायी फटकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को ट्रायल के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के फैसले को लेकर उसे कड़ी फटकार लगायी है। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह विनेश के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाकर उनका मूल्यांकन करे और आगामी एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करे। विनेश मैटरनिटी ब्रेक के बाद खेल में वापसी कर रही है। वहीं डब्ल्यूएफआई ने विनेश को ट्रायल के लिए आयोग्य घोषित करते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें उन पर नुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चार सवालों के जवाब मांगे थे। इसके साथ ही डब्ल्यूएफआई ने विनेश के किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में शामिल होने पर 26 जून, 2026 तक रोक लगा दी थी। डब्ल्यूएफआई के इस फैसले के कारण से विनेश नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं ले सकी थीं। विनेश ट्रायल की अनुमति मांगने के लिए डब्ल्यूएफआई के पास पहुंची थीं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। डब्ल्यूएफआई ने विनेश की नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के ट्रायल में शामिल होने की अपील यह कहकर ठुकरा दी थी कि उनके खिलाफ वाडा के 5.6.1 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। डब्ल्यूएफआई के अनुसार, इस नियम के मुताबिक संन्यास से वापसी कर रहे खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से पहले कम से कम छह महीने तक का नोटिस पूरा करना जरूरी होता है।इसके बाद विनेश ने कोर्ट में अपील की जिसमें कहा गया था कि एशियन गेम्स के लिए 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल में शामिल होने की उन्हें अनुमति दी जाये।

सीएसके के अंशुल कंबोज के नाम दर्ज हुआ सबसे अधिक छक्के खाने का अनचाहा रिकार्ड

अहमदाबाद । तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस 19 वें सत्र में शुरुआत से ही शानदार गेंदबाजी की पर अंतिम तीन मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण उनके नाम एक ऐसा अनचाहा रिकार्ड दर्ज हो गया है जिसे वह भूलना चाहेंगे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मैच में अंशुल की गेंदों पर चार छक्के लगे। इसी के साथ ही कंबोज के नाम एक आईपीएल सत्र में सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया।

इस सत्र में अंशुल ने सीएसके की ओर से कुल 14 लीग मैच खेले और हैरानी की बात है कि इन मैचों में उनपर कुल 34 छक्के लगे। इससे पहले, एक आईपीएल सत्र में सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड स्पिन राशिद खान के नाम था, जिनके खिलाफ आईपीएल 2025 में 33 छक्के लगे थे।

अंशुल ने हालांकि इस सत्र में अच्छी शुरुआत करते हुए विरोधी बल्लेबाजों को दबाव में बनाये रखा। इसी कारण वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भी शामिल रहे। सटीक यॉर्कर और विकेट लेने की क्षमता से वह सीएसके के मुख्य गेंदबाज बनकर उभरे हैं। उनकी खराब फॉर्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण सीएसके के 12वें लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ देखने को मिला था। उस मैच में लखनऊ के बल्लेबाजों ने अंशुल के खिलाफ आठ छक्के लगाए थे, जो एक आईपीएल मैच में किसी भी गेंदबाज द्वारा खाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है।

छक्कों के इस रिकॉर्ड के अलावा, अंशुल ने आईपीएल 2026 में कुल 530 रन भी दिये। इससे वह इस साल के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। हालांकि, यह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन लुटाने का ऑल-टाइम रिकॉर्ड नहीं है। वह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के नाम है, जिन्होंने आईपीएल 2024 के 16 मैचों में कुल 566 रन दिए थे। इस सूची में उनके बाद तुषार देशपांडे के नाम है। तुषार ने आईपीएल 2023 में 564 रन दिये जबकि राशिद खान ने 2023 में 552 रन दिये थे।

आईपीएल को और रोमांचक बनाने ये तीन बदलाव करें - चोपड़ा

मुम्बई। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आजकल बल्लेबाज हावी हो रहे हैं जिससे खेल का रोमांच घट रहा है जिससे बढ़ाने के लिए गेंद और बल्ले में संतुलन लाना होगा। इसके लिए कुछ बदलाव भी करने होंगे। चोपड़ा के अनुसार पिछले कुछ सत्र में ये देखा गया है कि सपाट पिचों और छोटी बाउंड्रियों के कारण बल्लेबाज वावी हो गये हैं जिससे मुकबले एकतरफा हो रहे हैं। ऐसे में खेल को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ऐसे बदलाव करने होंगे जिससे कि उसका रोमांच बढ़ सके।

इसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव गेंदबाजों को मजबूत करने से जुड़ा है। इसके तहत तीन विकेट पर एक अतिरिक्त ओवर मिलना चाहिये। चोपड़ा के अनुसार, यदि कोई गेंदबाज एक पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट ले लेता है, तो उसे अपनी चार ओवर की तय सीमा के अलावा एक पांचवां ओवर फेंकने का अवसर मिलना चाहिए। यह नियम गेंदबाजों को अधिक आक्रामक होने और विकेट लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे मैच में नया मोड़ आ सकता है और बल्लेबाजों को भी और सतर्क रहना होगा।

दूसरा सुझाव बड़ी जीत पर अतिरिक्त अंक प्रदान करने का है, जिसका उद्देश्य टीमों को केवल जीत दर्ज करने के बजाय प्रभावशाली तरीके से जीतने के लिए प्रेरित करना है। वर्तमान नियमों के तहत जीत पर दो अंक मिलते हैं। चोपड़ा ने सुझाया है कि यदि कोई टीम किसी लक्ष्य को 15-16 ओवर में ही हासिल कर लेती है, या बचाव करते हुए 40 से अधिक रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज करती है, तो उसे दो के बजाय तीन अंक दिए जाने चाहिए। यह बदलाव लीग चरण के दौरान टीमों के बीच एक अतिरिक्त अंक हासिल करने की होड़ बढ़ाएगा, जिससे हर मैच में अंतिम गेंद तक रोमांच बना रहेगा और टीमें सिर्फ नेट रन रेट पर ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी।

वहीं तीसरा और संभवतः सबसे अनोखा प्रस्ताव 100 मीटर से लंबे छक्के पर 8 रन का है। यह बात इससे पहले रोहित शर्मा भी कही थी। चोपड़ा का मानना है कि आईपीएल में ऐसे असाधारण मौके कम ही आते हैं जब कोई बल्लेबाज 100 मीटर से अधिक लंबा छक्का लगाता है। यदि कोई खिलाड़ी यह उपलब्धि हासिल करता है, तो उसे छह के बजाय आठ रन मिलने चाहिए। हालांकि चोपड़ा ने इसे विवादित बताया, उनका तर्क है कि इससे बल्लेबाज बड़े छक्के लगाने के प्रयास में अधिक जोखिम उठा सकते हैं, जिससे उनके आउट होने की संभावना बढ़ेगी और खेल में अप्रत्याशितता का तत्व जुड़ जाएगा। यह प्रशंसकों के लिए एक अतिरिक्त रोमांच होगा। यदि बीसीसीआई इन तीनों सुझावों को लागू करने पर विचार करती है, तो निश्चित रूप से इंडियन प्रीमियर लीग के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। ये नियम बदलाव न केवल खेल में संतुलन बहाल करेंगे, बल्कि इसे दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग के रूप में और अधिक मनोरंजक और प्रतिस्पर्धी भी बनाएंगे, जिससे हर मैच एक यादगार अनुभव बन सकेगा।

हार्दिक पांड्या को मुम्बई इंडियंस से रिलीज करने की मांग उठी

मुम्बई। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुम्बई इंडियंस का प्रदर्शन आईपीएल में लगातार तीसरे सत्र में भी बेहद खराब रहा है और टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पायी है। ऐसे में पांड्या को टीम से रिलीज करने की मांग एक बार फिर तेज हो गयी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने पहले ही सत्र में खिताब जीता था और दूसरे सत्र में वह उपविजेता रही थी। जिसके बाद वह मुम्बई आये थे और रोहित शर्मा की जगह पर उन्हें कप्तान बनाया गया लेकिन टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। टीम के प्रदर्शन के अलावा उनका स्वयं का प्रदर्शन भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। मुंबई इंडियंस पिछले तीन सत्र में केवल एक बार ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाई है, जबकि दो बार तालिका में सबसे नीचे रही है, जिसमें आईपीएल 2024 भी शामिल है। इसी वजह से अब पांड्या से सिर्फ कप्तानी छीनने की नहीं, बल्कि उन्हें टीम से ही रिलीज़ करने की मांग उठ रही है। इसी को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी अपनी राय रखते हुए एक बड़ा सुझाव दिया है। हार्दिक को लेकर वॉन ने कहा, रिलीज कर दो। हालांकि, उन्होंने तुरंत एक और विकल्प सुझाया। उन्होंने कहा, उसे कैमरून ग्रीन से रिप्लेस कर दो। वॉन का यह सुझाव कई क्रिकेट जानकारों को काफी पसंद आ रहा है। पांड्या और ग्रीन दोनों एक ही तरह के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ऐसे में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच एक ट्रेड डील की संभावना बन सकती है। इस संभावित अदला-बदली से दोनों ही टीमों को लाभ हो सकता है। इससे कोलकाता नाइट राइडर्स को हार्दिक पांड्या के रूप में एक नया और अनुभवी कप्तान मिल जाएगा, वहीं ग्रीन मुंबई इंडियंस के बॉलिंग और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट को मजबूती प्रदान करेंगे।

वॉन ने स्वीकार किया कि उन्हें गुजरात टाइटन्स में दो सफल सीज़न के बाद हार्दिक के मुंबई वापस आने के पीछे का तर्क कभी समझ नहीं आया। गुजरात टाइटन्स की कप्तानी करते हुए हार्दिक ने टीम को लगातार दो फाइनल तक पहुंचाया था और एक खिताब भी जीता था। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। मुझे सच में उसे वापस लाने का कारण समझ नहीं आया। वह गुजरात टाइटन्स के साथ अच्छा कर रहा था, वहां अलग खिलाड़ियों और अलग कोच के साथ उसने टाइटल जीता था। वहीं मुंबई के ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे लीडर-कप्तान या स्टार खिलाड़ी हैं। वॉन ने आगे कहा, अगर वह कप्तान बने रहना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वह नए कप्तानों के साथ रहें। शायद केकेआर को नया कप्तान चाहिए होगा। इसीलिए ग्रीन-हार्दिक की अदला-बदली संभव है।

विराट से टेस्ट प्रारुप में वापसी को लेकर बात कर रहे बचपन के कोच

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद से ही प्रशंसकों के अलावा पूर्व क्रिकेटरों ने भी मांग की है कि वह एक बार फिर खेल में वापसी करें। इन लोगों का मानना है कि भारतीय टेस्ट टीम को अभी विराट की जरुरत है और उनमें अभी काफी क्रिकेट भी बचा है। इसी को लेकर प्रशंसकों ने विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा से भी उन्हें वापसी के लिए मनाने को कहा था। इस मामले में अब कोच का बयान आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ने उनकी इस बारे में विराट से बात हुई है पर अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। विराट ने पिछले साल 12 मई 2025 को अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर प्रशंसकों को हैरान कर दिया था। भारत के लिए 123 टेस्ट मैचों में 9230 रन बनाकर, वह देश के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट बल्लेबाज के रूप में अपने करियर का समापन कर चुके थे। जून 2011 से जनवरी 2025 तक चले उनके लंबे करियर के बाद यह फैसला अप्रत्याशित था। उनके इस फैसले को एक साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमी लगातार उन्हें एक बार फिर भारतीय टीम के लिए टेस्ट प्रारूप में खेलते देखना चाहते हैं।

कोच ने बताया कि उन्होंने विराट से टेस्ट में वापसी को लेकर चर्चा की है। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या उन्होंने विराट से टेस्ट क्रिकेट में लौटने के लिए कहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, कई लोगों ने मुझसे कहा है कि विराट को टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए कहूं क्योंकि वह मेरी बात सुनता है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। विराट ने जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और 14 साल के करियर में उन्होंने 123 मैच खेले। वह अपने दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे और 2014 से 2022 तक 60 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी संभाली। विराट टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती, जो उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि, अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज (नवंबर 2024 से जनवरी 2025) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे। नौ पारियों में उन्होंने कुल 190 रन बनाए, जिसमें पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट की दूसरी पारी में बनाए गए 100 रन भी शामिल थे। अब देखना कि बचपन के कोच की पहले क्या रंग लाती है।

विंबलडन में नजर नहीं आयेंगे अल्काराज़, प्रशंसक निराश हुए

पेरिस। यहां अगले माह 29 जून से शुरु हो रहे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज़ खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अल्काराज़ ने कलाई की गंभीर चोट के कारण इस वर्ष के विंबलडन और क्वींस क्लब टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। इससे उनके प्रशंसकों में निराशा का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि अल्काराज़ जैसे स्टार खिलाड़ी के नहीं होने से टूर्नामेंट का आकर्षण घटेगा। कार्लोस अल्काराज़ को इस समय टेनिस के सबसे आक्रामक और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है पर उनकी यह चोट इस पूरे सीजन की तस्वीर को बदलने वाली साबित हुई है। इसी कारण उन्हें आधिकारिक तौर पर घोषणा करना पड़ी है कि वह आगामी विंबलडन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ज्ञात हो कि उन्हें पिछले महीने बार्सिलोना ओपन के दौरान दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी थी, जिसके बाद से वे कोर्ट से बाहर हैं। यह चोट अल्काराज़ को बार्सिलोना ओपन के शुरुआती मुकाबले में महसूस हुई थी। दर्द बढ़ने के कारण उन्हें दूसरे दौर का मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद, उन्होंने पूरे क्ले कोर्ट सत्र से भी दूरी बना ली थी, जिसमें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन भी शामिल था। उनकी अनुपस्थिति ने कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं को प्रभावित किया है।इस खिलाड़ी ने एक बयान में कहा कि उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है और वे अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रतिस्पर्धी मुकाबले खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। इसी वजह से उन्होंने क्वींस क्लब और विंबलडन से हटने का यह मुश्किल फैसला लिया है। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि ये दोनों प्रतियोगिताएं उनके लिए बेहद खास हैं और उन्हें इन्हें नहीं खेल पाने का गहरा दुख रहेगा।

गौरतलब है कि अल्काराज पिछले साल के फ्रेंच ओपन चैंपियन रहे थे, जहाँ उन्होंने फाइनल में इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर को हराया था।

बाबर और राऊफ की वापसी

लाहौर । शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलने उतरेगी। इस टीम में अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम घोषित की है। यह घरेलू सीरीज इसी माह के अंत में 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। इस टीम में ऑलराउंडर सलमान अली आगा को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गयी है।

वक्त संभलने का है, देश का युवा मौजूदा सिस्टम से खफा

कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़ते फॉलोअर्स पर थरुर की दो टूक

नई दिल्ली। देश की राजनीति में इन दिनों एक अजीब और अनोखे नाम ने सोशल मीडिया पर भारी हलचल मचा रखी है। यह नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। भले ही यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है और न ही इसके पास कोई चुनावी मशीनरी या जमीनी संगठन है, लेकिन डिजिटल दुनिया में इसका असर इतना व्यापक हो चुका है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में इसने कई स्थापित बड़े दलों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इस पूरे अनोखे और व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मूवमेंट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। थरूर ने स्पष्ट किया है कि इसे सिर्फ एक वायरल मजाक या इंटरनेट ट्रेंड मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह देश के युवाओं की व्यवस्था के प्रति गहरी नाराजगी और सिस्टम से बढ़ती दूरी का एक बड़ा और गंभीर संकेत है।

थरूर ने एक विशेष इंटरव्यू के दौरान युवाओं के इस गुस्से और निराशा के मुख्य कारणों को रेखांकित किया। उनके अनुसार, हाल ही में हुए नीट पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी, बेकाबू महंगाई और युवाओं के सामने अवसरों की भारी कमी ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। यही वजह है कि एक सोशल मीडिया आधारित व्यंग्यात्मक अभियान अचानक देश के करोड़ों युवाओं की आवाज बनकर उभर आया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जब लोगों को अपनी बात रखने के सही मंच नहीं मिलते, तो वे नए रास्ते तलाशते हैं और सीजेपी उसी संचित गुस्से का एक डिजिटल विस्फोट है। नीट पेपर लीक विवाद को उन्होंने युवाओं के धैर्य को तोड़ने वाला 'आखिरी झटका'बताया।

लाखों छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, उनके परिवार कर्ज के जाल में डूब जाते हैं और अंत में जब पूरी परीक्षा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाती है, तो यह छात्रों के लिए मानसिक रूप से बेहद विनाशकारी साबित होता है। इस अव्यवस्था के चलते कई छात्रों को मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लगे कुछ प्रतिबंधों को भी गलत ठहराया और कहा कि लोकतंत्र में असहमति, रचनात्मक आलोचना और व्यंग्य को पूरी जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं की यह निराशा केवल मौजूदा सरकार से नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे से है। हाल के क्षेत्रीय चुनावों का उदाहरण देते हुए उन्होंने इसे नई पीढ़ी यानी जेन-जी की जीत बताया, जो अब पारंपरिक राजनीति से हटकर नए विकल्प तलाश रही है। अंत में उन्होंने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों और विपक्ष को सलाह दी कि वे युवाओं की इस बेचैनी और उनकी भाषा को समझें, अन्यथा ऐसे डिजिटल मूवमेंट और मजबूत होंगे जो भविष्य में मतदान के रुख को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं।

जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री

नई दिल्ली। भारत की अध्यक्षता में 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली 'क्वाड' विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के शीर्ष राजनयिक शामिल होंगे। बैठक के दौरान सदस्य देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भाग लेने के जिएए विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। इस बैठक में मंत्री एक जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुई चर्चाओं को एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप आगे बढ़ाएंगे। वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। साथ ही क्वाड की चल रही पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। अपनी यात्रा में ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ-साथ अमेरिका के विदेश मंत्री के भी, विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह यात्रा क्वाड साझेदारों के बीच लगातार उच्च-स्तरीय जुड़ाव को दर्शाती है और एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए उनके साझा दृष्टिकोण को मजबूत करती है। क्वाड की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीतिक गतिशीलता लगातार बदल रही है और सदस्य देश साझा क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग और समन्वय को गहरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच, भारत की अपनी यात्रा से पहले रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन नई दिल्ली के साथ ऊर्जा संबंधों का विस्तार करना चाहता है और क्वाड के जरिए समन्वय को गहरा करना चाहता है, साथ ही उन्होंने होर्मुज से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच भारत को एक महान सहयोगी और महान साझेदार बताया है।

सपा सांसद इकरा हसन और सात अन्य पर नामजद एफआईआर दर्ज

सहारनपुर। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इकरा हसन के साथ 7 अन्य लोगों को भी नामजद किया है, जबकि 25 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सहारनपुर के डीआईजी ऑफिस के बाहर सड़क जाम करने और हंगामा करने के मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई है।

जानकारी के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई सिविल लाइन चौकी प्रभारी की शिकायत के आधार पर की गई है। आरोप है कि सांसद और उनके समर्थकों ने डीआईजी कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क को बाधित कर दिया था, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सड़क रोककर यातायात ठप करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर हंगामा करने के आरोप लगे हैं। सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें इकरा हसन पिछले दिनों एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए डीआईजी ऑफिस पहुंची थीं। उनका आरोप था कि पुलिस उनकी बात तो मान रही है, लेकिन पीड़िता की बात नहीं सुन रही। जिसके बाद उन्होंने डीआईजी ऑफिस के बहार अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई थीं। डीआईजी के आदेश पर पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर महिला थाने पहुंची थीं। हालांकि, 10 मिनट बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए फिर उन्होंने धरना दिया था।

रेगिस्तान में बनी झील में बिछाई प्लास्टिक शीट

जैसलमेर । राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान के बीच बनाई जा रही कृत्रिम झील इन दिनों चर्चा में है। करीब 242 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस झील में बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के लिए 300 माइक्रोन मोटी प्लास्टिक शीट बिछाई गई है। झील की लंबाई 28 किलोमीटर है और इसमें लगभग 76 लाख स्क्वेयर मीटर प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, ताकि रेतीली जमीन पानी को सोख न सके। प्लास्टिक शीट के ऊपर मिट्टी की परत भी डाली गई है, जिससे यह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। इस परियोजना से जैसलमेर और बाड़मेर के करीब 50 लाख लोगों को सालभर पानी उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है।

नीट पेपर की बिक्री सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, खरीदने वालों की सूची हो रही तैयार

नई दिल्ली। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि नीट का पेपर पांच राज्यों में बिका था। सबसे ज्यादा बिक्री महाराष्ट्र में हुई और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि अब तक गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ और डिजिटल गैजेट्स खंगालने के बाद यह जानकारी सामने आई है। सीबीआई का कहना है कि आगे और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक का मामला और बड़ा हो सकता है। इसी कारण एजेंसी अभी यह तय नहीं कर पा रही कि कितने छात्रों ने पेपर खरीदा था। जांच में सामने आया है कि कुछ परिजनों ने पेपर को आगे दूसरे लोगों को भी बेच दिया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई को महाराष्ट्र और राजस्थान में पेपर के प्रिंट निकालकर बेचने के सबूत मिले हैं। इसी वजह से अभी यह पता लगाना मुश्किल है कि पेपर कितने लोगों तक पहुंचा। जांच में अब तक सामने आया है कि पेपर लीक का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र था। यहीं से राजस्थान और दूसरे राज्यों के छात्रों तक 'क्वेश्चन बैंक' पहुंचा। अब सिर्फ पेपर लीक करने वाले बिचौलिए और मास्टरमाइंड ही नहीं, बल्कि भारी रकम देकर पेपर खरीदने वाले रसूखदार माता-पिता भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। जांच एजेंसी अब उन सभी अभिभावकों की सूची तैयार कर रही है, जिनके बैंक खातों से शिवराज मोटेगांवकर, पी वी कुलकर्णी या उनकी सहयोगी मनीषा वाघमारे के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने पेपर लीक करने और इसे बेचने वाले ज्यादातर बड़े चेहरों को बेनकाब कर दिया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अलावा बाहर के कुछ किरदार अभी भी शक के दायरे में हैं।

हल्द्वानी के चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी गिरफ्तार

देहरादून। हल्द्वानी के चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी को ऊधमसिंहनगर एसआईटी ने जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। करीब 20 लोगों से 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में आरोपित को काठगोदाम थाने में हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल के निर्देश पर गठित एसआईटी ने देर रात कार्रवाई कर आरोपित धनंजय को हिरासत में लिया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, धनंजय और उसके सहयोगियों ने लोगों को जमीन दिलाने, प्लॉट बेचने और निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए है।

प्री-प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूलों के लिए मान्यता अनिवार्य, बिना पंजीयन संचालन पर होगी कार्रवाई

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-11 तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति 2013 के प्रावधानों के तहत जिले में संचालित सभी निजी एवं शासकीय शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों, प्री-प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूलों को संचालन से पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती दीपमाला मंगोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना मान्यता अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद किसी भी शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र का संचालन करना दंडनीय माना जाएगा। विभाग द्वारा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी निजी एवं शासकीय प्री-प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल संचालकों को महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पेंशनर्स विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का आव्हान

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। सम्पूर्ण प्रदेश में पेंशनर्सों की बढ़ती समस्याओं, एवं सरकार की पेंशनर्स विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। संगठन के उप प्रांताध्यक्ष व जिला अध्यक्ष ए.एल. मोहारे ने बताया कि 10 जून को तहसील स्तर पर सभा कर रैली के माध्यम से प्रदर्शन कर एस डी एम को ज्ञापन सौंपा जायेगा।तो वही 26 जून को जिला स्तर पर सभा कर, रैली के माध्यम से प्रदर्शन कर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जायेगा।जिसके

अगले चरण में 10 जुलाई को सभी जिले व तहसील शाखाओं के साथ भोपाल मे प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जायेगा। श्री मोहारे ने सभी पेंशनर्सों से आव्हान किया है कि सरकार की पेंशनर्स विरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अभी से मानसिकता बनायें अधिक से अधिक पेंशनर्सों साथियों से मुलाकात कर उन्हें आंदोलन की जानकारी दे और संगठन की पहल पर पेंशनर्स का सम्मान, हमारा अभिमान और एकता हमारी , जीत हमारी का मंत्र लेकर अधिक से अधिक पेंशनर्सों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास करें।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पेंशनर्सो से स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 4 प्रतिशत मासिक अंशदान राशि लेना व कार्यरत कर्मचारियों से मात्र 1 प्रतिशत राशि लेना, पेंशनर्सों के प्रति न्याय संगत नहीं है। धारा 49(6) को विलोपित कर केन्द्र के समान देय तिथि से ही मंहगाई राहत प्रदान कि जानी चाहिए। छठवें वेतनमान का 32माह का एरियर्स और सातवें वेतन मान का 27 माह का एरियर्स हाईकोर्ट के निर्णय व आदेश के परिपेक्ष्य में देने पर भी आनाकानी की जा रही है । 25 वर्षों की सेवा उपरांत चतुर्थ वेतनमान की अवधि 01 जुलाई 2023 से प्रदाय कर पूर्व के सेवानिवृत्त साथियों को वंचित किया जा रहा है। 65 वर्ष की आयु पर 5प्रतिशत,70वर्ष की आयु में 10 प्रतिशत , 75 वर्ष की आयु में 15प्रतिशत तथा 80 वर्ष की आयु में 20प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई राहत देने जैसे अनेक मांगों पर सरकार निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रही है। इसलिए प्रदेश के सभी पेंशनर्स एकजूट होकर आंदोलन का शंखनाद करेंगे। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने इस आंदोलन में आहुति देने का आग्रह किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव पर आरोप तय करने का फैसला टला

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला 9 जून तक टाल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे हाई-प्रोफाइल मामले में फैसला सुनाने की अगली तारीख तय की है। ईडी का मामला कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले से अर्जित अपराध की आय के धन शोधन से जुड़ा है, जिसका मूल मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज किया था। आरोप है कि लालू ने 2004 से 2009 के बीच केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी होटलों के संचालन के ठेके देने में अनियमितताएं की थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, होटल के रखरखाव के ठेका निर्धारित नियमों की अनदेखी कर एक निजी कंपनी को दिए गए थे, जो कथित तौर पर लालू यादव के करीबी सहयोगियों से जुड़ी थी। इसके बदले में, करीब तीन एकड़ की एक कीमती जमीन एक बेनामी कंपनी के माध्यम से हासिल की गई, जिसका संबंध लालू यादव के परिवार और उनके सहयोगियों से बताया गया है। मामले के आरोपियों में लालू, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव सहित कई अन्य लोग शामिल हैं। इससे पहले, आरोपियों के वकीलों और ईडी की ओर से विस्तृत दलीलें पेश करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि इस घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में भी लंबित हैं। इन याचिकाओं में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। पिछले साल अक्टूबर में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप तय किए थे। लालू यादव लगातार आरोपों से इनकार करते रहे हैं और उनका दावा है कि आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना ने 22 मई को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभिन्न राजस्व कार्यों एवं लंबित प्रकरणों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को समयसीमा के भीतर प्रकरणों के निराकरण तथा राजस्व कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, श्री एम.आर. कोल, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव, एसडीएम बालाघाट गोपाल सोनी उपस्थित रहे। जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने फार्मर रजिस्ट्री कार्यों की समीक्षा की। कुछ तहसीलों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष शिविर आयोजित कर शेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री शीघ्र पूर्ण कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्री से वंचित नहीं रहना चाहिए। नक्शा तरमीम कार्य की समीक्षा के दौरान लालबर्रा एवं कटंगी तहसीलों की प्रगति धीमी पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों का अद्यतन एवं शुद्ध होना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा प्रकरणों तथा विभिन्न राजस्व मदों की वसूली की भी गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री मीना ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरण अनिवार्य रूप से आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज किए जाएं तथा अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान परसवाड़ा तहसील में लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों से कहा कि लंबी अवधि से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले वेंडर को सीमा पार से धमकी

झारग्राम। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार विक्रम साव को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जान से मारने की धमकियां मिली हैं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की नई सरकार बनने के बाद विक्रम को फोन कॉल के जरिए यह धमकियां दी गई हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब 19 अप्रैल को झारग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विक्रम साव की दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाई थी। इस दौरान दोनों के बीच हुई संक्षिप्त और मजेदार बातचीत का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने विक्रम से झालमुड़ी लेने के बाद उन्हें 10 रुपये का नोट भी दिया था, जिसे विक्रम ने हमेशा संभालकर रखने की बात कही थी।

खराब थी दाईं किडनी, निकाल दी बाईं, मौत

-दो करोड़ का हर्जाना भरेंगे डॉक्टर

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला की दाईं किडनी खराब थी, लेकिन लापरवाह डॉक्टर ने बाईं किडनी निकाल दी, जिसके कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस घोर लापरवाही पर अब डॉक्टर को दो करोड़ का हर्जाना भरना पड़ेगा। यह पूरा मामला साल 2012 का है, जब शांति देवी नामक महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर राजीव लोचन के पास पहुंची थीं। जांच रिपोर्ट में साफ था कि महिला की दाहिनी किडनी खराब हो चुकी है और बाईं किडनी पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टरों ने खराब दाहिनी किडनी को निकालने के लिए 6 मई 2012 को महिला का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के कुछ हफ्तों बाद भी जब महिला की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो परिवार ने जून 2012 में दोबारा सीटी स्कैन और रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराया। इस जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की खराब दाहिनी किडनी शरीर में ही मौजूद थी, जबकि डॉक्टरों ने उसकी स्वस्थ बाईं किडनी को बाहर निकाल दिया था। इस गलत ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। उन्हें दो साल तक डायलिसिस पर रहना पड़ा और आखिरकार 20 फरवरी 2014 को उनकी मौत हो गई। घटना के करीब 14 साल बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने इसे चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी विफलता मानते हुए दोषी डॉक्टर को पीड़ित परिवार को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है।

नीट-यूजी का पेपर लीक नहीं हुआ था, सिस्टम कम्प्रोमाइज हुआ था- एनटीए

नई दिल्ली,। नीट-यूजी के पेपर लीक मामले में गुरुवार को हुई संसदीय समिति के सामने पेश हुए एनटीए के शीर्ष अधिकारियों ने दावा किया है कि नीट-यूजी का पेपर लीक नहीं हुआ था बल्कि सिस्टम कम्प्रोमाइज हुआ था। वहीं पेपर लीक के मुद्दे पर बैठक में हंगामा भी हुआ, क्योंकि समिति के अध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जहां इसे पेपर लीक बता रहे थे, वहीं समिति की बैठक में मौजूद बीजेपी सांसदों ने उन्हें इस मुद्दे पर घेरा और कहा कि सीबीआई जांच पूरी हुए बगैर कैसे कह सकते है कि पेपर लीक हुआ था।

शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सामने पेश हुए एनटीए के शीर्ष अधिकारियों ने पेपर लीक से जुड़े सवालों पर कहा कि नीट-यूजी का पेपर लीक नहीं हुआ था बल्कि कम्प्रोमाइज हुआ था। एनटीए अधिकारियों ने दावा किया कि नीट-यूजी के अंतिम प्रश्न पत्र को मराठी भाषा में अनुवाद करने के लिए जिन शिक्षकों को दिया था, उन्होंने ही प्रश्नों को रट लिया और बाद में उन सवालों को कागज में उतार कर गेस पेपर के रूप में छात्रों को मुहैया कराया था।

इस दौरान समिति में शामिल सदस्यों ने इस पर सवाल भी उठाए। साथ ही कहा कि जब हूबहू प्रश्नपत्र गेस पेपर के जरिए बाहर आए तो इसे लीक ही माना जाएगा। इस दौरान समिति के सदस्यों ने एनटीए के महानिदेशक से प्रश्न पत्र को तैयार करने से जुड़े कई सवाल भी किए, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और केवल यह कहा कि इसकी सीबीआई जांच चल रही है। सूत्रों की मानें तो बैठक शुरू होने से पहले ही बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह पर एजेंडा लीक करने का आरोप लगाया। बैठक में हंगामे के बीच दिग्विजय सिंह ने कहा कि पेपर लीक को लीक न बोला जाए, तो क्या कहा जाए। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब तक सीबीआई की रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए।

बैठक में हंगामे के बीच एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने नीट पेपर लीक नहीं हुए थे बल्कि कुछ लोगों ने प्रश्न ही याद कर लिए थे। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक नहीं हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने परीक्षाओं से जुड़े प्रोटोकाल की जानकारी भी दी। साथ ही बताया कि राधाकृष्णन समिति की करीब 70 फीसदी सिफारिशों को वह अमल में ला चुके हैं। बैठक में एनटीए को सुझाव भी दिया गया कि प्रश्न पत्र के दस सेट बनवाए जाएं और उन्हें मिक्स करके अलग-अलग राज्यों में भेजा जाए।

पद्मेश न्यूज़
शहर | समाज | गांव
बालाघाट एक्सप्रेस
/padmeshmedia /padmeshmedia
epaper.balaghatexpress.in
E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

मलाजखंड में दर्दनाक सड़क हादसा पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल-कोचिंग संचालक की मौत

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मलाजखंड थाना अंतर्गत ग्राम टिंगीपुर से देवरी के बीच हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जहां मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 52 वर्षीय बिसराम पिता साधुराम शांडिल्य निवासी टिंगीपुर की बिरसा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मलाजखंड पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिसराम शांडिल्य मलाजखंड क्षेत्र के आसपास के गांवों में छात्रों को कोचिंग पढ़ाने का कार्य करते थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। दोनों बच्चे वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके बड़े भाई विपिन बिहारी शांडिल्य प्रेम नगर बालाघाट में रहते हैं और वे पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं बताया गया है कि 21 मई की रात करीब 10 बजे बिसराम शांडिल्य किसी आवश्यक कार्य से अपनी मोटरसाइकिल से टिंगीपुर से देवरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान टिंगीपुर से कुछ दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिसराम शांडिल्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही उनके परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल इलाज के लिए बिरसा अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया घटना के बाद मृतक बिसराम शांडिल्य का शव बिरसा अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवाया गया था। 22 मई को मलाजखंड पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही पूरी कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया पुलिस ने मामले में धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

यात्री वाहनों पर परिवहन और यातायात विभाग की बड़ी कार्रवाई, 40 वाहनों के काटे चालान

ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस-परमिट और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती, दो बसें परिवहन विभाग में खड़ी कराई गई

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

जिला परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यात्री वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीते एक-दो दिनों से जिले की अलग-अलग सड़कों पर संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अभियान के तहत यात्री बसों, ओवरलोडिंग कर रही पिकअप वाहनों और अन्य व्यावसायिक वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में 22 मई को यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने जिलेभर में लगभग 35 से 40 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी यात्री बसें पकड़ी गईं, जो ओवरलोडिंग कर संचालित हो रही थीं। इसके अलावा कई बसें बिना वैध पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस और परमिट के सड़कों पर दौड़ती मिलीं। कार्रवाई के दौरान एक अहम बात यह भी सामने आई कि कुछ बसों पर एक दिन पहले ही नियम उल्लंघन को लेकर चालान काटा गया था, लेकिन संचालकों द्वारा आवश्यक सुधार किए बिना दोबारा उन्हीं वाहनों को सड़कों पर उतार दिया गया। ऐसे वाहनों पर दोबारा सख्त कार्रवाई की गई। बताया गया कि जिन वाहनों को 24 घंटे की अवधि में दस्तावेज सुधारने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, उनमें कई वाहन निर्धारित समय समाप्त होने के कुछ मिनट बाद भी बिना सुधार के चलते पाए गए। कुछ मामलों में 5 से 10 मिनट अधिक होने पर भी नियमों का पालन नहीं मिलने के कारण यातायात पुलिस ने पुनः चालानी कार्रवाई की।

जिले में इन दिनों यातायात पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर शहर से लेकर प्रमुख मार्गों तक लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर हेलमेट जांच अभियान फिर तेज हो गया है, जहां बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी दोपहिया वाहन चालकों की जांच कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक-दो दिनों से शहर में यह सख्ती स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट नियम केवल चालान वसूली के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है। इधर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यात्री बसों के खिलाफ भी विशेष जांच अभियान चलाया गया। 22 मई की शाम शहर के संविधान चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर यात्री बसों की जांच की गई। इस दौरान अधिकारियों ने बसों के दस्तावेज, फिटनेस, परमिट, सुरक्षा उपकरण और अन्य आवश्यक नियमों की जांच की। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केवल 22 मई को ही संयुक्त कार्रवाई के दौरान लगभग 30 से 40 यात्री बसों पर कार्रवाई की गई। जांच में कई बसें ऐसी मिलीं जिनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था या परमिट संबंधी कमियां थीं। कुछ बसों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था भी नहीं पाई गई। इसके अलावा चालकों की निर्धारित ड्रेस, दस्तावेज और अन्य आवश्यक नियमों के पालन में भी लापरवाही सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाली दो बसों को परिवहन विभाग परिसर में खड़ा कराया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई बसों का एक दिन पहले ही चालान काटा गया था और उन्हें 24 घंटे का समय कमियां सुधारने के लिए दिया गया था। इसके बावजूद संबंधित बस संचालक और चालक बिना आवश्यक सुधार किए दोबारा यात्रियों को लेकर सड़कों पर दौड़ते पाए गए। जांच के दौरान कई बस चालकों ने पुलिस को एक दिन पहले काटे गए चालान दिखाकर यह तर्क दिया कि उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने समयावधि पूरी होने के बाद कार्रवाई जारी रखी। बताया गया कि कुछ मामलों में 24 घंटे की अवधि समाप्त होने के पांच से दस मिनट बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते दोबारा चालानी कार्रवाई की गई और बस संचालकों को तत्काल कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस ने शहर की सड़कों पर दौड़ रहे कुछ ओवरलोड पिकअप वाहनों पर भी कार्रवाई की। ऐसे वाहनों को रोककर चालान बनाए गए और वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई। यातायात थाना प्रभारी वीना राहांगडाले ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यात्री बस संचालकों से अपील की कि वे निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाएं और अपने वाहनों में सभी आवश्यक सुरक्षा और दस्तावेजी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मोबाइल हैक कर रिश्तेदारों से मांगने लगे पैसे, साइबर ठगों ने व्हाट्सएप से भेजे मैसेज

अर्जेंट 48 हजार रुपए भेज दो, लिखकर 200 से ज्यादा लोगों को भेजे संदेश, समय रहते खुलासा होने से बची बड़ी ठगी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों के बीच अब मोबाइल हैकिंग का एक नया मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम भमोड़ी में साइबर ठगों ने एक युवक का मोबाइल और व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। घटना के सामने आने के बाद लोगों में साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार युवक का मोबाइल अचानक हैक हो गया और कुछ ही देर में उसका व्हाट्सएप अकाउंट मोबाइल से गायब हो गया। इसके बाद मोबाइल का नियंत्रण साइबर ठगों के हाथ में चला गया। साइबर अपराधियों ने युवक के व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए उसके संपर्क सूची में मौजूद लोगों को पैसों की मांग वाले संदेश भेजने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि युवक के नंबर से करीब 200 से अधिक लोगों को मैसेज भेजे गए। संदेश में लिखा गया था कि मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है, शाम तक लौटा दूंगा, 48 हजार रुपए भेज दो। चूंकि यह संदेश युवक के निजी व्हाट्सएप नंबर से भेजे जा रहे थे, इसलिए कई लोगों को शुरुआत में यह वास्तविक लगे। कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने युवक को फोन कर पैसों की जरूरत के बारे में पूछताछ की, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवक ने बताया कि कुछ समय के लिए उसके मोबाइल का पूरा कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में चला गया था और उसके अकाउंट से लगातार संदेश भेजे जा रहे थे। इस दौरान उसे डर सताने लगा था कि कहीं साइबर अपराधी उसके बैंक खाते या मोबाइल में मौजूद अन्य निजी जानकारी तक पहुंचकर आर्थिक नुकसान न पहुंचा दें। हालांकि समय रहते युवक को मोबाइल हैक होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद उसने तुरंत अपने परिचितों को सतर्क करना शुरू किया और पूरे मामले की शिकायत भी की। इसी वजह से वह बड़ी साइबर ठगी का शिकार होने से बच गया। युवक का कहना है कि यदि कुछ और देर तक यह जानकारी नहीं मिलती तो संभव था कि उसके कई परिचित ठगों के झांसे में आकर पैसे ट्रांसफर कर देते। इस प्रकार के मामलों में साइबर अपराधी किसी लिंक, ओटीपी , तकनीकी कमजोरी के जरिए मोबाइल , व्हाट्सएप अकाउंट को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इसके बाद ये पीड़ित के संपर्कों को भावनात्मक , आपातकालीन संदेश भेजकर पैसे मांगते हैं। चूंकि संदेश परिचित व्यक्ति के नंबर से आते हैं, इसलिए लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। पुलिस और साइबर विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से अचानक पैसे मांगने वाला संदेश मिलने पर पहले सीधे फोन कर पुष्टि अवश्य करें। इसके अलावा किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी साझा न करें और संदिग्ध एप डाउनलोड करने से बचें। जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस भी लोगों को जागरूक रहने की सलाह दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल युग में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी आर्थिक ठगी का कारण बन सकती है।

पैसा ठीक होने के बाद देना
शादी से पहले एवं शादी के बाद
उम्र की अधिकता से कमजोर सेक्स, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, लिंग का छोटापन, टेडापन, निःसंतान, शुक्राणुओं की कमी, शुगर से आयी कमजोरी आदि सभी सेक्स समस्याओं का शर्तिया ईलाज किया जाता है।
पता-जगजीवन आयुर्वेदिक दवाखाना
गुरूनानक पेट्रोल पंप के सामने समाजवादी रोड, बालाघाट, मो. 9243880464

AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं RGPV & DTE भोपाल से सम्बध्द
सतपुड़ा कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग एण्ड पॉलिटेक्निक
बी.टेक. पॉलिटेक्निक
JOB SAHi
• कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
• माईनिंग इंजीनियरिंग
• सिविल इंजीनियरिंग
• मैकेनिकल इंजीनियरिंग
• इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
ADMISSION OPEN
नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों का Lateral Entry द्वारा बी.टेक. के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश
सतपुड़ा कैम्पस, लालबर्रा रोड, गर्रा-बालाघाट
6262604111, 9425836824 www.satpudaengineeringcollege.com

बार में मुनाफे के लिए नियम तोड़ा कर्मचारी शराब की पेटी सहित गिरफ्तार

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में बार संचालकों को शराब खरीदने के लिए दुकानें तय हैं। लेकिन ज्यादा मुनाफे के चक्कर में नियम तोड़े जा रहे हैं।

ऐसे ही एक मामले में कोतवाली पुलिस ने वैनगंगा क्लब में संचालित बार के कर्मचारी को अंग्रेजी शराब की एक पेटी के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वैनगंगा क्लब के बार में काम करने वाले 59 वर्षीय लालचंद पिता ज्ञानीराम भगत ग्राम गर्रा निवासी को पुलिस ने वार्ड क्रमांक 24 शिव मंदिर के पास से पकड़ा। उसके पास से आरएस ब्रांड की 12 बोतलों से भरी एक पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। नियमानुसार वैनगंगा क्लब बार को बस स्टैंड स्थित शराब दुकान से ही शराब खरीदनी थी। अप्रैल में नए ठेके होने के बाद अलग-अलग समूहों को ठेके मिले हैं। कम दाम में शराब मिलने के लालच में कर्मचारी तय दुकान छोड़कर दूसरी दुकान से शराब खरीद रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

स्वत्त्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट